R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 I अंक : 13

01 से 15 अप्रैल 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

माननीयों को पेंशन क्यों?

राष्ट्रपति के वेतन से भी अधिक...
पेंशन पा रहे कई विधायक

चपरासी से जज तक को सिर्फ एक,
नेताओं को कई पेंशन क्यों?

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

पुस्तकायन

8 | दो आईएएस की किताबें चर्चा में

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो किताबें चर्चा में हैं। इनमें से एक किताब है 2009 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण पिथोड़े और दूसरे हैं इसी बैच के आईएएस अभिषेक सिंह। पिथोड़े की पुस्तक द बैटल अगेंस्ट...

राजपथ

10-11 | विकास और वोट का रोडमैप तैयार

भोपाल से सवा दो सौ किलोमीटर दूर पचमढ़ी के जंगल में दो दिनों में करीब 21 घंटे की मैराथन चिंतन बैठक का निचोड़ यह निकला कि सरकार को अपनी तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच...

राजतंत्र

15 | सीपीए बन गया इतिहास

करीब 62 साल पहले 1 जून 1960 को गठित सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन 1 अप्रैल से इतिहास बन जाएगा। राजधानी भोपाल के विकास में इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शहर की कई योजनाओं को इस विभाग ने सजाया...

अपराध

18 | साइबर ठगी बनी नासूर

मप्र में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों से महिला अपराध को लेकर कई चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। विधानसभा में पेश जवाब में सरकार ने कहा है कि 2018 से अब तक 55 करोड़ 48 लाख 93 हजार से ज्यादा राशि का आर्थिक अपराध साइबर क्राइम...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता है। लेकिन आज भारत में राजनीति लाभ का धंधा बन गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनता की सेवा करने वाले माननीय राष्ट्रपति के वेतन से भी अधिक पेंशन पा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक दिन का विधायक या सांसद बनने के बाद भी माननीय पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जबकि यही हक एक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को 33 साल की सेवा के बाद मिलता है।

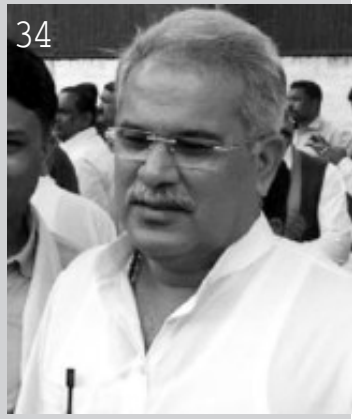

राजनीति

30-31 | दिशाहीन विपक्ष

एक वक्त देश की राजनीति में मंडल की काट के रूप में कमंडल आया। इस दौरान देश के दो सबसे बड़े राज्यों उप्र और बिहार में एक ओर लालू-मुलायम तो दूसरी ओर कांशीराम एवं भाकपा माले जैसे ध्रुव उभरे। इनमें पहली जोड़ी ने कहा कि उनका उभार सामाजिक न्याय की ताकत के रूप में...

महाराष्ट्र

36 | अपनी-अपनी जमावट

5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नेताओं की सक्रियता और मेल-मिलाप चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे यह संकेत भी मिल रहे हैं कि महाविकास आघाडी सरकार में सबकुछ ठीक नहीं है। जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे...

बिहार

38 | भाजपा की ख्वाहिश अब तक अधूरी

बिहार ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। ब्रिटिश राज में बंगाल के विभाजन के बाद बिहार को अलग प्रांत के तौर पर अधिसूचित किया गया था। अलग प्रशासनिक इकाई के तौर पर बिहार की राजनीति का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

तर्क-कुतर्क में खो रही राजनीति की भाषा-मर्यादा

शायर मिर्जा गालिब का एक शेर है

ये संगदिलों की दुनिया है, संभल कर चलना गालिब
यहां पलकों पर बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए...

महान शायर का यह शेर इन दिनों देश-प्रदेश की राजनीति पर सटीक बैठता है। दरअसल, तर्क-कुतर्क में इन दिनों राजनीति की भाषा और मर्यादा खो रही है। इससे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति को कलंक की तरह देखा जाने लगा है। गौरतलब है कि राज करने अथवा राज चलाने संबंधी नीति को ही राजनीति कहा जाता है। लिहाजा स्पष्ट है कि राज करने या चलाने जैसी अति संवेदनशील एवं गंभीर जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए इस पेशे में शामिल व्यक्ति को अत्याधिक योग्य, दक्ष, ईमानदार तथा कुशल नेतृत्व प्रदान कर पाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में चर्चा में बने रहने के लिए हमारे राजनेताओं की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। बड़ी पार्टियों के प्रमुख नेता जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। भाषा लगातार गिरते राजनीतिक स्तर को मापने का एक पैमाना है। इसमें नेता का स्तर रिफ्लेक्ट होता है। अगर राजनीतिक दल के नेता ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि भाषा की मर्यादा आपको बनाती है और अमर्यादा गिराती ही है। व्यक्तिगत हमलों से समर्थक भले ही ताली बजाते हों पर वह मतदाता जो अपनी सोच रखता है, तटस्थ है, वह उस नेता की मन में एक तस्वीर बनाता है जो लाख अच्छी बातें कहने से भी नहीं हटती। राजनीति में भाषा के गिरते स्तर से ही सवाल पूछने की गुंजाइश खत्म हो गई, क्योंकि नेता यह मान बैठे हैं कि वे जो कह रहे हैं, वही ईश्वरीय सत्य है। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी की भाषण शैली लोगों के मस्तिष्क में है। वे भी दहाड़ते और गरजते थे पर उसमें संयम नजर आता था। हमारे देश का सौभाग्य है कि प्राचीनकाल से ही भारत को राजनीति के क्षेत्र में ऐसी तमाम योग्य एवं विलक्षण प्रतिभाएं मिलीं जिन्होंने अपने तमाम राजनीतिक फैसलों के द्वारा देश को आगे ले जाने, देशवासियों को न्याय देने, तथा देश की प्रगति और विकास में अपनी योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का भरपूर इस्तेमाल किया। यदि हम आज के समय में पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण विश्व के बिगड़ते हुए हालात पर नजर डालें तथा प्रभावित देशों में मच रही तबाही, बर्बादी एवं आए दिन होने वाले कत्ल-ए-आम पर गौर करें तो हमें अपने देश के कुशल राजनीतिज्ञों की योग्यता पर यह सोचकर और भी गर्व होता है कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद भी बिना किसी भीषण संघर्ष किए देश को अंग्रजों की गुलामी की बेड़ियों से किस प्रकार मुक्ति दिलाई। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति में नैतिकता की न सिर्फ कमी होती दिखाई पड़ रही है बल्कि ऐसा लगने लगा है कि राजनीति जैसे पवित्र पेशे के लिए नैतिकता की बात करना ही कोई अनैतिक वार्तालाप बनकर रह गया हो। राजनीति में सक्रिय लोगों तमाम नेताओं पर हम नजर डालें तो हमें यह देखकर दुख होगा कि इनमें अनेक ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अशिक्षित होने के अलावा अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में असफल होने के बाद सफेद कुर्ते-पायजामे सिलवाकर समाज सेवा को बहाना बनाकर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। दूसरी तरफ ऐसे अपरिपक्व एवं असामाजिक लोगों के राजनीति में बढ़ते प्रवेश को देखकर योग्य, ईमानदार तथा देश सेवा का जज्बा रखने वाले उन तमाम लोगों ने अपने आपको राजनीति के क्षेत्र से दूर रखना शुरू कर दिया जो असामाजिक तत्वों की राजनीति में घुसपैठ को कतई उचित नहीं समझते थे।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 13, पृष्ठ-48, 1 से 15 अप्रैल, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बजट से होगा फायदा

मुख्यमंत्री प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं और वे नई-नई योजनाओं से प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मप्र सरकार ने बजट तो पेश कर दिया है। अब देखना यह है कि इस बजट से बेरोजगार युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं को क्या फायदा पहुंचता है।

● **चंदन सोनी,** ब्यावरा (म.प्र.)

एकजुट हो कांग्रेस

मप्र कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के गुट अलग-अलग हैं, जिसकी वजह एक कांग्रेस अलग-अलग हिस्सों में बंट गई है। यदि कांग्रेस को मजबूत बने रहता है तो उसे सबको एकजुट करके चलना होगा। आलाकमान को इस ओर ध्यान देना होगा।

● **विमलेश साहू,** इंदौर (म.प्र.)

मेट्रो के काम में गति

प्रदेश के दो बड़े शहरों राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल में मेट्रो संचालन को लेकर साल 2024 तक की समयसीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन कोरोनाकाल की वजह से काम काफी पिछड़ गया था, लेकिन अब इसने गति पकड़ ली है।

● **मुकेश गुप्ता,** भोपाल (म.प्र.)

भाजपा नई रणनीति की ओर

हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से भाजपा तो खुश है ही साथ ही साथ उसने इस वर्ष के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। उप्र सहित 4 राज्यों में भाजपा ही चुनकर आई है। इससे कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ गया है। उप्र में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे उपयोगी मुद्दा साबित हुआ अपराध मुक्त उप्र का। वहीं अन्य राज्यों में भी मोदी मैजिक कायम रहा। उप्र चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मप्र में भी चुनाव के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। भाजपा संगठन लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहा है। ताकि वह कहीं भी कमजोर न दिखे।

● **रूचि श्रीवास्तव,** ग्वालियर (म.प्र.)

बाघों की सुरक्षा मजबूत हो

प्रदेश में लगभग हर माह बाघ की मौत आम बात होती जा रही है। कभी आपसी संघर्ष, कभी शिकार तो कभी दुर्घटना में बाघों की मौत हो रही है। वह भी उस स्थिति में जब सरकार बाघों के संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आलम यह है कि बाघों का घर कहे जाने वाले मप्र में बीते एक दशक में 254 से ज्यादा बाघों की अलग-अलग कारणों से मौत हो चुकी है। प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़ें चौंकाने वाले हैं। प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे बाघों की सुरक्षा और तगड़ी हो।

● **विमल त्रिपाठी,** पन्ना (म.प्र.)

नल-जल योजना फलीभूत

मप्र में 4 हजार से अधिक ग्रामों में नल से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था फलीभूत हुई है। इन ग्रामों में अब नल के माध्यम से पेयजल मिल रहा है। इनमें 46 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार यह सुविधा पाकर हर्षित हैं। ग्रामीण माताएं और बहनें जिन पर घर में पीने का पानी लेकर आने का दारोमदार होता है, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल जल जीवन मिशन से रंग ला रही है।

● **प्रवेश नारंग,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

'मोदी शरणम् गच्छामि'

दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक इन दिनों राज्य में कुछ बड़ा 'खेला' होने की बात कही-सुनी जा रही है। वीआईपी पार्टी के विधान दल में सेंधमारी कर उसके तीन विधायकों को अपने दल में शामिल करा भाजपा आलाकमान ने इन चर्चाओं को अब तूफान में बदल डाला है। गौरतलब है कि उत्तरी भारत के मुख्य राज्यों में अकेला बिहार ऐसा राज्य है जहां भाजपा कई बार सत्ता में तो भागीदारी कर चुकी है लेकिन खुद का मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनवा पाई है। 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की परफॉरमेंस गठबंधन सहयोगी जद(यू) से खासी बेहतर रही लेकिन मुख्यमंत्री पद जद(यू) के पास ही रहा। अब खबर है कि भाजपा नीतीश कुमार को येन-केन-प्रकारेण पद छोड़ने के लिए तैयार करने का 'खेला' रच रही है। यही कारण है कि यकायक नीतीश बाबू का नाम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए उछाला गया है। भाजपा सूत्रों की मानें तो पार्टी आलाकमान नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई देने के मूड में है। दूसरी तरह नीतीश कुमार भी समर्पण की मुद्रा में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने नमस्कार किया उससे साफ झलकता है कि नीतीश बाबू अब 'मोदी शरणम् गच्छामि' को स्वीकार चुके हैं।

राज्यसभा वापसी के लिए बेचैन सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल इन दिनों लगातार गांधी परिवार को निशाने पर लिए हुए हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तो उनके तेवर खासे कड़े हो चले हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस को यदि बचाना है तो गांधी परिवार को पार्टी से हटाना होगा और किसी अन्य को पार्टी की कमान सौंपनी होगी। सिब्बल के ये तेवर हैरान करने वाले हैं क्योंकि उन्हें संसद की सदस्यता से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री की कुर्सी तक सब कुछ गांधी परिवार की कृपा के चलते ही मिला है। वकील भले ही वे काबिल हों, राजनीति में उनका कोई आधार नहीं रहा है। हालांकि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में सिब्बल ने दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जीत दर्ज कराई लेकिन इसके पीछे कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट बैंक का होना था। सिब्बल को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की दोनों सरकारों में मंत्री पद सोनिया गांधी के चलते मिला। इसके बावजूद उनका एंटी गांधी परिवार रुख अपनाना बहुतों की नजर में पाला बदलने के गेम प्लान का हिस्सा है। दरअसल, सिब्बल का राज्यसभा टर्म इस वर्ष जुलाई में समाप्त होने जा रहा है। वे उप्र से सांसद हैं जहां उनकी पार्टी के पास मात्र दो विधायक हैं जिसके चलते वे दोबारा उप्र से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा नहीं जा सकते।

कुछ बनेंगे लाट साहब तो कुछ मार्गदर्शक

हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में नाना प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। यह भी कहा-सुना जा रहा है कि कई बड़े चेहरों को सक्रिय राजनीति से विदा करके राजभवनों में स्थापित किया जाना तय हो चुका है तो कई चेहरे ऐसे भी हैं जो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के समान 'मार्गदर्शक' बना दिए जाएंगे। संभावित गर्वनरों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का चल रहा है जिन्हें पिछली दफे हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। खबर गर्म है कि इन दिनों भाजपा मुख्यालय में घंटों बैठ अपना समय व्यतीत करने वाले जावड़ेकर को गवर्नर बनाए जाने की पैरवी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा की गई है। इसी प्रकार कभी प्रधानमंत्री मोदी की टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी राज्यपाल बनाए जाने की बात कही-सुनी जा रही है। प्रसाद को भी जावेड़कर के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। भाजपा सूत्रों की मानें तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और आठ बार के सांसद संतोष गंगवार का नाम भी संभावित लाट साहबों की सूची में शामिल है।

अब पछताए होत क्या जब...

बसपा सुप्रीमो मायावती गहरे सदमे में बताई जा रही हैं। इस सदमे का कारण है उनका कोर वोट बैंक जो पहली बार उनसे बड़ी संख्या में छिटक भाजपा के पक्ष में जा खड़ा हुआ है। बसपा की असल ताकत रहे जाटव वोटरों ने इन चुनावों में मायावती के बजाय योगी पर भरोसा जता बहिनजी की जमीन हिलाने का काम कर डाला है। दरअसल, काशीराम से जाटव समाज का गहरा जुड़ाव 80 के दशक में बना था। इस समाज ने 1984 में बसपा के गठन के बाद से लगातार पार्टी का साथ दिया। लेकिन इस बार जो चुनावी डाटा सामने आया है उससे स्पष्ट होता है कि 22 फीसदी जाटव अब लाभार्थी वोटर में तब्दील हो बसपा से छिटक गया है। भाजपा ने इस समाज को लुभाने के लिए एक के बाद एक जाटव नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबीरानी मौर्य को चुनावों से ठीक पहले उप्र की राजनीति में सक्रिय कर इस वोट बैंक को रिझाने के साथ-साथ आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को वीआरएस दिला चुनाव मैदान में उतारा गया।

फुल एक्शन मोड में अखिलेश

समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार से हतोत्साहित नहीं हुए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो वह अभी से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि शिवपाल करहल सीट से अपने पुत्र आदित्य सिंह को उपचुनाव लड़ाना चाह रहे थे और इसके चलते वे अखिलेश को सांसदी न छोड़ने की सलाह दे चुके थे। ऐसे में पारिवारिक दबाव को कम करने की नीयत के चलते ही अखिलेश ने बगैर देर किए लोकसभा से त्याग पत्र दे डाला। कहा जा रहा है कि इस सीट से अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को उपचुनाव लड़ा संसद भेजने का मन बना रहे हैं। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में यदि अखिलेश उन्हें आजमगढ़ से उपचुनाव जिता लोकसभा भेजते हैं तो इससे ओबीसी समाज में सपा के प्रति सद्भाव बढ़ेगा।

आईएएस को दिखाया ठेंगा

प्रदेश में मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन की तर्ज पर प्रदेश के माननीयों और अफसरों के बीच अपने सरकारी बंगले को न्यारा बनाने की प्रतिस्पर्धा सी लगी रहती है। इस कारण राजधानी में सरकारी बंगलों पर तोड़फोड़ और नवनिर्माण का काम चलता रहता है। जनता से मिले टैक्स से अपने बंगले को न्यारा बनाने के लिए 1994 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने भी इच्छा जाहिर की। साहब की इच्छा पर पीडब्ल्यूडी वालों ने साहब की मंशानुसार निर्माण कार्य का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया। लेकिन वित्त विभाग ने फाइल रोक दी है। कारण क्या है यह तो साहब और वित्त विभाग ही बता सकते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बंगले पर पहले भी लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। 2019 से पहले यह बंगला प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री के पास था, फिर एक दूसरे मंत्री के पास आ गया। तब इस पर 75 लाख रुपए उनके विभाग द्वारा खर्च किए गए थे। फिर सत्ता परिवर्तन के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी को यह बंगला मिल गया। उन्होंने भी अपनी मंशानुसार निर्माण करवाया। अब जिन साहब को मिला है वे भी इसे न्यारा बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई है। साहब की कोशिश को वित्त विभाग ने ठेंगा दिखा दिया है। सूत्र बताते हैं कि वर्तमान में साहब के पास जिस एक निगम की जिम्मेदारी है, उससे भी वे अपने बंगले में खर्च करा चुके हैं।

साहबों की पार्टियां चर्चा में

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो अफसरों की जुगलबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दोनों साहब एक ही जिले में पदस्थ हैं। एक साहब जिले के कलेक्टर हैं तो दूसरे एसपी। मालवा के एक जिले में पदस्थ इन अफसरों के बारे में कहा जाता है कि दिनभर अपने-अपने काम की वजह से ये भले ही अलग-अलग रहते हों, लेकिन शाम ढलते ही दोनों की यारी परवान चढ़ने लगती है। अक्सर दोनों अफसरों की पार्टी एसपी साहब के बंगले पर ही सजती है। इसकी वजह यह है कि एसपी साहब अकेले रहते हैं। वहीं कलेक्टर साहब का भरा-पूरा परिवार है। लेकिन खाने-पीने के शौकीन दोनों अफसर लगभग हर शाम हम प्याला और हम निवाला होने का मौका नहीं चूकते हैं। सूत्रों का कहना है कि शाम ढलते ही दोनों इस जुगाड़ में जुट जाते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाया जाए और पीने-पिलाने की महफिल जमायी जाए। सूत्रों का कहना है कि अकेले होने के कारण एसपी साहब को रोकने और टोकने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन कलेक्टर साहब को रोजाना प्रशासनिक बैठकों या कार्यों का बहाना बनाकर घर से निकलना पड़ता है। अब साहब के परिजनों को इस बात की जानकारी है कि नहीं यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इसकी चर्चा राजधानी में जरूर हो रही है।

नजर लागी दूसरे कमरे पर

आपने यह गाना तो सुना ही होगा कि नजर लागी राजा तोहरे बंगले पर...। कुछ ऐसी ही स्थिति राज्य मंत्रालय में इस समय देखने को मिल रही है। दरअसल, प्रदेश के एक प्रमुख विभाग के एसीएस के लिए राज्य मंत्रालय में एक कमरा चिन्हित है। माना जाता है कि उस कमरे को उक्त विभाग के एसीएस को ही अलॉट किया जाता है। लेकिन अभी तक यह कमरा किसी को अलॉट नहीं किया गया है। यही नहीं उक्त विभाग के जो नए एसीएस आए हैं, वे भी एक दूसरे कमरे में जाकर बैठ रहे हैं। इस कारण उनके लिए चिन्हित कमरे में ताला डला है। अक्सर लोग ताला देखकर सवाल पूछते हैं कि आखिर इस कमरे में ताला क्यों है। लेकिन जवाब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि जिस विभाग के जिस अफसर के लिए यह कमरा अलॉट होता है, उन साहब की किसी और साहब के कमरे पर नजर है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि अभी हाल ही में एक एसीएस रिटायर हुए हैं। साहब ने उन रिटायर अफसर के कमरे पर नजर गड़ा रखी है। उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर उन्हें वह कमरा अलॉट हो जाए। बताया जाता है कि साहब ने इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिया है। वहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि विभाग के लिए आरक्षित कमरे को छोड़कर साहब ने दूसरे के कमरे की चाह पा ली है।

बिगड़ न जाए खेल

प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी इन दिनों हैरान-परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक प्राइवेट इस्तगासा दायर किया गया है। इसमें साहब पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए। गौरतलब है कि साहब इस विभाग में पदस्थापना से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। लेकिन सरकार ने इस पद के लिए उन्हें योग्य मानते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जाता है कि साहब को जबसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश के कई अफसरों को वे चुभने लगे हैं। इसलिए साहब को घेरने के प्रयास उनकी पदस्थापना के साथ ही शुरू हो गया था। अब जाकर साहब के खिलाफ प्राइवेट इस्तगासा दायर किया गया है। वैसे बता दें कि साहब जिस विभाग में पदस्थ हैं, उसे काजल की कोठरी कहा जाता है और इसकी कालिख से कोई बच नहीं पाया है। हालांकि मिलनसार छवि के साहब की हमेशा कोशिश रही है कि वे सबको साधकर चलें, लेकिन अंततः उन पर आरोप मढ़ने में उनके विरोधी सफल हो गए हैं। अब देखना है साहब इससे कैसे निकलते हैं।

क्या यहां भी चलेगा बुल्डोजर

प्रदेश में ही नहीं बल्कि देशभर में इन दिनों बुल्डोजर मामा चर्चा का विषय बने हुए हैं। माफिया और अपराधियों में बुल्डोजर मामा का खौफ समाया हुआ है। आलम यह है कि गलती छोटी हो या बड़ी सरकार से मिले फ्रीहैंड के बाद अफसर बुल्डोजर चलाने में देर नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक बुल्डोजर रीवा के सरकारी सर्किट हाउस में एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के दोषियों के ठिकानों पर चला है। लोग इसे बुल्डोजर मामा का त्वरित न्याय बता रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि सामूहिक बलात्कार करने वालों में एक रीवा जिले का हिस्ट्रीशीटर बदमाश भी था। उसी बदमाश के नाम पर सरकारी सर्किट हाउस का कमरा अलॉट किया गया था। यह कमरा हिस्ट्रीशीटर को किसी बड़े नेता की अनुशंसा पर अलॉट हुआ था। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उक्त नेता के घर पर भी बुल्डोजर चलेगा। अगर नीतिगत नजरिए से देखें तो उक्त नेता के बंगले पर बुल्डोजर हर हाल में चलना चाहिए, क्योंकि उक्त नेता के रसूख से ही अपराधी को कमरा अलॉट हुआ था, जहां नाबालिग के साथ दुराचार हुआ था।

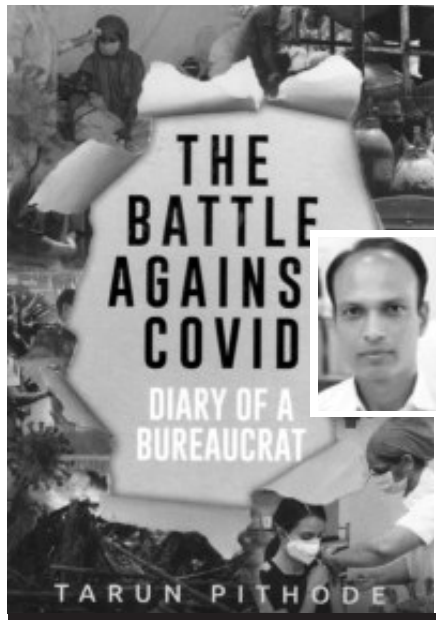

दो आईएएस की किताबें चर्चा में

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो किताबें चर्चा में हैं। इनमें से एक किताब है 2009 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण पिथोड़े और दूसरे हैं इसी बैच के आईएएस अभिषेक सिंह। पिथोड़े की पुस्तक 'द बैटल अगेंस्ट कोविड-डायरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट' इस सदी की सबसे बड़ी आपदा पर आधारित है। वहीं अभिषेक सिंह की किताब 'स्याही के रंग' पूरी तरह साहित्यिक है। इस किताब में उन्होंने कविताओं के माध्यम से जीवन के विभिन्न आयामों में शब्दों का रंग भरा है। इन दोनों प्रशासनिक अधिकारियों की किताबें खूब पढ़ी जा रही हैं और उन पर चर्चाएं भी हो रही हैं।

गौरतलब है कि एक चुस्त-दुरुस्त प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही पिथोड़े लेखक और विचारक भी हैं और इनकी कई मोटिवेशनल किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। शहर और गांव के सतत् विकास के प्रति संवेदनशीलता रखने वाले पिथोड़े ने सीहोर कलेक्टर रहते हुए देहदान करने का संकल्प भी लिया था। यही नहीं वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए भी वह जाने जाते हैं।

तरुण पिथोड़े दरअसल एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं। तरुण पिथोड़े द्वारा लिखित 250 पन्नों की इस किताब में देश के विभिन्न शहरों में पदस्थ आईएएस ऑफिसर्स के कोरोनाकाल के दौरान के अनुभवों को साझा किया गया है। किताब के लेखक तरुण कुमार पिथोड़े ने इस किताब के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि हम सभी लोगों की मदद से ही यह संसार चलता है। कोविड की लड़ाई तो केवल एक मुद्दा था, जिसने हमें यह अहसास कराया कि यह जीवन एक-दूसरे की मदद से चल रहा है।

इस किताब का पब्लिकेशन ब्लूम्सबैरी ने किया है। इस किताब में कोविड महामारी से हुई तबाही का चित्रण किया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पिथोड़े ने अपने अनुभवों, संघर्षों और विभिन्न राज्यों में अपने सहयोगियों के जरिए पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रबंधन करने वालों के अनुभवों को बताया है। उन्होंने इस किताब में जानलेवा वायरस को समझने और इसके प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा बनाई गई रणनीति की रूपरेखा का भी खुलासा किया है। इस किताब में उन प्रवासी कामगारों के कष्टों का भी विवरण है, जिन्होंने घर वापसी के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इस किताब में डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों, प्रशासकों और नागरिकों की वीरता की कहानियां भी हैं, जिन्होंने लोगों को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी।

दरअसल, ये किताब परदे के पीछे कोविड के खिलाफ लड़ाई का अमूल्य रिकॉर्ड है कि कैसे नौकरशाही ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करने वाले संकट का प्रबंधन किया है। कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद कई किताबें लिखी गईं। लेकिन वे किताबें किसी कोने में बैठकर आपदा के दंश की कल्पना कर लिखी गई हैं। जबकि तरुण पिथोड़े की यह किताब पूरी तरह आंखों देखी दास्तान कहती है। आपदा के दौरान ये भोपाल कलेक्टर भी रहे और उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसलिए उनकी यह किताब पूरी तरह वास्तविकता पर आधारित है। उन्होंने कोविड त्रासदी को न केवल आंखों से देखा बल्कि महसूस भी किया है। इसका पूरा चित्रण 'द बैटल अगेंस्ट कोविड- डायरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट' में मिलता है।

● **कुमार राजेंद्र**

सत्य का साक्षात्कार है 'स्याही के रंग'

आईएएस अभिषेक सिंह का कविता संग्रह स्याही के रंग में कवि ने सत्य का साक्षात्कार कराया है। कई कविताएं ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे यह कल्पना नहीं सत्य है। इससे ऐसा लगता है, कवि ने अपने साथ घटित घटनाओं और आंखों देखी को शब्दों में पिरोकर कविता का रूप दिया है। प्रकृति, प्रेम, परिवार और परिदृश्यों का ऐसा चित्रण किया गया है, जिसमें अपनापन झलकता है। भावों, विचारों और सोच का अद्भुत सामंजस्य स्याही के रंग को स्वर्णिम बना रहे हैं। अभिषेक की कविताओं में मन में हिलोरें लेने वाले जज्बात, जेहन में उठने वाले ख्याल महसूस किए जा सकते हैं। अतुकांत होने के बाद भी इन कविताओं में एक लय है, भावों की लय, जो पाठक को इनसे बांधे रखती है। अभिषेक सिंह की कविताएं अन्याय का प्रतिरोध करती हैं और पीड़ित के साथ गहरा तादात्म्य स्थापित करती हैं। कवि ने समाज, ब्यूरोक्रेसी, नेताओं में फैली बुराइयों पर भी कड़ा प्रहार किया है, वहीं कोरोना महामारी के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को रोकने का आह्वान किया है। कवि ने कोरोना के निराशा के घने अंधकार में भी आस का एक नन्हा दीया जलाकर रखा है। बहरहाल, भावनाओं के अलावा काव्य सृजन के मामले में भी कविताएं उत्कृष्ट हैं। कविता की भाषा में प्रवाह है, एक लय है। कवि ने कम से कम शब्दों में प्रवाहपूर्ण सारगर्भित बात कही है। कविताओं में शिल्प सौंदर्य है। कवि को अच्छे से मालूम है कि उसे अपनी भावनाओं को किन शब्दों में और किन बिम्बों के माध्यम से प्रकट करना है और यही बिम्ब विधान पाठक को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कविता में चिंतन और विचारों को सहज और सरल तरीके से पेश किया गया है जिससे कविता का अर्थ पाठक को सहजता से समझ आ जाता है। पुस्तक का आवरण सूफियाना है, जो इसे आकर्षक बनाता है। काव्य प्रेमियों के लिए यह एक अच्छा कविता संग्रह है।

मामा का बुलडोजर रुकेगा नहीं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मप्र में जितने गुंडे और अपराधी हैं, वो भी सुन लें, अगर गरीब-कमजोर की तरफ हाथ उठे तो मकान को मैदान बना दूंगा। गुंडागर्दी करने वालों, मप्र की धरती से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। सबको कुचल दिया जाएगा। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह मप्र है। मामा का बुलडोजर चला है... जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा, रुकेगा नहीं।

शिवराज ने कहा कि यहां कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सब हैं। किसी गरीब को घबराने की जरूरत नहीं है। इस घटना को एक सबक के तौर पर लेते हुए पूरे प्रदेश में एक-एक घर की सर्चिंग कर अवैध हथियार निकालने के निर्देश दिए गए हैं। शिवराज ने कहा कि लकड़ी चोरी के मामले निकालो। जो शिकारी बनते हैं उनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तैनात करो। घर-घर सर्चिंग करके देखो। शिवराज ने कहा कि गरीबों को पूरी तरह से सुरक्षा देने की जवाबदारी हमारी है। जितने भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले और दुराचार करने वाले, ये समझ लें, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री था और चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक था। लेकिन अब एक भी डाकू नहीं बचा है। कोई गिरोह नहीं बचने दिया।

गौरतलब है कि उप्र में बाबा का बुलडोजर कमाल कर गया। अब यही कमाल भाजपा मप्र में करना चाहती है। इसलिए यहां 'मामा का बुलडोजर' चलाया जाएगा। इसी लाइन के साथ वो अगले विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। इसके साफ संकेत हाईकमान से मिल गए हैं और शिवराज ने भी इसी स्ट्रैटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए उप्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा के नाम से बन गई है, चूंकि उन्होंने अवैध निर्माण और दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके चलते उप्र में भाजपा की जीत पर भी सभी जगह बुलडोजर लेकर जुलूस निकाले गए, इसके बाद अब मप्र में भी शिवराज सरकार द्वारा अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिससे मप्र में शिवराज सिंह चौहान को लोग बुलडोजर मामा कहने लगे हैं।

दरअसल, यह एग्रेशन दिखाने की दो वजह हैं। इसमें से पहली है उप्र चुनाव के नतीजे। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए बाबा ने बुलडोजर से जो 'हीरो' वाली छवि गढ़ी और हार्ड कोर कैंपेन चलाया, उसने सारे समीकरण ही बदल दिए। श्योपुर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी मोहसिन, रियाज और शाहबाज के घर ढ़हा दिए गए। सिवनी में कॉलेज छात्रा के साथ रेप के आरोपी हरिराम वर्मा, राहुल वर्मा, विकास सिंह, निरपत वर्मा, वीरेंद्र वर्मा के घर पर बुलडोजर चलाया। रायसेन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल हुए। यहां भी आरोपियों के घर ढहा दिए गए। पोस्टर लगने के अगले दिन शहडोल में सामूहिक बलात्कार के आरोपी अब्दुल शादाब के घर पर बुलडोजर चला। जावरा में अपहरण के आरोपी भूरू, जहरउद्दीन और उमर खां के निर्माण को तोड़ा गया। इससे पहले रतलाम में ड्रग माफिया लाला पठान का अवैध मार्केट तोड़ा गया। इन सब घटनाओं के बाद हाल ही में भोपाल में पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक होर्डिंग लगवाया है। जिस पर लिखा- 'बेटियों की सुरक्षा में जो भी बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा।' जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री गत दिनों रायसेन के उस खमरिया गांव में पहुंचे थे, जहां दो वर्ग भिड़ गए थे। यहां **उन्होंने चेतावनी** भरे लहजे में कहा- मामा का बुलडोजर चल निकला है। जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा, रुकेगा नहीं। जिन्होंने आदिवासियों पर हमला किया है, उनके घरों को खोदकर मैदान बना दिया जाए।

सियासी जानकारों के अनुसार प्रदेश में बीते दिनों तीन बड़ी कार्रवाई हुई है। जिसकी ब्रांडिंग भी खूब की जा रही है। सरकारी तंत्र के साथ-साथ संगठन के लोग भी इस कार्रवाई का प्रचार कर रहे हैं। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमेशा मुस्कुराते रहने वाले शिवराज सिंह चौहान की एक नई छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि शिवराज का मूल स्वभाव यह नहीं है। इसे शिवराज की छवि से जोड़कर नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रतीक के तौर पर देख सकते हैं। उप्र में इस एजेंडे से भाजपा को बड़ा लाभ मिला है। वहां 80:20 के सियासी रंग को अब भाजपा मप्र में भी सरकार के सहारे और गहरा करने की कोशिश कर सकती है। दरअसल, 2018 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। साफ है कि पार्टी किसी नए एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। अब देखना होगा कि शिवराज इस रास्ते पर कितना आगे तक बढ़ सकते हैं?

● **सुनील सिंह**

मामा के लिए लगी बुलडोजरों की लाइन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के दो साल पूरे होने पर गत दिनों मप्र में जमकर जश्न मनाया गया, जिसके तहत एक विधायक ने बुलडोजर की लाइन लगवाकर अनूठा जश्न मनाया, जो प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के दो साल पूरे होने का जश्न विभिन्न तरीकों से मनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को चौथी पारी का मुख्यमंत्री बने दो साल पूरे होने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अनूठा आयोजन किया। उन्होंने बिड़ला मंदिर के समीप स्थित मालवीय नगर युवा सदन निवास पर करीब एक दर्जन से अधिक बुलडोजर खड़े करवा दिए, इन पर बड़े-बडे होर्डिंग्स लगे हुए थे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुलडोजर मामा के नारे लगाए गए। इसी के साथ प्रदेश में कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल-ढमाकों के साथ शिवराज सरकार के दो साल पूरे होने पर आतिशबाजी, नारेबाजी और मिठाईयां बांटकर जश्न मनाया।

विकास और वोट का रोडमैप तैयार

> *हिल स्टेशन पचमढ़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट ने दो दिनों तक चिंतन, मनन और मंथन के बाद विकास और वोट का ऐसा रोडमैप तैयार किया है, जिससे भाजपा को उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मप्र में पिछले बार की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब इस रोडमैप के सहारे भाजपा जनता के बीच राज्य और केंद्र सरकार की ब्रांडिंग करेगी।*

भोपाल से सवा दो सौ किलोमीटर दूर पचमढ़ी के जंगल में दो दिनों में करीब 21 घंटे की मैराथन चिंतन बैठक का निचोड़ यह निकला कि सरकार को अपनी तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। जनता को बताना होगा कि उसके लाभ की योजनाएं केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार लेकर आई है। यह तय किया गया कि योजनाओं का भरपूर प्रचार-प्रसार किया जाए, प्रदेश से लेकर विकासखंड तक आयोजन किए जाएं, इनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के स्थानीय पदाधिकारी भी शामिल हों। दरअसल, राजधानी की भागम-भाग से दूर एकांत में खुले मन और सकारात्मक सुझावों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पचमढ़ी में बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य डेढ़ साल बाद 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करना ही था।

उप्र में भाजपा दोबारा सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई है, लेकिन पार्टी की इस कामयाबी को लेकर मप्र सरकार सहज नहीं है। चिंतन बैठक को लेकर तमाम मंत्री दो दिन के दौरान यही कहते रहे कि 2023 का चुनाव कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी रहे, जिन्होंने अनौपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी छवि को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर ही मुख्यमंत्री ने सुझाव लिए हैं। वजह यह है कि सरकार की तमाम योजनाएं पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लेकर जनता में सरकार के प्रति आकर्षण बनाने की जरूरत है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि हालांकि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद एक तरह से खत्म हो गई है, फिर भी जोखिम लेना उचित नहीं होगा।

शिवराज कैबिनेट के दो दिवसीय चितंन शिविर में प्रदेश के विकास की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। मंथन के बाद विभिन्न बिंदुओं पर मुहर भी लगी है। कैबिनेट की दो दिवसीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिविर में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद तीर्थ पर निकलकर नए सिरे से तीर्थदर्शन यात्रा की शुरुआत करेंगे। अप्रैल माह में शिवराज मंत्रिमंडल के साथ ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 48 हजार करोड़ के निर्माण कार्य होना है। इसके लिए समय सीमा में योजनाओं को शुरू कराया जाएगा, ताकि समय पर विकास कार्य पूरा हो सके। चिंतन शिविर में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में बेटियों की शादी के लिए 21 अप्रैल से कन्यादान योजना दोबारा शुरू की जाएगी।

हारी विधानसभा सीटों पर दिया जाएगा ध्यान

पचमढ़ी में चिंतन बैठक के अंतिम सत्र में हुई राजनीतिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी सीटों पर पूरा ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम 90 फीसदी काम पूरा कर देते हैं और जो 10 फीसदी अधूरा रहता है, उसका हल्ला मचता है। इसलिए अब सभी योजनाओं के 100 फीसदी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की है। इसके साथ मंत्री जनता के बीच जाएं, सीधे हितग्राही से संपर्क करें, पार्टी कार्यकर्ता से संपर्क करें। उन्होंने सभी योजनाओं को नए सिरे से जनता के बीच उतारने के लिए तारीख तय करने के साथ ही उनके प्रचार-प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों में पूरी सहभागिता और संगठन के 10 फीसदी वोट प्रतिशत बढ़ाने में पूरा योगदान देने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल का समय हमारे पास है, इसमें हम इतना काम कर दें कि चुनाव के समय हमें चिंता ही न रहे। कुछ मंत्रियों ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी बात रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की मंशा के विरुद्ध कोई कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि सरकार के हिसाब से कोई अफसर नहीं चलता है तो उसे हटा दिया जाएगा।

उन्होंने प्रदेश में अन्न उत्सव मनाने और शहरों में संजीवनी क्लीनिक खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाकर लोगों को आवागमन की ठीक से सुविधाएं दे पाएं। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगी। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं, उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में बेटियों की शादी के लिए 21 अप्रैल से कन्यादान योजना दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में अन्न उत्सव मनाने और शहरों में संजीवनी क्लीनिक खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाकर लोगों को आवागमन की ठीक से सुविधाएं दे पाएं। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगी। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं, उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे।

आयोजन की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार की गई है। 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना-2 शुरू होगी। 2 से 11 मई तक ब्लॉक स्तर तक लाडली लक्ष्मी उत्सव चलेगा। 2 मई को योजना का नया स्वरूप जारी होगा। निशुल्क राशन अगले 6 महीने तक 10 किलो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। 7 अप्रैल से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। सीएम राइज स्कूल के तहत जून से नए भवन बनाए जाएंगे। 13 जून से 350 सीएम राइज स्कूल शुरू होंगे। शहरों में 25 हजार की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक खुलेगा। 22 अप्रैल से शुरुआत होगी। सालभर में अभी नगरीय निकायों में खोलेंगे। मई से हर जिले में दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर खुलेगा। जल जीवन मिशन के लिए 6 हजार करोड़, 11 अप्रैल से जलाभिषेक अभियान और अगले महीने से

ग्रामीण परिवहन की नीति आएगी। 1 जून से साइबर तहसीलों की शुरुआत होगी। अविवादित मामले घर से निपटेंगे। टूरिज्म से रोजगार बढाएंगे। मप्र में बिजली का स्टोरेज होगा। मां तुझे प्रणाम योजना फिर शुरू होगी। मप्र के युवा सीमा पर जाएंगे। नए स्वरूप में समाज कल्याण विभाग कन्या विवाह योजना को शुरू करेगा। इसमें अब 51 हजार रुपए की जगह 55 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। विकासखंड स्तर पर पहले से तारीख तय कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना में सामूहिक विवाह ही होंगे। यह योजना प्रदेश से ही शुरू हुई। बाद में किसी न किसी रूप में देश के हर राज्य ने अपनाया। प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी हो गई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना-2 दोबारा प्रारंभ होगी। इसमें 2 मई से 11 मई तक प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। योजना के तहत लाडली को उच्च शिक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक संशक्तिकरण के लिए नए निर्णय लिए गए है। इसकी घोषणा लाडली लक्ष्मी उत्सव पर करेंगे। गांव में लाडली क्लब बनाए जाएंगे। जिनमें लाडली और उसकी मां को स्वसहायता समूह से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का समय 6 माह और बढ़ा दिया है। इसके तहत निशुल्क 5 किलो राशन दिया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चलती है। दोनों को मिलाकर 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को मिलेगा। राशन दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। राशन की दुकानों को प्रॉफिट का जरिया बनाए जाने के भी कदम उठाए जा रहे हैं। दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन वेंडर, बिजली बिल की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही राशन बांटने के अलावा दूसरी वस्तुएं भी बेची जा सकेंगे। अब एक वेंडर के पास एक ही दुकान रहेगी। सीएम राइज स्कूल बनने में अभी समय लगेगा। इन स्कूल के भवनों के निर्माण पर 24 करोड़ की लागत आएगी। इसमें लाइब्रेरी, लैब, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास की सुविधा होगी। शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग के साथ ही उनके कार्य का ऑडिट भी होगा। अभी 350 स्कूलों में सीएम राइज स्कूल की पढ़ाई शुरू की जाएगी। नए भवन तैयार होने के बाद स्कूलों को उनकी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्कूलों में गांव के बच्चों को बसों से लाने की सुविधा होगी। प्रदेश में साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि यदि किसी ने जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री कराई, उसके दर्ज होने के बाद ऑटोमेटिक रिकॉर्ड साइबर तहसील चला जाएगा। जहां से तहसीलदार को जानकारी भेजकर कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। दोबारा रिकॉर्ड के साइबर तहसील में वापस आने पर जमीन का नामांतरण हो जाएगा। इससे नामांतरण के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विवादित मामले में सुनवाई होगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश

शिवराज सरकार ने इस बार के दो सालों में माफिया पर सख्ती ज्यादा बरती है। गंभीर अपराधों के लिप्त बदमाशों के ठिकानों पर जेसीबी चलवाना हो या अपराधियों के आय के साधनों पर चोट करना। शिवराज सरकार ने अपराध पर लगाम कसने के लिए प्रयासरत सरकार होने का अहसास दिलाने की कोशिश की है। अब तो भाजपा शिवराज को बुलडोजर मामा की नई पहचान देने की योजना बना रही है। अपराध मुक्त प्रदेश के कामों के चलते उप्र में योगी आदित्यनाथ फिर सरकार बना चुके हैं। इस बार शिवराज भी ऐसी ही छवि बनाने और उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मप्र की धरती पर गुंडे और बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। गुंडागर्दी करने वालों के रसूख को समाप्त करके उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति सूझ रही है, पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह कमलनाथ की कांग्रेस सरकार नहीं, मामा की सरकार है। मामा का बुलडोजर चला है तो तब तक नहीं रुकेगा, जब तक अपराधियों को नेस्तनाबूद नहीं कर देता। गुंडागर्दी, दादागिरी, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले और दुराचार करने वाले ये समझ लें, उनके मकान को मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा।

मसाले के नाम पर बांट दिया मिर्च बीज

किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मसाला क्षेत्र विस्तार योजना शुरू किया है। जिसका उद्देश्य है कि योजना में शामिल अजमोदा, अजवायन, मैथी, धनिया, लहसून, हल्दी, जीरा, सौंफ, दिल और निगेला आदि की खेती कर किसान अधिक मुनाफा कमा सके। लेकिन मप्र के उद्यानिकी विभाग और मप्र एग्रो ने मिलभगत कर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर मिर्च के बीज किसानों को बांट दिया। आरोप लगाया जा रहा है की योजना के तहत वर्ष 2021 में ही करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए के मिर्च बीज किसानों को बांटे गए हैं। वह भी 200 से 500 रुपए प्रति किलो के बीज को करीब 35,000 रुपए प्रति किलो के मान से उद्यानिकी विभाग ने खरीदकर केंद्र की मसाला योजना को पलीता लगाया है।

जानकारी के अनुसार, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 2014 में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को 10 किस्म के मसाला बीज वितरित किया जाना है। जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 40 फीसदी और राज्य सरकार की ओर से 60 फीसदी अनुदान का प्रावधान है। लेकिन उद्यानिकी **विभाग के अफसरों ने** केंद्र सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए किसानों को मिर्च के महंगे बीज वितरित कर दिए।

केंद्र सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत राज्यों को अनुदान देती है। इसके लिए वह राज्यों से एक्शन प्लान मांगती है। देश में 24 राज्यों की तरह मप्र ने भी एक्शन प्लान भेजा था, जिस आधार पर उसे केंद्र से बीज मसाला एवं प्रकंदी मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार योजना के तहत अनुदान स्वीकृत हुआ। इसके बाद खेल शुरू हुआ। मप्र के उद्यानिकी विभाग और मप्र एग्रो के अधिकारियों ने योजना के तहत अनुदान पाने के लिए केंद्र के दिशा-निर्देशों को ही दरकिनार कर दिया। केंद्रीय योजना के अनुसार, बीज मसाला के क्षेत्र विस्तार के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को बीज बांटा जाना था, लेकिन विभाग ने इस योजना के दिशा-निर्देश के विपरीत जाकर हाइब्रिड मिर्च बीज की खरीदी कर ली। योजना में बीजीय मसाला के अंतर्गत अजवायन, मैथी, धनिया समेत 10 बीज मसाला फसलें शामिल हैं, लेकिन विभाग के द्वारा सिर्फ संकर मिर्च बीज की ही मप्र एग्रो से महंगी दरों पर खरीदी की गई, जो बीजीय मसाला फसल है ही नहीं।

हैरत की बात तो यह है कि मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत प्रदेश को जो भी लक्ष्य प्राप्त हुए थे, योजना के प्रावधान के अनुसार, जो फसलें प्रदेश के किसान लगाते हैं, उनमें लहसुन, हल्दी, धनिया, जीरा, मैथी आदि के कोई भी बीज कृषकों को उपलब्ध नहीं कराए गए, बल्कि केवल संकर मिर्च बीज ही खरीदे। विभाग और मप्र एग्रो द्वारा इतने संकर मिर्च बीज किसानों पर थोपे गए, जैसे किसान मिर्च के अलावा और कोई फसल लगाता ही नहीं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार से 7 करोड़ 20 लाख बजट आया था, जिसे हाइब्रिड मिर्च बीज खरीदी में लगा दिया गया। योजना में करीब 25 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, पर उन्हें अन्य मसाला बीज मिला ही नहीं।

केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से विभाग को नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइस (एनआरसीएसएस) के अनुसार योजना में बीजीय मसाला अर्थात् धनिया, अजवाइन, मैथी समेत 10 बीज मसालों के बीज की खरीद करनी थी, लेकिन इन्हें दरिकनार कर दिया गया। विभाग ने सिर्फ संकर मिर्च बीज की खरीदी की, जो बीज मसाला फसलों के समूह में नहीं आता। यह एनआरसीएसएस की सूची में शामिल भी नहीं है। मिर्च सप्लाई के लिए 6 निजी कंपनियों मेसर्स यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड हैदराबाद, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, मार्कफील्ड हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड जालना, नामधारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगुलरू, मोनसेंटो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड अहमदाबाद के रेट मप्र एग्रो में अनुमोदित है, जिनके संकर मिर्च बीज के रेट 28,600 रुपए से 35,090 रुपए किलो के बीच थे। तुलनात्मक देखा जाए तो योजना में लगने वाले किसी भी बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों के बीज की कीमत 100 रुपए से अधिकतम 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक ही हो सकती है। इसके विपरीत विभाग के द्वारा जो संकर मिर्च बीज मप्र एग्रो के माध्यम से खरीदा गया, उसकी कीमत 35,090 रुपए प्रति किलो तक है और इसी के चलते अधिकारियों ने इन कंपनियों से मिलीभगत कर इतना महंगा बीज किसानों को बांटने के लिए खरीदा। अब इस खरीदी का करोड़ों का भुगतान तेजी से करने की तैयारी है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

पुरानी दर पर ही खरीद लिया बीज

मिलीभगत कर घोटाला करने के लिए अफसरों ने रेट कॉन्ट्रैक्ट के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। निजी सप्लायरों से संकर बीजों की खरीद के लिए मप्र एग्रो ने अंतिम आरसीओ 2019 में आमंत्रित किया, जिसमें उक्त 6 कंपनियों के दर अनुमोदन किए गए। इस आरसीओ के तहत मप्र एग्रो ने इन 6 प्रदायकों की दरें 31 मार्च 2020 तक के लिए अनुमोदित की थी। उसके बाद विभाग को नए रेट कांट्रेक्ट करने थे, ताकि प्रतिस्पर्धा में बीज कम से कम दाम पर खरीदा जा सके, लेकिन मप्र एग्रो ने ऐसा नहीं किया। 2021 में मप्र एग्रो द्वारा संकर बीज के क्रय हेतु पुनः आरसीओ आमंत्रित किए गए, पर पुराने रजिस्टर्ड सप्लायर्स से मिलीभगत कर इस साल की आरसीओ को निरस्त कर दिया गया। इसका नतीजा यह है कि आज भी पुराने सप्लायरों द्वारा मप्र एग्रो के जरिए अवैध पुरानी दरों पर कृषकों को बीज थोप रहे हैं। बता दें कि मप्र एग्रो में पंजीकृत सभी सप्लायरों की दर अधिकतम 30 सितंबर 2020 तक के लिए थी। पहले के सालों में प्रदेश के किसानों को बीज की व्यवस्था खुद करने के निर्देश दिए गए थे। इससे किसानों को बहुत परेशानी होती थी। इसके बाद उद्यानिकी विभाग द्वारा 2019 से किसानों को मप्र एग्रो के माध्यम से बीजों की व्यवस्था शुरू करवाई गई, लेकिन उद्यानिकी विभाग और मप्र एग्रो सप्लायरों से मिलीभगत कर केवल संकर मिर्च बीज ही किसानों को दिए गए।

अफसरों के बिगड़े बोल

मप्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुशासन पर जोर दे रहे हैं और अफसरों को अपनी हद में रहने की हिदायत देते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के नौकरशाह हैं कि वे सिविल सेवा आचरण नियमों को दरकिनार कर उटपटांग बोल रहे हैं। इससे देशभर में मप्र के अफसरों की साख पर दाग लग रहा है। वर्तमान समय में आईएएस नियाज खान अपने बिगड़े बोल के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं।

द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ट्वीट करने वाले आईएएस अधिकारी नियाज खान को मप्र सरकार ने नोटिस दिया है। उनसे 7 दिन में जवाब मांगा गया है। लोकनिर्माण विभाग में डिप्टी सक्रेटरी नियाज खान से सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 दिन में जवाब मांगा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट करने से चर्चा में आए आईएएस अधिकारी नियाज खान का मामला प्रदेश में नया नहीं है। इससे पहले लोकेश जांगिड़, सिबि चक्रवर्ती एम, जगदीश चंद्र जटिया सहित कई आईएएस अधिकारी अपने बिगड़े बोल से सरकार को मुश्किल में डालते रहे हैं। अफसरों के बिगड़े बोल से सरकार की छवि भी खराब हो रही है। इनमें से ज्यादातर मामलों में सरकार ने नोटिस जारी किए, तबादले किए और कुछ समय में मामला शांत हो गया। किसी भी अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई कभी नहीं हुई। शायद यही कारण है कि सिविल सेवा आचरण नियमों से बंधकर रहने वाले ये अधिकारी इंटरनेट मीडिया में बिगड़े बोल बोलने से नहीं चूक रहे हैं।

मुसलमानों की हत्या दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनाने की बात ने तूल पकड़ लिया है। यह मांग आईएएस नियाज खान ने की है। करीब 7 दिन से यह मामला गर्माया हुआ है। दो मंत्री, एक विधायक और एक भाजपा नेता नियाज खान पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है पर मामले का पटाक्षेप अभी नहीं हो पाया है।

एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में **सुशासन की वकालत** करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई नौकरशाहों ने उटपटांग बयान देकर सरकार को मुश्किल में डाला है। मंडला कलेक्टर रहते हुए जनवरी 2020 में जगदीश चंद्र जटिया ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर फिल्म छपाक का पोस्टर अपलोड किया और लिखा तुम चाहे जितनी घृणा करो, हम देखेंगे छपाक। इसके बाद उनके मित्रों ने टिप्पणी लिखी। मित्रों को जवाब देते हुए जटिया ने लिख दिया था कि उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना आता है। वे सीएए, एनआरसी का समर्थन नहीं करते। हालांकि विवाद बढ़ता देख जटिया ने अपनी पोस्ट हटा ली। वहीं नरसिंहपुर कलेक्टर रहते हुए वर्ष 2016 में सिबि चक्रवर्ती एम ने तमिलनाडु में दूसरी बार सरकार बनाने पर जयललिता की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि फेसबुक वॉल पर उन्हें बधाई भी दे दी। नौकरशाही और मंत्रालय में इसे लेकर सरगर्मी बढ़ी, तो चक्रवर्ती ने 2 घंटे में ही पोस्ट हटा दी। जबकि बड़वानी जिले में अपर कलेक्टर रहते हुए वर्ष 2021 में लोकेश जांगिड़ सरकार और सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने अपने ही कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। आईएएस अधिकारियों के ऑफिशियल ग्रुप में उन्होंने लिखा कि कलेक्टर मेरी वजह से पैसा नहीं खा पा रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री के कान भरकर उन्हें हटवा दिया। यह चैट चंद घंटों में ग्रुप से हटा दी गई। उन्हें नोटिस दिया और बाद में जिले से हटाकर भोपाल पदस्थ किया। वहीं बड़वानी कलेक्टर रहते हुए अजय गंगवार ने वर्ष 2016 में फेसबुक वॉल पर नेहरू-गांधी परिवार की तारीफ कर दी। यह तारीफ गंगवार को भारी पड़ी। उन्हें जिले से हटा दिया और मंत्रालय में उपसचिव पदस्थ कर दिया गया। काफी समय बाद उन्हें नई पदस्थापना दी गई। गंगवार अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

पत्नी से मारपीट के मामले में स्पेशल डीजी पद से निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गत दिनों गृह विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दो डीई एक साथ बिठा दी हैं। रिटायर्ड आईपीएस राजन एस. कटोज को जांच अधिकारी बनाया गया है। पहली जांच 29 सितंबर 2020 को सामने आए वीडियो में उनके द्वारा अनैतिक आचरण और पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किए जाने की है। वहीं, दूसरी जांच 3 अक्टूबर 2019 से 29 सितंबर 2020 तक 22 जिला अभियोजन अधिकारी समेत 99 कर्मचारियों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट के मामले में की जाएगी।

● **विकास दुबे**

सरकार को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाना होगी

पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर किसी भी अधिकारी का जातिगत, राजनीतिक और सामाजिक पोस्ट डालना अनुचित है। ये साफतौर पर सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। ऐसी पोस्ट लोगों में दूरियां बढ़ाती हैं। नई समस्याएं खड़ी करती हैं। ऐसा होना अनुशासन का उल्लंघन है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ढिलाई बरत रही है। नोटिस या तबादला ही इसका हल नहीं है। कई बार कार्रवाई होती भी है पर लचर तरीके से। सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए।

रुचि सोया ने कार्पोरेट लूट का इतिहास रचा

विजय माल्या और नीरव मोदी को पछाड़ते हुए बाबा रामदेव ने बैंकों को चूना लगाने का नया कीर्तिमान बना लिया। अभी रूचि सोया, जो कि पतंजलि ग्रुप के पास है, का एफपीओ जारी किया गया, जो कि आखिरी दिन 3.6 गुना सब्स्क्राइब हुआ। दरअसल शेयर बाजार से रूचि सोया 4 हजार 300 करोड़ रुपए जुटा रही है। वहीं दूसरी तरफ बैंकों को बाबा बनाकर रामदेव 25 हजार करोड़ के आसामी बन गए। दिवालिया फर्म रूचि सोया पर बैंकों का 1800 करोड़ रुपए से अधिक बकाया था, उसे बट्टे खाते में डालते हुए बैंकों ने एक रुपए की वसूली भी नहीं की, उलटा पतंजलि को रूचि सोया खरीदने के लिए एसबीआई ने 1200 करोड़ रुपए अलग दे डाले।

कॉर्पोरेट लूट और बैंकों को खोखला करने का रूचि सोया-पतंजलि ने नया उदाहरण प्रस्तुत किया। एसबीआई के साथ-साथ पीएनबी, सेंट्रल बैंक और अन्य ने भी कर्जा माफ कर दिया। दिसंबर 2019 में पतंजलि ने दिवालिया कंपनी रूचि सोया को खरीदा। पहले अडानी ग्रुप भी दौड़ में था, जो बाद में पीछे हट गया। अब पतंजलि पब्लिक इश्यू के जरिए 4300 करोड़ जुटाना चाहती है, ताकि **इस राशि का इस्तेमाल** कर्ज उतारने में किया जा सके। आधे से अधिक लोन को माफ करने के बाद एनसीएलटी ने सस्ते में रूचि सोया को पतंजलि के हवाले कर दिया। बाबा ने एनसीएलटी को भी चूना लगाकर एक फीसदी शेयर ही जारी किए और सेबी चुप रहा। फिर शेयर की कीमतों में घोटाला करते हुए साढ़े 3 रुपए का शेयर दो साल में एक हजार पार पहुंचा दिया। अब उसका 20 फीसदी हिस्सा पब्लिक इश्यू के रूप में सामने आ रहा है और जिस रूचि सोया को बाबा ने हजार करोड़ में खरीदा उसके एवज में रामदेव 25 हजार करोड़ के आसामी बन गए और बदले में बैंकों को बाबा बना दिया।

अन्ना हजारे ने जब तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तब उसमें बाबा रामदेव ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के भी नुस्खे सुझाए। तब से ही भाजपा की राज्य और फिर केंद्र में बनी सरकारें पतंजलि की मददगार साबित हुईं। यहां तक कि कोरोनाकाल में बाबा रामदेव ने जो विवादित आयुर्वेदिक कोरोनिल बनाई उसकी भी लॉन्चिंग तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कर दी, जिसको लेकर जमकर विवाद भी हुआ। वहीं पतंजलि के उत्पादों को लेकर भी तमाम शिकायतें मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरी तरफ रूचि सोया के मामले में तो कॉर्पोरेट लूट का इतिहास ही पतंजलि के पक्ष में लिख दिया गया। अभी सेबी ने बीड वापस लेने का जो विकल्प दिया, वह भी मार्केट जानकारों के मुताबिक दुर्लभ है।

सेबी ने प्रमुख बैंकिंग मैनेजर्स को भी निर्देश दिए कि वे सभी निवेशकों को अखबार में विज्ञापन के रूप में अवांछित एसएमएस के संबंध में आगाह करते हुए नोटिस जारी करें। वहीं बोलियों को वापस लेने के लिए अतिरिक्त विंडो के बारे में उन्हें सूचना दी जाएगी। सेबी पहले तो सोया रहा और अब उसकी नींद थोड़ी खुली और पतंजलि के यूजर्स को निवेश करने के जो ऑफर अवांछित एसएमएस के जरिए दिए गए, उस पर सेबी कार्रवाई कर रहा है। सेबी ने प्रथम दृष्टया ही इस मैसेज को फ्रॉड बताया और अब उसे विज्ञापन छापकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। खुदरा निवेशकों को अपनी बीड वापस लेने का विकल्प भी दिया गया। इस एसएमएस में लिखा गया कि पतंजलि परिवार के सभी प्रिय सदस्यों के लिए अच्छी खबर। खुदरा निवेशकों के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ओपन किया है, जिसका फायदा उठाया जाए।

गौरतलब है कि दिवालिया इंदौरी रूचि सोया कंपनी को औने-पौने दामों पर बाबा रामदेव की पतंजलि ने खरीदा और बैंकों को हजारों करोड़ रुपए की टोपी पहना दी। अभी रूचि सोया का एफपीओ जारी किया गया, जो 28 मार्च को बंद हुआ। मगर एक विवादित एसएमएस के चलते सेबी ने ना सिर्फ निवेशकों को निकलने का मौका दिया, बल्कि रूचि सोया को नोटिस भी जारी कर दिया और कहा कि अखबारों में विज्ञापन देकर निवेशकों को उनके आवेदनों से निकलने की अनुमति दी जाए। सेबी की कार्रवाई ने बाबा को जहां शीर्षासन करवा दिया, वहीं हरिद्वार में एफआईआर भी पतंजलि समूह द्वारा दर्ज करवाकर इस एसएमएस से पल्ला भी झाड़ने का प्रयास किया।

रूचि सोया के एफपीओ में निवेश के लिए प्रेरित करने वाला एक एसएमएस पिछले दिनों चला, जिसे सेबी ने नियमों का उल्लंघन माना और बाबा की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके चलते निवेशकों में भी भगदड़ की स्थिति रही और जो एफपीओ 3.6 गुना सब्स्क्राइब हुआ था, वह सेबी की कार्रवाई के बाद 24 घंटे में ही घटकर 2.58 गुना रह गया। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1.23 करोड़ बोलियां वापस ले ली और सब्स्क्रिप्शन भी 2.20 गुना से घटकर 1.6 गुना रह गया। एफपीओ का इश्यू प्राइट 615 से 650 रुपए तय किया गया था और सेबी के निर्देश के चलते रूचि सोया को बकायदा विज्ञापन जारी कर निवेशकों के लिए एफपीओ से निकलने का ऑप्शन खोलना पड़ा। यानी एक एसएमएस ने बाबा रामदेव को शीर्षासन करवा दिया। हालांकि कंपनी ने इस मामले में हरिद्वार में एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा कि जो एसएमएस जारी हुआ, वह कंपनी या उसके किसी प्रवर्तकों द्वारा जारी नहीं किया गया। किसी ने गलत एसएमएस जारी कर दिए। उधर, सेबी की कार्यवाही की घोषणा के बाद रूचि सोया के एफपीओ में निवेश करने वालों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अभी तक रीटेल इन्वेस्टर्स ने 1.23 करोड़ बोलियां वापस ले ली हैं।

● **जय सिंह**

बोलियां लगाने वाले निवेशक होने लगे बाहर

दरअसल 28 मार्च को रूचि सोया का एफपीओ बंद हुआ और उसी दिन शाम को सेबी ने वापसी के संबंध में निर्देश जारी कर दिए, जिसके चलते निवेशकों में भगदड़ मची और 24 घंटे में ही कई निवेशकों ने अपने आवेदन वापस ले लिए। 4300 करोड़ रुपए का यह एफपीओ यानी फॉलोऑन पब्लिक ऑफर रूचि सोया की ओर से जारी किया गया और देशभर में इसके विज्ञापन भी दिए गए।

सीपीए बन गया इतिहास

करीब 62 साल पहले 1 जून 1960 को गठित सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन 1 अप्रैल से इतिहास बन जाएगा। राजधानी भोपाल के विकास में इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शहर की कई योजनाओं को इस विभाग ने सजाया संवारा है, लेकिन खराब सड़कों की वजह से यह विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्रोध का इस कदर शिकार हुआ कि अब यह पूरी तरह बंद हो गया है। इस विभाग का काम अब कई विभागों में बांट दिया गया है। यानी एक अप्रैल से सीपीए जिन कामों को किया करता था, अब उसे लोक निर्माण विभाग, नगर निगम भोपाल आदि करेंगे। राजधानी की 92 किमी सड़कें और एनेक्सी जैसी बिल्डिंगें तो लोक निर्माण विभाग संभालेगा ही, लेकिन गैस राहत के काम भी वही देखेगा। 1 अप्रैल को वह सीपीए के काम और संपत्ति हैंडओवर कर लेगा। वहीं सभी 7 पार्क वन विहार के हवाले होंगे।

शिवराज कैबिनेट में 3 मार्च को सीपीए को समाप्त करने की फाइल पर मुहर लगने के बाद 17 मार्च को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए थे। सड़कें और बिल्डिंगें पीडब्ल्यूडी के हवाले किए गए तो 7 बड़े पार्क वन विभाग को सौंपे गए हैं। पहले गैस राहत के काम गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग को सौंपने की चर्चा थी, लेकिन अब यह काम पीडब्ल्यूडी ही देखेगा। गैस राहत के हॉस्पिटल समेत बिल्डिंगों की रिपेयरिंग पीडब्ल्यूडी के हवाले की गई है। बिल्डिंग, सड़कों या निर्माण से जुड़े अन्य कामों को पीडब्ल्यूडी के हवाले सौंपा गया है। अभी 147 करोड़ रुपए के 100 से अधिक निर्माण चल रहे हैं। ये काम अब पीडब्ल्यूडी करेगा। इन शाखाओं से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी, इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के अधीन काम करेंगे। बिट्टन मार्केट स्थित सीपीए का तीन मंजिला भवन भी पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाएगा। इसके साथ पीडब्ल्यूडी गैस राहत के काम भी करेगा।

वर्ष 1986 से अब तक सीपीए ने साढ़े 35 लाख से अधिक पौधे-पेड़ लगाए थे। वहीं, 132 एकड़ में फैले एकांत, प्रियदर्शनी, चिनार, मयूर, प्रकाश तरण पुष्कर समेत 7 बड़े पार्कों की देखरेख भी करता था। पहले इनका जिम्मा नगर निगम को देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। वहीं, निगम में नई विंग बनाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अब पार्क समेत इससे जुड़े सारे काम वन विभाग को सौंपा गया है। कुल 223 कर्मचारी वन विभाग में मर्ज किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने सीपीए को नई विंग की तरह संभालने के लिए इंजीनियर-कर्मचारियों की पोस्टिंग कर दी है। बताया जाता है कि सीपीए की जिन शाखाओं में कर्मचारी पदस्थ हैं, वे वहीं पर काम करते रहेंगे। उन्हें इधर से उधर नहीं किया जा रहा है।

उधर, सीपीए के बंद होने के बाद मास्टर प्लान की सड़कें बनाने को लेकर सरकारी एजेंसियों में कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है। नगर निगम, बीडीए और पीडब्ल्यूडी तीनों एजेंसियों ने अपने-अपने स्तर पर सड़कें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। मौजूदा मास्टर प्लान में 241 किमी सड़कें बनाने की बात थी, लेकिन केवल 53 किमी सड़कें ही बन पाईं, यानी अब भी 188 किमी सड़कें बनना है। मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी सीपीए के पास थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के लिए कलेक्टर गाइडलाइन से दोगुना मुआवजा देने की पॉलिसी आई तो सड़कों का निर्माण बहुत महंगा हो गया। टीडीआर पॉलिसी आने से पहले 188 किमी सड़कों के लिए सीपीए ने प्लानिंग की थी तो उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आते ही सड़कों का निर्माण रुक गया। इसके बाद ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की पॉलिसी आई, जिसे मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया। सीपीए ने शहर की 6 सड़कों को टीडीआर के आधार पर बनाने की प्लानिंग की, जब तक इसकी मंजूरी मिलती सीपीए ही भंग हो गया।

सड़क बनाने में एजेंसियों की ऐसी रूचि की असल वजह बजट का खेल है। एक किमी सिंगल लेन डामर सड़क एक करोड़ में बनती है और सीमेंट-कांक्रीट की डेढ़ करोड़ में। 4 से 5 किमी फोरलेन सड़क और उसके साथ टाउन प्लानिंग स्कीम जोड़ने पर प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती है। सीपीए ने जिन 6 सड़कों के टीडीआर से निर्माण की प्लानिंग की थी, अब उस पर निगम एक्शन में आया है। निगम ने उस पूरी प्लानिंग को जस का तस आगे बढ़ा दिया है। लेकिन, दूसरी तरफ बीडीए ने भी इनमें से दो सड़कों के निर्माण पर दावा कर दिया है। अब इनका निर्माण कौन करेगा, यह देखने वाली बात होगी।

● **राजेश बोरकर**

इस तरह समाप्त हुआ सीपीए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 अगस्त 2021 को सीपीए को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा। जिसे 3 मार्च को हुई शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। मंजूरी के साथ ही सीपीए को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसके तहत सीपीए का सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पार्कों के रखरखाव का काम वन विभाग और अन्य काम भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को सौंपे गए हैं। बता दें कि सीपीए भोपाल में सड़कों, मंत्रालय, विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह, गैस राहत एवं पुनर्वास, चिकित्सालय, सरकारी आवास और यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन का काम कर रहा था। अब 7 मार्च की बैठक में इन कामों का बंटवारा अन्य विभागों को किया जाएगा। एनेक्सी (मंत्रालय) की देखरेख की जिम्मेदारी भी किस विभाग को सौंपी जाएगी, यह भी देखने वाली बात रहेगी। वहीं शहर के पार्कों की जिम्मेदारी वन विभाग को दी जाएगी। वन विभाग ने 132 एकड़ में फैले शहर के 7 बड़े पार्कों, एकांत, प्रियदर्शिनी, चिनार, मयूर, प्रकाश तरण, पुष्कर की देखरेख का प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। पहले सीपीए के पार्क निगम को मिलने वाले थे लेकिन बाद में इन्हें वन विभाग को देने का फैसला किया गया।

आज सेना से लेकर हर मोर्चे पर महिलाएं अपना दम दिखा रही हैं। काम कोई भी हो महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सरकार भी महिलाओं को हर मोर्चे पर प्रोत्साहित कर रही है। उसके बावजूद कहीं न कहीं महिलाओं से भेदभाव किया जा रहा है। अगर प्रशासनिक सेवा को ही लें तो इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके महिलाओं को कलेक्टर बनाने में राज्य सरकारें परहेज कर रही हैं। इसकी वजह क्या है, यह किसी को नहीं पता।

महिलाओं को कलेक्टर बनाने में परहेज क्यों?

भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस में यूपीएससी के लोक सेवा परीक्षाओं के जरिए 2014 से महिलाओं की संख्या औसतन तकरीबन 30 फीसदी है, मगर देशभर में महिलाओं को जिला मजिस्ट्रेट या डीएम जैसा अहम पद मिलने का औसत 19 फीसदी से ज्यादा नहीं है। कुछ हफ्ते पहले केरल सरकार ने अपने 14 में से दसवें जिले में एक महिला आईएएस को डीएम बनाया। इससे वह देश में महिला डीएम के मामले में दूसरे नंबर का राज्य हो गया है। इस मामले में दिल्ली के बाद केरल का नंबर है। राजधानी दिल्ली में 11 में से 9 डीएम महिलाएं हैं। केरल और दिल्ली की मिसाल आईएएस बनने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि डीएम का पद अफसरों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में हालात निराशाजनक ही हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, कुल 716 जिलों में सिर्फ 142 जिलों में डीएम महिलाएं हैं। आबादी के लिहाज से 20 बड़े राज्य हरियाणा (4 फीसदी), छत्तीसगढ़ (7 फीसदी), बिहार (8 फीसदी), गुजरात (9 फीसदी) और मप्र (10 फीसदी) वगैह इस मामले में काफी पीछे हैं। मसलन, हरियाणा के 22 जिलों में सिर्फ एक (हिसार) में महिला डीएम है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध में खासकर चर्चित है। आबादी के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों में दिल्ली (80 फीसदी), केरल (71 फीसदी), पश्चिम बंगाल (39 फीसदी), असम (27 फीसदी) और पंजाब (27 फीसदी) हैं। आंकड़ों के मुताबिक टॉप पांच राज्यों में भी असम और पंजाब 30 फीसदी से कम महिला डीएम हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भाजपा शासित राज्यों का प्रदर्शन गैर-भाजपा राज्यों से बदतर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों में महिला डीएम का औसत प्रतिनिधित्व 14 फीसदी है (कुल 394 जिलों में 57) है, जबकि गैर-एनडीए दलों के राज वाले राज्यों में दोगुना यानी 26 फीसदी है (कुल 302 जिलों में 81)। बेहतर प्रदर्शन वाले केरल और दिल्ली को गैर-एनडीए शासित राज्यों की सूची से हटा लें तब महिला डीएम 22 फीसदी हैं (277 में 62)।

मसलन लगभग सभी एनडीए शासित पूर्वोत्तर के राज्यों में देश में सबसे कम महिला डीएम का प्रतिनिधित्व है। सिक्किम और नागालैंड के क्रमश: 6 और 11 जिलों में एक भी महिला डीएम नहीं हैं। अरुणाचल और त्रिपुरा में क्रमश: 17 फीसदी और 12 फीसदी महिला प्रतिनिधित्व है। मणिपुर, मेघालय और असम में अपने पड़ोसियों से कुछ बेहतर स्थिति

राज्यवार महिला कलेक्टर

राज्य	जिले	महिला कलेक्टर	प्रतिशत
उप्र	75	12	16
बिहार	38	3	8
जम्मू-कश्मीर	20	4	20
हिमाचल प्रदेश	12	2	17
पंजाब	22	6	27
हरियाणा	22	1	4
उत्तराखंड	13	2	15
राजस्थान	33	7	21
मप्र	52	5	10
गुजरात	33	3	9
छत्तीसगढ़	27	2	7
झारखंड	24	5	21
पश्चिम बंगाल	23	9	39
महाराष्ट्र	36	8	22
ओडिशा	30	6	20
तेलंगाना	31	8	26
आंध्र प्रदेश	13	2	15
तमिलनाडु	38	9	24
गोवा	2	1	50
केरल	14	10	71
दिल्ली	11	9	81
कर्नाटक	30	6	20
असम	33	9	27
नागालैंड	11	0	0
मणिपुर	15	3	20
अरुणाचल प्रदेश	23	4	17
मेघालय	10	2	20
त्रिपुरा	8	1	12
सिक्किम	6	0	0
मिजोरम	11	3	27
कुल	**716**	**142**	**19**

है। वहां क्रमश: 20 फीसदी, 20 फीसदी और 27 फीसदी महिला प्रतिनिधित्व है। उप्र और उत्तराखंड जैसे एनडीए-शासित बड़े राज्यों में यह प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औसत से कम 16 फीसदी और 15 फीसदी है। गैर-एनडीए शासित राज्यों में तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाड़, राजस्थान और ओडिशा में महिला डीएम प्रतिनिधित्व क्रमश: 26 फीसदी, 15 फीसदी, 19 फीसदी, 23 फीसदी, 22 फीसदी और 20 फीसदी है।

विश्लेषण के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 तक 47 जिले उग्र वामपंथ से ग्रस्त बताए गए हैं, इनमें सिर्फ 7 जिलों में महिला डीएम हैं। यह आंकड़ा 15 फीसदी बैठता है। जम्मू-कश्मीर में 20 फीसदी (20 जिलों में सिर्फ 4 में) से ज्यादा महिला डीएम नहीं हैं। ये आंकड़े महिला अफसरों की बताई कहानियों से मेल खाते हैं, जिनमें तबादलों और नियुक्ति में भेदभाव का शिकार होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि महिला आफसरों की तादाद 1970 के दशक में 10 फीसदी से कम थी, जो अब बढ़कर करीब 30 फीसदी हो गई है।

अपनी किताब 'एब्रिथिंग यू एवर वांटेड टु नो अबाउट ब्यूरॉक्रेसी बट वर अफ्रेड टु आस्क' में आखिर में पूर्व आईएएस अधिकारी रेणुका विश्वनाथन ने लिखा है कि महिलाओं को जिला कलेक्टर बनाने से इनकार करने का चलन आजादी के बाद शुरुआती दशकों से ही बेहिसाब है। डीएम का दायित्व 24 घंटे का होता है, इसलिए महिलाओं को घर और परिवार की जिम्मदारियों की वजह से उपयुक्त नहीं माना जाता। घर के दायित्व पर जोर उनके वरिष्ठ अधिकारी भी देते हैं। इसके अलावा नेताओं के राजनीतिक हस्तक्षेप और वरिष्ठ लोगों के अहम पद पर जाने की जरूरतें भी महिलाओं के आड़े आती हैं। मसलन, नागालैंड में प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डीएम हैं, वहां कोई महिला डीएम नहीं है (आईएएस के मुकाबले प्रादेशिक सेवा के अधिकारियों के नेताओं से बेहतर ताल्लुकात होते हैं)। लिहाजा, महिलाएं उन्हीं पदों तक सीमित रहती हैं, जिसमें 9-टू-5 की सेवा होती है या मजाक में जिसे 'रेगुलर' जीवन-शैली कहा जाता है। ऐसे पदों पर सचिवालय में डेस्क पर ज्यादा समय देना होता है और धूल भरी सड़कों की खाक नहीं छाननी पड़ती और इस तरह शुरुआत से ही उनके कैरियर में ऊंचे सरकारी पदों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डीएम की नियुक्ति के स्तर पर ही भेदभाव का शिकार महिलाओं के लिए आश्चर्य नहीं कि ऊंचे सरकारी पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। इंडिया स्पेंड के 3 जनवरी 2022 तक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि केंद्र में कुल 92 सचिवों में (13) महिलाएं सिर्फ 14 फीसदी ही थीं और मुख्य सचिव तो महज दो थीं। सबसे बढ़कर यह कि आज तक कोई महिला कैबिनेट, गृह या रक्षा सचिव नहीं बनी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मप्र में वर्तमान में ये 5 महिला आईएएस हैं कलेक्टर

मप्र की बात करें तो यहां के 52 जिलों में से मात्र 5 जिलों में ही वर्तमान समय में महिला आईएएस कलेक्टर के पद पर हैं। खरगौन जिले में 2011 बैच की आईएएस अधिकारी अनुग्रह पी कलेक्टर हैं। वहीं अशोकनगर में 2000 बैच की उमा माहेश्वरी को कलेक्टर बनाया गया है। शहडोल जिले में कलेक्टर की कमान 2008 बैच की आईएएस अधिकारी वंदना वैध को दी गई है। वहीं अनूपपुर जिले में 2013 बैच की आईएएस अधिकारी सोनिया मीणा को कलेक्टर बनाया गया है, जबकि मंडला जिले में 2012 बैच की महिला आईएएस हर्षिका सिंह कलेक्टर के पद पर हैं।

अचल संपत्ति छिपाने वाले वरिष्ठ पदों के एम्पैनलमेंट में नहीं होंगे शामिल

वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) को लेकर आईएएस व आईपीएस सहित दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने चेताया है। आयोग का कहना है कि अगर ये अधिकारी तय समय पर अपनी एआईपीआर जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें भारत सरकार में वरिष्ठ पदों के पैनल यानी एम्पैनलमेंट में शामिल होने के लिए सीवीसी की मंजूरी नहीं मिलेगी। चूंकि सतर्कता मंजूरी के लिए एआईपीआर को समय पर दाखिल करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है, इसलिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वे सभी अधिकारी, जिनके लिए आयोग से सतर्कता इनपुट मांगा गया है, उनकी एआईपीआर तय समय पर जमा हो जाए। अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारियों को हर साल 31 जनवरी तक एआईपीआर जमा करानी होती है। देखने में आया है कि बहुत से अधिकारी निर्धारित तिथि पर एआईपीआर जमा नहीं कराते। इससे दिक्कत यह होती है कि अगर ऐसे किसी अधिकारी का नाम भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में शामिल करने के लिए सीवीसी के पास भेजा जाता है तो संबंधित अधिकारी की एआईपीआर नहीं मिलती। इससे सीवीसी, डीओपीटी और संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पत्राचार शुरू होता है। इस प्रक्रिया के चलते बाकी अधिकारियों की मनोनयन एम्पैनलमेंट सूची जारी होने में भी देरी हो जाती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 27 सितंबर 2011 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/2007-एस्टेब्लिशमेंट ए, जारी किया गया था। उसमें लिखा है कि केंद्रीय सिविल सेवा/पदों पर कार्यरत सदस्यों को, वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी जमा करानी अनिवार्य है। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें सीवीसी की मंजूरी नहीं मिलेगी। अब गत सप्ताह सीवीसी ने दोबारा से आदेश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर एआईपीआर जमा करानी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं होगा। सीवीसी, एक अधिकारी को सतर्कता मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, यदि वह पिछले वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न अगले वर्ष की 31 जनवरी तक जमा करने में विफल रहता है। एआईएस (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2) के अनुसार, अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग यह रिपोर्ट जमा करने में विफल रहते हैं, उन्हें सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा। सतर्कता मंजूरी प्रदान करने के लिए समय पर एआईपीआर दाखिल करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है।

साइबर ठगी बनी नासूर

मप्र में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों से महिला अपराध को लेकर कई चौका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। विधानसभा में पेश जवाब में सरकार ने कहा है कि 2018 से अब तक 55 करोड़ 48 लाख 93 हजार से ज्यादा राशि का आर्थिक अपराध साइबर क्राइम के माध्यम से हुआ। पुलिस ने अपराधियों से 6 करोड़ 80 लाख 22 हजार रुपए की राशि वसूली है। प्रदेश में साइबर क्राइम के बीते 5 साल में 3365 मामले दर्ज हुए हैं, इनमें से 1212 प्रकरण लंबित हैं।

इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़े हैं। मप्र में वर्ष 2021 में साइबर अपराधियों द्वारा किए गए बैंकिंग धोखाधड़ी के 576 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2.37 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों में मप्र देशभर में 12 स्थान पर है। सबसे अधिक 19,671 मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए, जबकि तमिलनाडु में ये आंकड़ा 5292 था। दिल्ली में बैंकिंग धोखाधड़ी में 5001 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2021 में देशभर में दर्ज 50,242 मामलों में कुल 167.03 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। यहां बता दें, कोरोनाकाल यानी वर्ष 2019 और 2020 में लगे लॉकडाउन में साइबर ठग सबसे अधिक सक्रिय रहे। मप्र में ही वर्ष 2019 में 865 लोगों से कुल 2.62 करोड़ और वर्ष 2020 में 979 लोगों से 3.48 करोड़ रुपए की ठगी की गई।

गौरतलब है कि साइबर क्राइम में संगठित गिरोह सक्रिय हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत बिहार और झारखंड से अपराधी साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 से 2021 तक मप्र में कुल 2632 लोग बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार हुए और इनसे 9.19 करोड़ रुपए की राशि ठगी गई। ये अपराध वे हैं, जो राज्य साइबर सेल और जिलों की साइबर सेल में दर्ज हुए हैं। राज्य साइबर सेल के मुताबिक वर्ष 2015 से 2021 तक दर्ज 81 फीसदी मामलों में चालान पेश किया गया है। वहीं वर्ष 2021 में सभी प्रकार के 163 साइबर अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 60 में चालान पेश किया गया है। राज्य साइबर सेल में दर्ज सभी प्रकार के साइबर अपराधों में से 81 फीसदी में चालान पेश करने की बात कही जा रही है। एसपी वैभव श्रीवास्तव के मुताबिक वर्ष 2020 से 2021 तक राज्य साइबर सेल में दर्ज मामलो में से 19 फीसदी की जांच जारी है। यहां बता दें, साइबर अपराधी अन्य राज्यों में बैठकर ठगी को अंजाम देते हैं। इसके लिए फर्जी नामों से ली गई मोबाइल सिम का उपयोग किया जाता है। इसी तरह ठगी गई रकम उन बैंक खातों में जमा की जाती है, जो ऐसे लोगों के नाम पर होते हैं, जिन्हें इसकी जानकारी तक नहीं होती। जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से उनके दस्तावेज लेकर मोबाइल सिम लेने के अलावा बैंक खाते खोले जाते हैं।

पिछले दो महीनों में अकेले शहरों में साइबर अपराध के 600 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो इस तरह के मामले दर्ज भी नहीं करवाते हैं। वहीं, मप्र में साल 2021 में साइबर अपराध के कुल 3600 मामले दर्ज हुए थे। इस साल दो महीने में ही यह आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। पिछले साल जो मामले दर्ज हुए थे, इसमें साइबर अपराध, सेक्सटॉर्शन, सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड तस्वीरें शेयर करना, अश्लील टिप्पणियां और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हैं। वहीं, पिछले दो महीनों के दौरान ऐसे मामलों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2021 में दर्ज कुल साइबर अपराधों की शिकायत में 25 फीसदी मामले महिलाओं के खिलाफ थे। इस साल बढ़त का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2022 के पहले 2 महीनों में ही संख्या बढ़कर 32 फीसदी हो गई है। 3 फीसदी मामले अलग-अलग क्षेत्रों के हैं। सबसे ज्यादा मामले वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। 2 महीने में जो मामले दर्ज हुए हैं। उनमें 65 फीसदी शिकायतें ऑनलाइन धोखाधड़ी की है।

मप्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह केवल आधिकारिक पुलिस डेटा है, जिसमें पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क करने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी की राशि कम होती है, रिपोर्ट भी नहीं की जाती है। ऐसे में राज्य की वास्तविक स्थिति बहुत गंभीर है। पुलिस के अनुसार पिछले साल साइबर सेल ने मप्र निवासियों को ऑनलाइन ठगने के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों सहित 170 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। 2021 के दौरान साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को लगभग एक करोड़ रुपए वापस किए गए, जबकि 25 लाख रुपए जालसाजों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए।

● **बृजेश साहू**

मप्र की साइबर पुलिस है देश में नंबर वन

मप्र पुलिस ने प्रदेश को गर्व करने का मौका दिया है। दरअसल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मप्र पुलिस को पूरे देश में नंबर वन माना गया है। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए मप्र को पहला नंबर दिया है। इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट के खुलासे के लिए मप्र साइबर पुलिस को सबसे बेहतरीन माना गया है। बता दें कि देशभर में साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर का गठन किया था। इसी सेंटर ने बीते दिनों एक दिवसीय ऑनलाइन समिट में सभी राज्यों से दो-दो केस स्टडी साझा करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद सभी केस स्टडी को देखने के बाद साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर ने मप्र की साइबर पुलिस को इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट का खुलासा करने के लिए देश में सबसे बेहतरीन माना है। कर्नाटक को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि साइबर क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए मप्र की साइबर क्राइम पुलिस भी तैयारियों में जुटी है। बता दें कि मप्र साइबर क्राइम पुलिस साइबर ठगों से जुड़ी हर जानकारी का डाटाबेस तैयार कर रही है। इसमें आरोपितों द्वारा की गई वारदात का तरीका और उनकी व्यक्तिगत जानकारी का ब्यौरा शामिल किया जा रहा है।

मप्र का किसान होगा मालामाल

रूस और यूक्रेन के मध्य भयानक युद्ध के बीच मप्र के किसानों की किस्मत चमकने जा रही है। इसकी वजह यह है कि मप्र का गेंहू विदेशों में बिकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में देश के बड़े गेंहू एक्सपोर्टर्स से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक्सपोर्टर्स के लिए कई तरह की सुविधाएं देने की घोषणा की। माना जा रहा है कि सरकार की इस नीति से प्रदेश के किसान मालामाल होंगे।

आज मप्र देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य बन गया है। इस साल प्रदेश में करीब 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उपज होने की संभावना है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में देश के बड़े गेंहू एक्सपोर्टर्स से मुलाकात की। बैठक में बताया गया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में गेहूं की भारी कमी पैदा हुई है। इसी कड़ी में विदेशों में गेहूं की मांग बढ़ गई है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गेहूं की विदेशों में एक्सपोर्ट करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री शिवराज का कहना है कि मप्र का गेहूं विदेशों में एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्टर्स को सरकार सारी सुविधाएं देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र के एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी शुल्क नहीं लेंगे। एपीडा के भोपाल स्थित कार्यालय में एक्सपोर्ट सेल बनाया जाएगा। एमपी में एक लायसेंस पर कंपनी या व्यापारी या मंडी से बाहर खरीदी कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र गेहूं के उत्पादन का केंद्र है। हम पिछले दो सालों से 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रिक्योर कर रहे हैं। मप्र के पास गेहूं के भंडार हैं। अगली फसल भी जबरदस्त आ रही है। अब हम मप्र का गेहूं एक्सपोर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा की। इस दौरान एक्सपोर्ट कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उधर सरकार का साथ, मौसम की मेहरबानी और किसानों की मेहनत के कारण इस बार प्रदेश में गेहूं की बंपर फसल होने वाली है। गेहूं की फसल को देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार इस बार प्रदेश में लगभग 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जिससे किसानों को करीब 2800 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरूरत होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना निर्यात कर सकते हैं, इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मप्र के किसानों को फायदा होगा। इस बार भी सरकार की कृषि नीतियों और प्रदेश के किसानों की मेहनत के बल पर बंपर फसल आ रही है। मप्र के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मप्र के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। मप्र व्हीट के नाम से इसकी पूरे देश में साख है। कई कंपनियां आटा बनाकर बेचती हैं तो उसे भी मप्र व्हीट के नाम से बेचा जाता है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी जबरदस्त आ रही है। बम्पर फसल की वजह से गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था। पर अब गेहूं मप्र की ताकत होगा। हम दुनियाभर में गेहूं को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए एक्सपोर्टर्स से बातचीत भी की गई है। हमने उनकी समस्याओं को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश की।

प्रदेश में गेहूं के बम्पर उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए एक्सपोर्टर्स को हरसंभव सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी कड़ी में एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लेने और एक्सपोर्टर्स को ग्रेडिंग व सॉर्टिंग पर होने वाले खर्च का भुगतान करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। वह चाहे मंडी से खरीदे या मंडी के बाहर से। वह किसान के घर या खेत से भी खरीदारी कर सकती है। मंडी में बिकने वाले गेहूं की वैरायटी और ग्रेड का भी उल्लेख होता है। हमने तय किया है कि मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुज्ञा का लाभ एक्सपोर्टर स्वयं या अपने किसी स्थानीय व्यापारी के पंजीयन से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल के वैल्यू एडिशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब उपलब्ध कराई जाएगी।

● **राकेश ग्रोवर**

नान के पास है 37 लाख टन गेहूं

मप्र नागरिक आपूर्ति निगम के पास पिछले सालों में खरीदा गया 37 लाख टन गेहूं गोदामों में रखा है। जिसमें से 2 लाख टन गेहूं बेचने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 5 लाख टन गेहूं को बेचने के टेंडर हो चुके हैं। जबकि 30 लाख टन गेहूं को बेचने की जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात यह है कि नान को गेहूं की कीमत 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिली है। जो कि अब तक की सबसे बेहतर कीमत है। नान के पास वह गेहूं बचा है जो चमकविहीन है और उसे पिछले दो साल से भारतीय खाद्य निगम ने नहीं उठाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि वैश्विक मांग को देखते हुए मप्र के गेहूं को ग्लोबल पहचान मिले। इस बार मप्र सरकार ने 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उर्पाजन की तैयारी की है। हालांकि फिलहाल बाजार में किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहे हैं। वैश्विक मांग को देखते हुए इस बार खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से ज्यादा रहने की संभावना है। ऐसे में सरकारी एजेंसियों को इस बार उपार्जन से राहत मिल सकती है। प्रदेश के अन्नदाताओं के सर्वांगीण विकास और खुशहाली के लिए राज्य की योजनाएं भी भलीभांति फलीभूत हो रही हैं।

सिंचाई परियोजनाएं अधूरी

मप्र-गुजरात के बीच नर्मदा जल संधि को लेकर पानी के बंटवारे का अनुबंध 2024 में खत्म हो रहा है। मप्र को अपने हिस्से का पानी वर्ष 2024 से पहले लेना है। जिसके लिए प्रदेश में तेजी से नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी सहित इंदौर जिले में 13 नहर परियोजनाएं प्रस्तावित, निर्माणाधीन हैं। अफसरों की लापरवाही के चलते कार्य की गति कछुआ चाल है, जिससे इन परियोजनाओं का वर्ष 2024 से पहले पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है। जबकि इन परियोजनाओं को हर हाल में दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री भारी नाराजगी भी जता चुके हैं।

नर्मदा जल पर अपने अधिकार को कायम रखने के लिए नर्मदा पर बने बांधों से सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। वर्तमान में कुल 17 नहर परियोजनाएं निर्माणाधीन व प्रस्तावित हैं। इन 17 नहर परियोजनाओं से प्रदेश का कुल 2.60 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचित होगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3252 करोड़ रुपए है। सभी 17 परियोजनाओं का काम दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 13 नहर परियोजनाएं इंदिरा सागर बांध से संबंधित है। इंदिरा सागर बांध की 5 परियोजनाओं का काम तो मार्च 2022 में ही पूरा होना था, लेकिन काम की गति धीमी होने से अब तक ये परियोजनाएं अधूरी हैं। जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल बैठक में नाराजगी भी जताई थी। साथ ही एनवीडीए अधिकारियों को साफ चेतावनी दी थी कि सभी नहर परियोजनाएं समय सीमा में पूरी कर ली जाएं।

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1979 में नर्मदा के जल का बंटवारा किया था। जिसमें सालभर में बहने वाले नर्मदा के पानी की मात्रा 28 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) मानते हुए 9 एमएएफ गुजरात को, 0.50 एमएफ राजस्थान, 0.25 एमएएफ महाराष्ट्र और बाकी 18.25 एमएएफ मप्र को आवंटित किया है। गुजरात में एक ही बांध सरदार सरोवर नर्मदा पर बने होने के कारण वहां की जल भंडारण क्षमता 4.75 एमएएफ है। इसलिए गुजरात के हिस्से का पानी इंदिरा सागर में सुरक्षित रखा जाता है, जिसे गुजरात की मांग पर समय-समय पर छोड़ा जाता है। जल न्यायाधिकरण के समझौते के अनुसार 2024 के बाद गुजरात अपने हिस्से का पानी मप्र को नहीं लेने देगा। वर्तमान में विभिन्न नहर परियोजनाओं से मप्र 14.55 एमएएफ पानी ही ले पा रहा है।

एनवीडीए की इंदिरा सागर बांध से 6 नहर परियोजनाएं मार्च 2022 तक पूरी होनी थी। जिसमें खंडवा, खरगोन की 5 परियोजनाएं, भुरलाय, कोदवार, पुनासा विस्तार, छैगांवमाखन, बिस्टान और अलीराजपुर सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना है। इसमें छैगांवमाखन और पुनासा विस्तार योजना का काम अंतिम चरण में है। काम की गति इतनी धीमी है कि इसके अप्रैल तक पूरा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

खंडवा जिले में चल रही नहर परियोजनाओं में किल्लौद, जावर उद्वहन सिंचाई योजना का काम भी कछुआ गति से चल रहा है। झिरनिया, पामाखेड़ी नहर परियोजना का काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसके टेंडर बुलाना बाकी है। उल्लेखनीय है कि दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान द्वारा ये सभी परियोजनाओं को स्वीकृत कराया गया था और अपने कार्यकाल के दौरान इनका भूमिपूजन भी किया गया था। झिरनिया सिंचाई का भूमिपूजन करने तो स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार अभी तक जो परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उनमें 10 हजार हेक्टेयर की किल्लौद परियोजना है, जिसकी लागत 140.57 करोड़ है। वहीं 1060 हेक्टेयर की पामाखेड़ी परियोजना जिसकी लागत 22.69 करोड़, 4 हजार हेक्टेयर की सिमरोल (इंदौर) जिसकी लागत 59.13 करोड़, 4 हजार हेक्टेयर कीही चौड़ी जगानिया जिसकी लागत 68.36 करोड़, 9 हजार हेक्टेयर की बलकवाड़ा परियोजना जिसकी लागत 123.69 करोड़ है। वहीं 26 हजार हेक्टेयर की जावर परियोजना की लागत 466.91 करोड़ और 47 हजार हेक्टेयर की नागलवाड़ी परियोजना की लागत 1173.03 करोड़ रुपए है।

इंदिरा सागर नहर परियोजना के चीफ इंजीनियर एमएस अजनारे का कहना है कि पुनासा विस्तार और छैगांवमाखन परियोजना का काम पूरा हो चुका है। इनकी टेस्टिंग की जा रही है। पामाखेड़ी और झिरनिया परियोजना के टेंडर बुलाए जा रहे हैं। सभी परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

दरकते और रिसते बांधों ने बढ़ाई चिंता

बुंदेलखंड के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के बॉर्डर पर बने बान सुजारा बांध के छह गेट और गैलरी में बड़ा लीकेज हो गया है। इससे दोनों जिलों के 52 गांवों के ऊपर तबाही का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, प्रदेश में करीब आधा सैकड़ा बांध ऐसे हैं जो पुराने होने के कारण जर्जर स्थिति में आ गए हैं। दरकते और रिसते बांधों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जल संसाधन विभाग ने 27 ऐसे बांधों को चिन्हित किया है, जिनकी मरम्मत जरूरी है। जल संसाधन विभाग जल्द की निविदा आमंत्रित करके काम शुरू कराएगा। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार श्योपुर जिले में वर्ष 1908 में निर्मित वीरपुर, वर्ष 1910 में सिवनी जिले में निर्मित रुमल और 1913 में धार जिले में बने माही सहित प्रदेश के 27 बांधों की सरकार मरम्मत कराएगी। इन बांधों की दीवार में कहीं-कहीं दरार आ चुकी हैं या कहीं-कहीं मिट्टी धंस रही है। मरम्मत कार्य के लिए सरकार ने 551 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

बंगले को न्यारा बनाने की होड़!

कोरोना महामारी से बदहाल हुई अर्थव्यवस्था और प्रदेश पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद माननीय अपने बंगलों की साज-सज्जा में करोड़ों खर्च करने के लिए तत्पर हैं। प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और अफसरों ने अपने सरकारी बंगलों की साज-सज्जा और मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि वित्त विभाग ने फिलहाल माननीयों की मंशा पर पानी फेर दिया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद बंगले बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पूर्व में जिन बंगलों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं दोबारा फिर से उन बंगलों पर लाखों रुपए साज-सज्जा के नाम पर स्वाहा होने लगते हैं। 23 मार्च 2020 के बाद जब प्रदेश में वर्तमान सरकार शुरू हुई, तबसे एक बार फिर सरकारी बंगलों पर पानी की तरह पैसा बहाया जाने लगा। जैसे-जैसे मंत्री बनते गए, वैसे-वैसे बंगले आवंटित होते गए और उन बंगलों के साज-सज्जा पर लाखों रुपए खर्च होने लगे। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 15 माह के कार्यकाल में मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे।

वर्तमान सरकार में अभी जितने मंत्री हैं, उनके बंगलों पर पिछले दो साल से लगातार साज-सज्जा के काम हो रहे हैं और लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसके बावजूद मंत्री संतुष्ट नहीं हैं और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से अपने बंगले को न्यारा बनाने के लिए लाखों रुपए के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा रहे हैं। 74 बंगला स्थित सी-2 में निवासरस प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले में सिविल एवं विद्युतीय निर्माण कार्य के लिए 36.67 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। जबकि पूर्व में इनके बंगले पर 18,75,175 रुपए खर्च किए गए हैं। यहां यह बता दें कि यह वही बंगला है जिसमें कांग्रेस शासनकाल के दौरान लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रहते थे। उन्होंने इस बंगले पर सबसे अधिक खर्च भी किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब इस बंगले में ऐसा कौनसा काम बाकी है, जिस पर 36 लाख रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी हो रही है।

वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के शासकीय आवास 74 बंगला स्थित सी-12 में सिविल एवं विद्युतीय लघुमूल कार्य के लिए 97.55 लाख का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। गौरतलब है कि सारंग लगभग एक दशक से इस बंगले में रह रहे हैं और पूर्व में भी इस बंगले पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसे ही अन्य कई मंत्री और विधायक हैं जिनके बंगलों पर निर्माण के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।

वित्तमंत्री के प्रस्ताव को उनके ही विभाग ने लौटाया

प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी

कमजोर है। प्रदेश में राजस्व संग्रहण सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद सादा जीवन और उच्च विचार की बात कहने वाले मंत्रीजी ने अपने बंगले की साज-सज्जा के लिए लाखों रुपए का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग से बनवाकर वित्त विभाग को भिजवाया है। लेकिन मंत्रीजी के प्रस्ताव को उनके ही विभाग ने वापस लौटाकर उन्हें आईना दिखाया है।

हालांकि वित्त विभाग ने फिलहाल इन प्रस्तावों को होल्ड कर रखा है। उल्लेखनीय है कि भवन कार्य हेतु 381.61 लाख रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, जिसमें सबसे अधिक 97.55 लाख रुपए का प्रस्ताव विश्वास सारंग के बंगले का है।

गौरतलब है कि 2021 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि शिवराज सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में मंत्रियों के बंगले सजाने में 4.58 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए थे। सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री निवास पर खर्च हुए थे, तो 56 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले की साज-सज्जा में लगे थे।

गौरतलब है कि एक साल पहले विधानसभा में विधायक पांचीलाल मेड़ा के प्रश्न के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री भार्गव ने जो जानकारी दी थी उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के बंगलों की साज-सज्जा में 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक हुए खर्च का ब्यौरा दिया था। मुख्यमंत्री निवास में बिजली के काम में 81 लाख से ज्यादा खर्च किए गए, साथ ही 18.52 लाख का सिविल वर्क हुआ था। मुख्यमंत्री के 74 बंगला स्थित एक अन्य घर में बी-8 में 13.41 लाख का काम हुआ था। वहीं सिविल वर्क में मुख्यमंत्री के बंगले से ज्यादा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पर 44 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ था। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह 31 लाख, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे प्रभुराम चौधरी के आवास पर 27 लाख से ज्यादा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया 19 लाख और सिंधिया समर्थक परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आवास पर 18 लाख खर्च हुए थे। इस लिस्ट के हिसाब से सबसे कम सिविल वर्क का काम खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और इमरती देवी के आवास पर हुआ था। इसके बाद भी कई मंत्रियों के बंगलों पर लाखों रुपए के काम हुए हैं। लेकिन इससे अभी मंत्रियों का मन नहीं भरा है। जनता से मिलने वाले टैक्स को मंत्री अपने आराम के लिए पानी की तरह बहा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को साफ-साफ शब्दों में निर्देशित किया है कि फिजूल के खर्चे न किए जाएं।

● **अरविंद नारद**

धधकते जंगल... झुलसता जीवन

आज जंगलों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है। लिहाजा मिट्टी में गर्मी, ओजोन परत की कमी आदि में वृद्धि हुई है। हमारी विकास प्रक्रिया ने हजारों लोगों को पानी, जंगल और भूमि से विस्थापित कर दिया है। ऐसे में जंगल की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बल्कि हमारा धर्म भी होना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले 12 वर्षों में जंगल में आग लगने की 13 हजार से अधिक घटनाएं सामने आई हैं और इनमें हर साल औसतन 1978 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन संपदा जलकर राख हो रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार जंगल की आग को बुझाने के लिए केवल समय से बारिश का होना ही एकमात्र कारगर विकल्प है।

जंगल में आग लगने की एक वजह मानव जनित भी है। कई बार ग्रामीण जंगल में जमीन पर गिरी पत्तियों या सूखी घास में आग लगा देते हैं, ताकि उसकी जगह नई घास उग सके। लेकिन आग इस प्रकार फैल जाती है कि वन संपदा को खासा नुकसान होता है। दूसरा कारण चीड़ की पत्तियों में आग का भड़कना भी है। चीड़ की पत्तियां (पिरुल) और छाल से निकलने वाला रसायन, रेजिन बेहद ज्वलनशील होता है। जरा-सी चिंगारी लगते ही आग भड़क जाती है और विकराल रूप ले लेती है। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी मामूली बात लगती है, लेकिन जंगलों के सूखे पत्तों के लिए यह महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, पेड़ों और पत्तियों में से पानी की मात्रा कम होती जाएगी और ये ईंधन का काम करेंगे। सूखी पत्तियों की रगड़ से आग का लगना और फैलना तेजी से होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वनाग्नि से हुई वार्षिक वन हानि 440 करोड़ रुपए आंकी है। जंगलों में लगी आग से कई जानवर बेघर हो जाते हैं और नए स्थान की तलाश में वे शहरों की ओर आते हैं। वनों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में भी भारी कमी आती है और उन्हें वापस प्राप्त करने में भी लंबा समय लगता है।

वनाग्नि के परिणामस्वरूप मिट्टी की ऊपरी परत में रसायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण भूजल स्तर भी प्रभावित होता है। इससे आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों की आजीविका को भी नुकसान पहुंचता है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग तीन करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों के संग्रह पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वनों में लगी आग को बुझाने के लिए काफी अधिक आर्थिक और मानवीय संसाधनों की जरूरत होती है, जिस कारण सरकार को काफी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। वनाग्नि से वनों पर आधारित उद्योगों एवं रोजगार की हानि होती है और कई लोगों की आजीविका का साधन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इसके अलावा वनों पर आधारित पर्यटन उद्योग को भी खासा नुकसान होता है। वनाग्नि से जलवायु भी प्रभावित होती है। इससे कार्बन डाईआक्साइड तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसों का काफी अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। इसके अलावा वनाग्नि से वे पेड़-पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड को समाप्त करने का कार्य करते हैं।

वर्तमान में अतिशय मानवीय अतिक्रमण ने वनों में लगने वाली आग की बारंबारता को बढ़ाया है। पशुओं को चराना, झूम खेती, बिजली के तारों का वनों से होकर गुजरना आदि ने इन घटनाओं में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, सरकारी स्तर पर वन संसाधन एवं वनाग्नि के प्रबंधन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव इसका प्रमुख कारण है। अव्यावहारिक वन कानूनों ने वनोपज पर स्थानीय निवासियों के नैसर्गिक अधिकारों को खत्म कर दिया है, लिहाजा ग्रामीणों और वनों के बीच की दूरी बढ़ी है। कुछ समय पूर्व खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञों के दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भारत में जंगल की आग की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्थिक और पारिस्थितिकी के नजरिए से जंगल की आग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न ही क्षेत्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना है। जंगल की आग पर आंकड़े बहुत सीमित हैं, साथ ही वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसके अलावा, आग की भविष्यवाणी करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है तथा इसके खतरे के अनुमान, आग से बचाव और उसकी जानकारी के उपाय भी उपलब्ध नहीं हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि वनों में लगी आग से उन क्षेत्र विशेषों का भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है। अत: इन घटनाओं को न्यूनतम किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन के समुचित उपायों के साथ-साथ आग के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्र एवं मौसम में वनों में मानवीय क्रियाकलापों को बंद या न्यूनतम किया जाना चाहिए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिकतम तकनीकों से युक्त संसाधनों के साथ पर्याप्त आपदा प्रबंधन बल की तैनाती की जानी चाहिए।

● **जितेंद्र तिवारी**

देशभर में काटे गए 30 लाख से ज्यादा पेड़

लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत 30,97,721 पेड़ काटे गए और 2020-21 में इसके बदले वनीकरण पर 359 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यादव ने एक लिखित बयान में कहा, पेड़ काटने की अनुमति संबंधित राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा विभिन्न अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और अदालतों के निर्देशों के प्रावधानों के तहत दी जाती है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत 2020-21 के दौरान 30,97,721 पेड़ों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत डायवर्जन प्रस्तावों को मंजूरी एक सतत् प्रक्रिया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैर-वानिकी उपयोग के लिए स्वीकृत वन क्षेत्रों के बदले प्रतिपूरक वनरोपण करना जरूरी है। मंत्री ने सदन को बताया कि 2020-21 में 30.97 लाख पेड़ काटे गए, उस वर्ष के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के हिस्से के रूप में 3.6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे, जिसके लिए सरकार ने 358.87 करोड़ रुपए खर्च किए।

अब निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इन पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

प्रदेश सरकार की नई नीति के अनुसार टोल नाकों पर जिन वाहनों को टोल टैक्स से छूट रहेगी, उनमें भारत सरकार और मप्र सरकार के समस्त यानी जो सरकारी ड्यूटी पर हों, संसद तथा विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के गैर व्यवसायिक यान, ऐसे समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक और तार विभाग के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली, ऑटो रिक्शा, दुपहिया वाहन, बैलगाड़ियां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि को टोल से छूट प्रदान की जाएगी। अभी तक 25 श्रेणियों से प्रदेश में टोल टैक्स नहीं वसूला जाता था, उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसद, जज-मजिस्ट्रेट, बड़े-बड़े अधिकारी, रक्षा पुलिस, फायर, फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन, मजिस्ट्रेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, विभिन्न विभागों के सचिव, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल थे। इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा छूट दी जाती है।

मप्र में अब निजी उपयोग में आने वाले यात्री वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। यह सुविधा राज्य सड़क विकास निगम की नई सड़कों पर उपलब्ध होगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने टोल टैक्स से संबंधित नीति में नए प्रावधान किए हैं। वास्तव में, अब एकत्र किए गए टोल का 80 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों से आता है। वहीं, निजी इस्तेमाल में आने वाले वाहनों पर टोल टैक्स कम और परेशानी ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य में अधिकांश प्रमुख सड़कों का निर्माण राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) पद्धति पर किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने इसके मद्देनजर नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर विभाग ने यह प्रावधान किया है। तय किया गया है कि अब चाहे बीओटी (जो एजेंसी सड़क बनाती है, टोल लेती है और निश्चित अवधि के बाद सरकार को सौंप देती है) की सड़क हो या फिर एन्यूटी पद्धति (इस एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण करने के बाद उसे समान किश्तों में लागत राशि दी जाती है) पर बनने वाली सड़क हो, इन पर निजी उपयोग में आने वाले यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई का कहना है कि अब टोल टैक्स लगाने के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स नहीं लेने का प्रावधान शामिल रहेगा। पूर्व में कुछ सड़कों के प्रस्ताव पुराने प्रावधान अनुसार कैबिनेट में चले गए थे और स्वीकृति भी मिल गई थी, उन्हें भी संशोधन के लिए प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग की ओर से 200 सड़कों का सर्वे किया गया। यह बात सामने आई कि एकत्र किए गए टोल टैक्स का 80 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों का है। निजी छोटे वाहनों पर सिर्फ 20 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, यात्रियों को ज्यादा परेशानी होती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है तो यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का अधिक नुकसान नहीं होगा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसे देखते हुए विभाग ने यह प्रावधान किया है। यह तय किया गया है कि सड़क बीओटी है (एजेंसी सड़क बनाती है, टोल लेती है और एक निश्चित अवधि के बाद इसे सरकार को सौंपती है) या वार्षिकी प्रणाली (एजेंसी द्वारा सड़क के निर्माण के बाद, समान किश्तों में लागत राशि दी गई)। इन सड़कों पर निजी इस्तेमाल के लिए यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार अब टोल टैक्स लगाने के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स नहीं वसूलने का प्रावधान शामिल नहीं किया जाएगा। पहले कुछ सड़कों के **प्रस्ताव पुराने प्रावधान** के अनुसार कैबिनेट में गए थे और उन्हें मंजूरी भी मिली थी लेकिन अब उन्हें संशोधन के लिए पेश करने की तैयारी की जा रही है।

ऐसे सभी वाहन जिनका इस्तेमाल बतौर कमर्शियल वाहन नहीं होता है, वो टोल टैक्स में रिवायत के दायरे में आते हैं। राज्य के सड़क विकास निगम द्वारा हाल में इस नीति में बदलाव किया है और ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई गई सभी सड़कों पर अब टोल नहीं लगेगा। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट नीति के तहत एजेंसियां सड़क बनाती हैं और इसके लिए टोल वसूलती हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार इन एजेंसियों को आसान किश्तों में सड़क निर्माण की रकम चुकाती है। सरकार इन दोनों तरहों की सड़कों पर निजी वाहन चालकों से टैक्स नहीं वसूलेगी।

मप्र सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव से पहले राज्य की 200 सड़कों का सर्वे पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया था। सर्वे में सामने आया है कि कुल टोल टैक्स का 80 प्रतिशत सिर्फ कमर्शियल वाहनों से आता है, ऐसे में निजी वाहनों का योगदान सिर्फ 20 फीसदी ही है। इस राशि और इसे माफ करने पर जनता को होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले से पहले पीडब्ल्यूडी ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें निजी वाहनों का टोल टैक्स माफ करने की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई। अब मप्र में केवल कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा और निजी चालक बिना टोल चुकाए बूथ से आगे बढ़ सकेंगे। मप्र ने अपने 17 मुख्य सड़कों पर इन लोगों को मुक्त कर दिया है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

राष्ट्रपति के वेतन से भी अधिक...
पेंशन पा रहे कई विधायक

चपरासी से जज तक को सिर्फ एक,
नेताओं को कई पेंशन क्यों?

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता है। लेकिन आज भारत में राजनीति लाभ का धंधा बन गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनता की सेवा करने वाले माननीय राष्ट्रपति के वेतन से भी अधिक पेंशन पा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक दिन का विधायक या सांसद बनने के बाद भी माननीय पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जबकि यही हक एक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को 33 साल की सेवा के बाद मिलता है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र सहित देशभर में लाखों अधिकारी-कर्मचारी नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 'माननीय' पेंशन से ही निहाल हो रहे हैं। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का ऐलान किया है। इससे मप्र सहित देशभर में 'माननीय' की पेंशन पर सवाल उठने लगे हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर माननीयों को पेंशन क्यों दी जा रही है? सवाल वाजिब भी है। एक तरफ देश में करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए मुहाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में रहकर सारी सुख-सुविधाएं भोगने और संपत्ति जुटाने के बाद माननीय जब चुनाव हार जाते हैं या राजनीति से रिटायर हो जाते हैं तब भी उन्हें मोटी पेंशन के साथ ही बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जबकि कहने को जनता मालिक और माननीय सेवक होते हैं।

भारत में सांसद या विधायक रहते वेतन और सुविधाएं मिलने का प्रावधान तो है ही, चुनावी हार या दूसरे कारणों से भूतपूर्व हो जाने पर भी उन्हें पेंशन और कई सुविधाएं आजीवन मिलती हैं। निधन हो जाने के बाद उनके आश्रित को भी आजीवन पारिवारिक पेंशन मिलती है। विश्व के अनेक देशों में जनप्रतिनिधियों को वेतन और सुविधाएं मिलती हैं जिसे निर्धारित करने का अधिकार अलग संस्थाओं को रहता है। इसके लिए उम्र और सेवा की सीमा निर्धारित है। ब्रिटेन जैसे देश में इसके लिए आयोग का गठन किया गया है, किंतु भारत में सांसद व विधायकों की सुविधाओं के संबंध में क्रमशः संसद व विधानसभाएं ही निर्णय लेतीं हैं।

एक से अधिक पेंशन के हकदार

देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं है। यानी, विधायक से यदि कोई सांसद बन जाए तो उसे विधायक की पेंशन के साथ ही लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। इसी तरह राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन-भत्ता और विधायक-सांसद की पेंशन भी मिलती है, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एक ही पेंशन मिलती है। वह भी 33 साल की नौकरी पूरी करने के बाद। वहीं, नेताओं को एक दिन का विधायक या सांसद बनने पर भी पेंशन की पात्रता होती है। यह जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना से मिली है। यह जानकारी हासिल करने के बाद एडवोकेट पूर्वा जैन हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगी। उनकी मांग है कि संविधान के मुताबिक समानता के अधिकार के कानून का पालन हो। जनप्रतिनिधियों की पेंशन के लिए भी शासकीय सेवकों की तरह गाइडलाइन बनाई जाए। कम से कम पांच साल का कार्यकाल अनिवार्य किया जाए। साथ ही वे अंत में जिस पद पर रहे, उसी की पेंशन उन्हें मिले। मंत्री या निगम-मंडल में अन्य सरकारी पदों पर रहते हुए वेतन के साथ पुराने पदों की पेंशन नहीं दी जाए, क्योंकि सरकार ने जहां एक तरफ मार्च 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ही बंद कर दी है। वहीं, लोगों से गैस सब्सिडी तक छोड़ने की अपील की। ऐसे में देश के माननीयों के लिए भी नियम-कायदे बनाए जाना चाहिए। उप्र में विधायकों को पेंशन के साथ भत्ता भी मिलता है।

माननीयों की बंद हो सकती एक से अधिक पेंशन!

विधायक, सांसद एवं मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन मिलने से जुड़े नियम में बदलाव की मांग को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गत दिनों जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ में सुनवाई हुई। मामले में पहले ही केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दे चुकी है। मप्र के संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। विभाग की ओर से मुख्य सचिव के स्थान पर उनका नाम जोड़ने से जुड़ा आवेदन पेश किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। याचिका को लेकर अब तक किसी ने जवाब पेश नहीं किया है। कोर्ट ने पहले ही पूछा है कि जब सभी विभागों में एक व्यक्ति को एक ही पेंशन दी जाती है तो फिर विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को अधिक क्यों दी जाती है। इसके क्या नियम हैं? शासन की ओर से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे हालिया याचिका से अलग मुद्दा मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। एडवोकेट पूर्वा जैन ने बताया, याचिका में मांग है कि जब देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को सिर्फ एक पेंशन मिलती है तो सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन देने का नियम क्यों है? यदि कोई विधायक बाद में सांसद भी बन जाए तो उसे विधायक और सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन-भत्ता और विधायक-सांसद की पेंशन भी मिलती है।

वहीं बिहार में एमएलए या एमएलसी को भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं।

पूर्व विधायकों की पेंशन लाखों में

26 अक्टूबर 2016 में पंजाब में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में संशोधन किया गया था। इसके तहत पूर्व विधायकों को उनके पहले कार्यकाल के लिए पेंशन के रूप में 15 हजार रुपए और इसके बाद अगले हर कार्यकाल के लिए 10 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया। इस रकम में पहले 50 फीसदी डीए मर्ज होगा और उसके बाद बनने वाली कुल रकम में फिर से 234 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह पूर्व विधायकों को काफी फायदा हुआ, क्योंकि इससे 15000 पेंशन में 50 प्रतिशत डीए यानी 7,500 रुपए जुड़ने से 22500 रुपए बने। अब 22,500 में 234 फीसदी डीए यानी 52,650 रुपए और जुड़ने से कुल पेंशन 75,150 रुपए बन जाती है। इसी नियम के चलते कई नेताओं को 5 लाख रुपए तक की पेंशन मिलती थी। अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल 11 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें 5.76 लाख रुपए की पेंशन मिलती थी। हालांकि, उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पेंशन नहीं लेने का ऐलान किया था।

ऐसा ही हाल हरियाणा का भी है। चार साल पहले तक हरियाणा में 262 पूर्व विधायकों को पेंशन मिलती रही है। इसके बाद पेंशन में बढ़ोतरी भी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को लगभग सवा दो लाख रुपए पेंशन मिलती है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव की मासिक पेंशन 2.38 लाख रुपए है। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने हरियाणा सरकार से 2018 में यह जानकारी मांगी थी। पूर्व विधायक चंद्रावती को 2,22,525 रुपए, एलनाबाद के पूर्व विधायक भागीराम 1,91,475 रुपए, शमशेर सिंह सुरजेवाला 1,75,950 रुपए, अशोक अरोड़ा 1,60,425 रुपए, प्रो. सम्पत सिंह 2,14,763 रुपए, हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा

हाथ में कैंची तो है मगर चला नहीं सकते

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा कर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया कि अब राज्य में पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार एमएलए बनने की पेंशन मिलेगी। पूर्व विधायकों को मिलने वाले कई दूसरे भत्तों में भी कटौती करने की बात कही गई है। वहीं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस स्ट्रोक से मुश्किल में पड़ गए हैं। उनके हाथ में कैंची तो है, मगर वे अपनी मर्जी से उसे चला नहीं सकते। मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा के बाद कई दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मान के फैसले की तारीफ की है। चूंकि, हरियाणा, पंजाब से लगता हुआ राज्य है, इसलिए यहां पर उस फैसले की ज्यादा चर्चा सुनाई पड़ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। पूर्व विधायकों सहित खेलों से जुड़े लोग भी आप में शामिल हो रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ रहे लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना था, कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो कई बार विधायक बनने के बाद चुनाव हार गए हैं। उन्हें भी पेंशन मिल रही है। कई विधायक तो ऐसे हैं, जिनकी मासिक पेंशन चार-पांच लाख रुपए से ज्यादा है। अब उन्हें एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। अगर कोई नेता विधायक और सांसद की पेंशन एक साथ ले रहा है, तो उसे केवल एक ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

1,60,425 रुपए, और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के पुत्र चन्द्रमोहन को 1,52,663 रुपए बतौर मासिक पेंशन मिलती है। इनके अलावा धर्मवीर गाबा को 1,52,663 रुपए, खुर्शीद अहमद 1,52,663 रुपए, फूलचंद मुलाना 1,68,188 रुपए, मांगेराम गुप्ता 1,68,188 रुपए, शकुंतला भगवाडिया 1,68,188 रुपए, बलबीरपाल शाह 2,07,000 रुपए, सतबीर कादियान 1,29,375 रुपए, स्वामी अग्निवेश 51,750 रुपए तत्कालीन अवधि के दौरान अब उनका देहांत हो चुका है। शारदा रानी को 1,37,138 रुपए, देवीदास सोनीपत 1,21,613 रुपए, दिल्लू राम कैथल 1,13,850 रुपए, कमला वर्मा 1,13,850 रुपए, निर्मल सिंह अंबाला 1,52,663 रुपए, मोहम्मद इलयास 1,37,138 रुपए और कंवल सिंह हिसार को 1,21,613 रुपए मासिक पेंशन मिलती रही है। इस पेंशन में करीब 200 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। तब प्रदेश में न्यूनतम मासिक पेंशन 51,750 रुपए रही है। 39 पूर्व विधायकों को 90,543 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। इनमें अजय चौटाला भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की विधवा जसमा देवी को दोगुनी पेंशन मिल रही है। खुद पूर्व विधायक होने के नाते जसमा देवी को 51,750 रुपए प्रतिमाह तथा पूर्व मुख्यमंत्री की विधवा होने के नाते 99,619 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मिल रही है।

मप्र में कई सुविधाएं

मप्र में विधायक बने नेता वेतन-भत्ते और दूसरी सुविधाओं के नाम पर 2 लाख 10 हजार रुपए तो पाते ही हैं, हार जाने या दोबारा नहीं चुने जाने पर भी कई सुविधाओं के अलावा बतौर पेंशन वे या उनके आश्रित आजीवन अच्छी-खासी रकम के हकदार हो जाते हैं। मप्र विधानसभा के सेक्शन 6ए के तहत, मप्र में पूर्व विधायकों को हर महीने 20 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। ये सुविधा हर पूर्व विधायक को मिलती है, फिर चाहे उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। उपचुनाव जीतकर कार्यकाल पूरा न कर पाने वालों को भी 20 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलती है। पांच साल से ज्यादा विधायक रहने वालों की पेंशन में हर साल 800 रुपए हर महीने के हिसाब से पेंशन जुड़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर

किस राज्य में विधायकों को कितना वेतन मिल रहा है?

राज्य	एक विधायक का वेतन (रुपए में)
तेलंगाना	2.50 लाख
महाराष्ट्र	2.32 लाख
दिल्ली	2.10 लाख
उप्र	1.87 लाख
उत्तराखंड	1.60 लाख
जम्मू-कश्मीर	1.60 लाख
आंध्र प्रदेश	1.30 लाख
राजस्थान	1.25 लाख
हिमाचल प्रदेश	1.25 लाख
गोवा	1.17 लाख
हरियाणा	1.15 लाख
बिहार	1.14 लाख
पंजाब	1.14 लाख
पश्चिम बंगाल	1.13 लाख
झारखंड	1.11 लाख
छत्तीसगढ़	1.10 लाख
मप्र	1.10 लाख
तमिलनाडु	1.05 लाख
कर्नाटक	98 हजार
सिक्किम	86.5 हजार
केरल	70 हजार
गुजरात	65 हजार
ओडिशा	62 हजार
मेघायल	59 हजार
पुदुचेरी	50 हजार
अरूणाचल प्रदेश	49 हजार
मिजोरम	47 हजार
असम	42 हजार
मणिपुर	37 हजार
नागालैंड	36 हजार
त्रिपुरा	34 हजार

केंद्रीय मंत्री को 2.32 लाख

1 लाख वेतन, 70 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60 हजार कार्यालयीन भत्ता, 2 हजार सत्कार भत्ता।

सांसद को 2.05 लाख

1 लाख रुपए वेतन, 45 हजार रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 2 हजार रुपए रोज कार्यालय भत्ता यानी महीने के 60 हजार।

(इसके अलावा ट्रेन के सेकंड एसी कोच में एक सहायक के साथ राज्य में असीमित और राज्य के बाहर सीमित यात्रा कर सकते हैं।)

कोई दोबारा विधायक बना और उस दौरान जितने साल विधायक रहा, तो 20 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन के अलावा हर साल उसकी पेंशन में 800 रुपए महीने और मिलते हैं, यानी सालाना 9,600 रुपए और उसकी पेंशन में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर उसने दो कार्यकाल पूरे किए हैं, तो उसे 24 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। पूर्व विधायक की मृत्यु की तारीख से उसके पति/पत्नी, या मृतक आश्रित को हर महीने 18 हजार रुपए की फैमिली पेंशन मिलती है। हर साल फैमिली पेंशन में 500 रुपए जुड़ जाते हैं। पूर्व विधायकों को हर महीने 15 हजार रुपए का मेडिकल भत्ता और राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पेंशन के हकदार सभी पूर्व विधायकों को अपनी पति/पत्नी या एक अटेंटडेंट के साथ रेलवे के फर्स्ट एसी या सेकेंड एसी कोच में यात्रा के लिए रेलवे के कूपन मिलते हैं। इस रेलवे कूपन से वे राज्य भर में बिना रोक-टोक कहीं भी यात्रा करने को स्वतंत्र होते हैं। राज्य के बाहर हर फाइनेंशियल ईयर में चार हजार किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त होती है।

मप्र में 1.70 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के बावजूद मप्र सरकार ने मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने का फैसला लिया है। लगभग 43 करोड़ रुपए मंत्रियों के इनकम टैक्स पर राज्य सरकार खर्च करेगी। 1990 में मप्र के विधायकों का मासिक वेतन 1000 था, जो अब 35000 हो गया है। एक आंकड़े के मुताबिक, पिछले वर्षों में विधायकों के वेतन के मुकाबले उनके भत्तों पर साढ़े चार गुना से ज्यादा भुगतान किया गया है। पिछले 5 सालों में 230 विधानसभा सदस्यों के वेतन पर 35.03 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि उन्हें मिलने वाले अलग-अलग भत्तों पर सरकारी खजाने से लगभग 121 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें यात्रा भत्ता के रूप में 38.03 करोड़ रुपए की बड़ी अदायगी शामिल है। मप्र के विधायकों को हर महीने 1.10 लाख रुपए सैलरी, 35 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10 हजार टेलीफोन भत्ता, 10 हजार चिकित्सा भत्ता, 15 हजार अर्दली-ऑपरेटर के, 10 हजार लेखन-डाक भत्ता और उसके बाद पेंशन 35 हजार महीना मिलता है। मप्र शासन की सर्विस कंडिका 6-ख के मुताबिक किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई आश्रित हो, को, धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था, उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए 18,000/- रुपए प्रतिमाह कुटुंब पेंशन दी जाती है।

8 वर्षों में पूर्व सांसदों को 500 करोड़ की पेंशन

बीते 8 सालों में पूर्व सांसदों को पेंशन में करीब पांच सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में यह नियम था कि वही पूर्व सांसद पेंशन के योग्य माना जाएगा जिसने बतौर सांसद 4 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, पर साल 2004 में कांग्रेस नीत संप्रग की सरकार ने संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया था कि यदि कोई एक दिन के लिए भी सांसद बन जाएगा तो वह पेंशन का हकदार होगा और तब से यही हो रहा है। यही नहीं 1954 में लागू किए गए सांसदों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम में अब तक 29 बार मनमाने संशोधन किए जा चुके हैं। एक सांसद को तब भी पेंशन मिलने लगती है, जब उसने एक दिन भी सांसदी संभाली हो। इसमें एक अजब-गजब बात यह है कि सांसदों और विधायकों को दो-दो, तीन-तीन बार पेंशन लेने तक का हक है। मसलन कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में सांसद बना हो या पहले सांसद और बाद में विधायक बना हो, तो उसे दो-दो पेंशन मिलती हैं। इतना ही नहीं, इनके पति, पत्नी या आश्रित को भी परिवार गुजारा भत्ता (फैमिली पेंशन) की सुविधा है। मतलब अगर किसी सांसद या पूर्व सांसद या विधायक या मंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी या आश्रितों को आजीवन आधी पेंशन दी जाती है। इसके अलावा सभी को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। पूर्व सांसदों को किसी एक सहयोगी के साथ ट्रेन में द्वितीय श्रेणी एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा है, जबकि अकेले यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी एसी की सुविधा है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर सनातन धर्म परिषद् के संस्थापक नंदकिशोर मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों से यह अपील की है कि वे इस याचिका के पक्ष में खड़े हों, ताकि इन माननीयों को मिलने वाली इस सुविधा को खत्म किया जा सके और देश का एक बड़ा खर्चा बच सके।

राजस्थान में विधायकों की पेंशन

राजस्थान में यदि किसी विधायक ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे हर महीने 35 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। वहीं अगर कोई दूसरी बार विधायक बनता है और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो इन पांच साल के दौरान हर महीने के हिसाब से 1,600 रुपए और मिलेंगे यानी दो कार्यकाल पूरा करने के बाद उसे हर महीने 43 हजार रुपए मिलने लगेंगे। वहीं 70 वर्ष की उम्र होने पर इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 80 वर्ष का होने पर यह 30 प्रतिशत बढ़ जाएगी। उपचुनाव में जीते विधायकों को उनकी शपथ लेने की तारीख से विधानसभा खत्म होने के पीरियड को 5 साल मानकर पेंशन दी जाएगी। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले यदि किसी विधायक की मौत हो जाती है तो ऐसे में उसके आश्रितों को हर माह वही पेंशन मिलेगी, जो पूर्व विधायक को मिलती है। वहीं, पूर्व विधायक के निधन के बाद उनकी पत्नी या पति को 17,500 रुपए या उन्हें मिली लास्ट पेंशन का 50 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो वह पेंशन के रूप में मिलता है। सभी पूर्व विधायकों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के तहत कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलती है।

इसके अलावा पूर्व विधायकों को दो फ्री पास मिलते हैं। इससे वे और उनके साथ कोई और व्यक्ति राजस्थान की सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक रेल, फ्लाइट या शिप से किसी भी कैटेगरी में यात्रा कर सकते हैं। यदि पूर्व विधायक एक साल में 70 हजार रुपए ही ट्रैवल पर खर्च कर पाते हैं तो ऐसे बचा हुआ पैसा अगले साल के ट्रैवल भत्ते में जुड़ जाएगा। इसके

अलावा भी पूर्व विधायकों को कई और सुविधाएं मिलती हैं।

उप्र में स्थिति

उप्र में 2000 से ज्यादा पूर्व विधायक हैं। उप्र में पूर्व विधायकों को हर महीने 25 हजार रुपए पेंशन मिलती है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायकों की पेंशन में हर साल 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी होती जाती है। यानी 10 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 35 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इसी तरह 15 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 45 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। 20 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 55 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके लोगों, यानी एमएलए और एमएलसी को मिलने वाले पेंशन और सुविधाएं एक ही होती हैं। पूर्व विधायकों को सालाना एक लाख रुपए का रेल कूपन मिलता है, जिसमें से 50 हजार रुपए निजी वाहन के डीजल, पेट्रोल के लिए कैश लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जीवनभर मुफ्त रेलवे पास और मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता है। उप्र में पिछले 9 बार से विधानसभा का चुनाव जीतने वालों में भाजपा के सुरेश खन्ना, सपा के दुर्गा यादव हैं, जबकि आजम खान 10वीं बार जीते हैं। 2016 में अखिलेश यादव सरकार ने उप्र के पूर्व विधायकों की पेंशन को 10 हजार रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह किया था।

हिमाचल में 36 हजार पेंशन

प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जैसे ही विधायक बनने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वह पेंशन के हकदार बन जाते हैं। यहां पर विधायक को एक टर्म यानी 5 साल पूरा होने पर हर महीने 36,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसके बाद एक और टर्म पूरा करने पर विधायक को 5,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन दी जाती है यानी एक साल का एक हजार रुपए ज्यादा मिलता है। प्रदेश में इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स, कौल सिंह ठाकुर और गंगूराम मुसाफिर सहित कई पूर्व विधायक हैं

जिन्हें अधिक पेंशन मिलती है। विधानसभा से जुटाई गई जानकारी के अनुसार विधायकों को पेंशन बेसिक टर्म 65,000 रुपए डीए के साथ मिलता है। वहीं झारखंड में एक टर्म के विधायक को 40 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि निर्धारित है। एक बार 40 हजार रुपए का पेंशन निर्धारित होते ही प्रतिवर्ष उसमें केवल 4 हजार रुपए की वृद्धि होती जाएगी, लेकिन पेंशन की अधिकतम राशि एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। दर्जनभर पूर्व विधायक हैं, जिन्हें एक लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है।

गुजरात में नहीं मिलती पेंशन

देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन यहां भी पूर्व विधायकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल के मानदंड के अनुसार इलाज के बिल के भुगतान और राज्य परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। पूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था सभी लोकतंत्रात्मक देशों में है। परंतु उन्हें पेंशन उस दिन से मिलती है, जब वे उतनी आयु के हो जाते हैं, जो उस देश में शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु है। जैसे यदि फ्रांस में शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, तो वहां के हर सांसद को 60 वर्ष का होने के बाद ही पेंशन मिलेगी।

बात पेंशन की हो या वेतन की, भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह सार्वजनिक हित में नहीं है। इन नियमों में तत्काल परिवर्तन की जरूरत है। कम-से-कम सांसदों और विधायकों का वह अधिकार समाप्त कर देना चाहिए, जिसके चलते वे स्वयं अपने वेतन-भत्ते निर्धारित कर लेते हैं। विदेशों की तरह यहां भी पेंशन के नियमों में परिवर्तन करके पेंशन पाने की आयु-सीमा शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा के समान होनी चाहिए।

गौरतलब है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने इस प्रकार की पहल की तो थी, परंतु उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। वेतन और पेंशन संबंधी नियमों में परिवर्तन न होने से जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वह जारी रहेगा और संसद की प्रजातांत्रिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। हमारे संविधान ने संसद और विधानमंडल को सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार दिया है। संसद और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। परंतु माननीयों द्वारा पेंशन के अधिकार का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए किया जाता रहा है, जो कि एक दृष्टि से अनैतिक है। आज ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि अपने हित में सरकारी कोष का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में अविश्वास की खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज को कायम रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। आज समय की मांग है कि जनप्रतिनिधियों को अपने चाल-चलन से आदर्श स्थापित करना चाहिए।

भारत में सांसद और विधायक खुद अपनी सैलरी बढ़ाने पर फैसला करते हैं

दुनिया के अनेक देशों में जनप्रतिनिधियों को वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, इसे वह खुद नहीं तय करते हैं बल्कि इसे तय करने का अधिकार अलग संस्थाओं को रहता है। इसके लिए उम्र और सेवा की सीमा तय है। वहीं, ब्रिटेन जैसे देश में इसके लिए आयोग का गठन किया गया हैं। हालांकि, भारत में सांसद व विधायकों की सुविधाओं के संबंध में क्रमशः संसद व विधानसभाएं ही फैसला लेती हैं। कनाडा में वेतन हर साल तय होती है और ये पिछले साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होती है। ब्रिटेन में आयोग है, जिसमें इंडिपेंटेंड पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड अथॉरिटी में शामिल सांसद, ऑडिटर और पूर्व जज तय करते हैं। सैलरी में सालाना संशोधन होता है, जो पब्लिक सेक्टर की औसत इनकम के अनुसार होता है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार, इकोनॉमी, कानून और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स तय करते हैं, सालाना संशोधित होती है। न्यूजीलैंड में जज, सांसद और स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं तय करती हैं, ये सदन में सांसद या विधायक के पद पर आधारित होती है। फ्रांस में हाईएस्ट ग्रेड वाले सबसे ज्यादा और सबसे कम सैलरी वाले सिविल सेवकों की सैलरीज के औसत से तय होती है। सिविल सेवकों की सैलरी को सदन के कोषाध्यक्ष (तीन सांसद) तय करते हैं।

कुप्रबंधन से जल संकट

जल जीवन मिशन के आंकड़े चिंताजनक

जल संकट से त्राहि-त्राहि के दिन आने वाले हैं। ऐसे संकेत आने भी लगे हैं और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि विश्व के अनेक बड़े-बड़े शहर निकट भविष्य में जल संकट से जूझ रहे होंगे। जल संकट एकल रूप में नहीं आता, अपने साथ अनेक सामाजिक तनाव पैदा करता आता है। कुछ मनीषी तो भविष्यवाणी भी करने लगे हैं कि तीसरा विश्वयुद्ध पानी पर होगा। वह तो समय ही बताएगा, लेकिन गर्मियों में गली-मोहल्लों में लघु 'गृह युद्धों' के दृश्य अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। अब ऋतु चक्र भी जल-चक्र के साथ मिल-जुल कर चलते हैं। एक ऋतु जल की उत्तरोत्तर कमी का विकट संकट लेकर आती है, और अगली **प्रचंड बाढ़ों और भूस्खलनों** के साथ जल की मारक शक्ति का घनघोर संकट लेकर। जल संकट की यह दोहरी मार प्रकृति का नहीं, मानव का खेल है।

पृथ्वी पर जीवन के लिए जल की आवश्यकता जीवन पर्यंत है। जल की कमी के कारण प्रजातियां और सभ्यताएं तक प्रभावित होकर नष्ट हो जाती हैं। सभ्यता के संकट की जड़ें जल संकट में ही निहित हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि जल ही जीवन का सार है, जिसके बिना जीवन की परिकल्पना करना व्यर्थ है। ऐसे में जल की महत्ता को देखते हुए इसके संरक्षण, सुरक्षा, प्रबंधन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व हमको लेना होगा। जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस राष्ट्रीय नीति और रणनीति का अभाव जल संकट का प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर जल का संरक्षण, सुरक्षा, प्रबंधन व बेहतर गुणवत्ता एक संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर गंभीर मंथन व क्रियान्वयन अपेक्षित है।

पृथ्वी पर जीवन-यापन के लिए पर्याप्त पानी किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य समस्या पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती मांग है। विश्लेषण बताते हैं कि सतही पानी का 80 प्रतिशत हिस्सा प्रदूषित है, जिसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेपों को माना गया है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है, जिससे गांवों और शहरों में जल को लेकर सामाजिक तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं। बात यहां तक आ पहुंचने लगी है कि पर्याप्त जल उपलब्ध न हो पाने के कारण अब जनमानस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जबकि यह उनके मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2001 में देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1,816 घनमीटर थी, जो एक दशक यानी 2011 बाद घटकर 1,545 घनमीटर और 2021 में 1,486 घनमीटर तक सिमट चुकी है। और आगामी साल 2031 तक लगभग घटकर 1,367 घनमीटर तक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

भारत सरकार के जल जीवन मिशन के आंकड़ों के अनुसार जल के गुणवत्ता की दृष्टि से तीन पहाड़ी राज्यों का स्थान शीर्ष पर है, जिनमें हिमाचल प्रदेश प्रथम, मणिपुर दूसरे तथा उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। पर्वतीय राज्यों के जलस्रोतों और उनके जल की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों से काफी बेहतर स्थिति में है, जिसका मुख्य कारण कहीं न कहीं मानवीय हस्तक्षेपों का कम होना है। लेकिन हाल ही में प्रकाशित एक आलेख में उत्तराखंड प्रदेश के 1200 जलस्रोतों के सूखने पर चिंता व्यक्त की गई है, जो निसंदेह भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों में जल की मांग में बढ़ोत्तरी का कारण बन सकते हैं। देखा जाए तो पृथ्वी पर जल की असुरक्षा और कुप्रबंधन भविष्य के लिए एक नया संकट बनता जा रहा है, जिससे बचने लिए सार्थक और अभूतपूर्व प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए जल के महत्व को समझना होगा और व्यर्थ में जल की बर्बादी को जनसहयोग से रोकना होगा और संकटग्रस्त जल स्रोतों को सूखने और जीवित व गतिमान जलस्रोतों को प्रदूषित तथा संक्रमित होने से बचाना होगा। जलस्रोत जीवित और हरे-भरे रहेंगे तो पृथ्वी पर जल की पर्याप्त उपलब्धता होगी और भू-गर्भीय जल का रीचार्ज एवं संतुलन ठीक प्रकार से बना रहेगा, जिससे पृथ्वी पर जल संकट की चिंता और भविष्य में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा जा सकता है।

अध्ययन यह भी बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से साल 2041 और 2051 तक जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटकर क्रमशः 1,282 और 1,228 घनमीटर तक रह जाएगी। देश में प्रति व्यक्ति घटती जल की उपलब्धता और तेजी से बढ़ती जनसंख्या निकट भविष्य में नए संकट का कारण बन सकती है, जिस पर गहन चिंतन, मनन के साथ प्राथमिकता स्तर से कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट बताती है कि भू-जल के अत्यधिक दोहन से देश में हर वर्ष पानी की मात्रा 0.4 मीटर घट रही है। देखा जाए तो भू-गर्भीय जल का अत्याधिक दोहन, कुप्रबंधन, अनियंत्रित विकास, शहरीकरण और मानवीय कार्यकलाप के कारण सतही जलस्रोतों का तेजी से संकुचित, अतिक्रमित व संक्रमित होकर सूखना जल मांग में वृद्धि का कारण बन रहे हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में साफ पानी न मिलने के कारण सालभर में लगभग दो लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं तथा 60 करोड़ भारतीय किसी न किसी प्रकार की जल की समस्याओं से जूझ रहें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन नें जीवन-यापन के लिए न्यूनतम 5 से 7 लीटर जल को आवश्यक बताया है, साथ ही 86 प्रतिशत से अधिक मानव रोगों का कारण दूषित जल को ठहराया है, जिसमें से हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया व पेचिश इत्यादि मुख्य हैं। एक तरफ जहां नीति आयोग 2030 तक देश में पानी की मांग को दोगुनी होने की संभावना पर चिंता व्यक्त कर चुका है, वहीं अगर आंकड़ों की माने तो जल गुणवत्ता सूचकांक मामले में 122 देशों की सूची में भारत का स्थान 120वां है जो देश में जल गुणवत्ता की निम्न स्थिति को परिलक्षित करता है।

● **अक्स ब्यूरो**

आज विपक्षी दलों के लिए अस्तित्व का संकट है। यह संकट गहराया तो प्रजातंत्र की बुनियाद हिल सकती है। समाज को एक-दलीय जकड़न से निकालने और विपक्ष की खराब राजनीति खत्म करने के लिए समाज की चिंता करने वाले नैतिक लोगों को राजनीति में आना होगा।

दिशाहीन विपक्ष

एक वक्त देश की राजनीति में मंडल की काट के रूप में कमंडल आया। इस दौरान देश के दो सबसे बड़े राज्यों उप्र और बिहार में एक ओर लालू-मुलायम तो दूसरी ओर कांशीराम एवं भाकपा माले जैसे ध्रुव उभरे। इनमें पहली जोड़ी ने कहा कि उनका उभार सामाजिक न्याय की ताकत के रूप में हुआ है, तो कांशीराम ने बसपा को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ दलितों की क्रांति की संज्ञा दी। वर्षों भूमिगत रहने के बाद चुनावी राजनीति में आए विनोद मिश्र ने दावा किया कि माले दलित चेतना को जमींदारों के शोषणकारी वर्चस्व के खिलाफ सकारात्मक पहलू विकसित कर रहा है और बसपा दलित चेतना का भ्रष्ट पक्ष उभार रही है। माले आज शोषणकारी व्यवस्था तो दूर, स्थानीय गुंडों के मुकाबले भी खड़ा होने की स्थिति में नहीं रहा। वैसे भी दुनिया में साम्यवाद के खात्मे के बाद धुर वामपंथ भी कुछ जंगलों में छिटपुट घटनाओं के अलावा अंतिम सांसें ले रहा है।

यह तो अतीत की बात है, लेकिन आज मंडल-कमंडल की राजनीति के 32 वर्षों बाद उत्तर भारत के 5 में से तीन राज्यों के चुनाव बताते हैं कि कमंडल तो मंडल को अपनाकर लगातार अपना विस्तार कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ सभी तीनों शक्तियां अवसान की स्थिति में पहुंच चुकी हैं और एक जो शक्ति सबसे पुख्ता लगती थी, वह विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी हाशिये पर खिसक गई है। वजह क्या रही? इन तीनों शक्तियों का सामाजिक न्याय हो या कांग्रेस का सेक्युलरिज्म, वह छिन्न-भिन्न होता दिख रहा है।

लार्ड एक्टन के प्रचलित कथन 'पावर करप्ट्स (सत्ता भ्रष्ट करती है)' को चरितार्थ करते हुए लालू-मुलायम ने राजनीति में अपराधीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक घातक मिश्रण तैयार किया, जबकि कांग्रेस नेहरू के बाद से ही परिवारवाद की जकड़न से निकल नहीं पाई। नेहरू-गांधी परिवार की चौथी यानी वर्तमान पीढ़ी को अकर्मण्यता, अक्षमता और पूर्णकालिक राजनीति के प्रति अरुचि ने घेर लिया है। इसके बरक्स भाजपा ने अपने को न तो भ्रष्ट होने दिया और न ही गवर्नेंस के मूल काम में कोई कोताही की। वह जनता के बहुसंख्यक भाग को गुड गवर्नेंस के कुछ अहसास के साथ अपने मोहपाश में बांधे रही। पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत गवर्नेंस की नई अवधारणा है कि अगर जीडीपी वाल्यूम बढ़ रहा हो और साथ ही गरीब-अमीर की खाई भी, तो उसे कम कर विकास में पिछड़े वर्ग को शामिल करने के लिए 'डायरेक्ट डिलीवरी' सबसे बेहतरीन तरीका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस ब्राजीलियन मॉडल के अनुरूप भारत में भी 5 किलो मुफ्त राशन या किसान सम्मान निधि के नाम पर हर किसान परिवार को 17 रुपए रोज देकर 'लाभार्थियों' का एक नया वर्ग तैयार किया। इसे राजनीतिक समर्थन में बदलना आसान हो गया। देश में एक पार्टी का वर्चस्व तोड़ने और जनता के बीच अपना प्रभाव बनाने के लिए अन्य विपक्षी दल एड़ी-चोटी का जोर लगाकर समझौते करते रहे हैं। इसके लिए वे भांति-भांति के समूहों में दिखाई देते हैं। जैसे पहली बार 1967 में नौ राज्यों में गैर-कांग्रेसी संविद सरकारें बनाकर या फिर 1977 में जनता पार्टी बनाकर अथवा 1996 में राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर।

भारत का समाज हजारों पहचान समूहों में बंटा है और ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों से आपस में वैमनस्य का भाव रखता है। भारत में प्रचलित चुनाव पद्धति, फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम, समाज को पहचान-समूहों में तोड़ता है। कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी धार्मिक निष्ठा के नाम पर। राजनीतिशास्त्र का यह सिद्धांत कि समय के साथ प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, भारत में कारगर नहीं है। 70 साल में जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति और बढ़ी है। हाल के दौर में छोटे-छोटे जाति समूहों के नेता वोटों का सौदा करने लगे और बड़ी पार्टियां उनसे समझौता करके सत्ता में हिस्सा देने लगी हैं। दलितों की स्थिति तो करीब-करीब यथावत रही, लेकिन **उसकी अगुआ बसपा** पैंतरा बदलकर कभी ब्राह्मणों तो कभी मुसलमानों को लुभाने लगी। वह सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य को भूल गई। यही कारण है कि दलितों का इस दल से मोहभंग हो गया और उन्होंने भाजपा को अपना बड़ा शुभचिंतक माना।

इन दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का दिल्ली, झारखंड और अन्य राज्यों के गैर-भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मिलना विपक्षी एकता का एक नया प्रयास है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश का मतदाता पार्टी के सिद्धांतों से नहीं, उसके नेता से प्रभावित होता है। नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी, सोनिया और मोदी इसी जन-भाव की उपज रहे। जनता अपना मत तभी बदलती है, जब किसी नेता को लेकर जबरदस्त आक्रोश हो या नया भरोसा बना हो या फिर कोई भावनात्मक मुद्दा हो। आज क्या विपक्षी एकता का कोई स्पष्ट कारण है? क्या जनमत वर्तमान

'पार्ट टाइम' पॉलिटिक्स का बोझ उठा रही कांग्रेस

बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की हो या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। इन दोनों ही कांग्रेस नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाजपा जैसी पार्टी के सामने, जो साल के 365 दिन चुनावी मोड में ही नजर आती है, ये भाई-बहन की जोड़ी आमतौर पर ट्विटर और कुछ खास मौकों पर ही जमीन पर एक्टिव नजर आती है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो कांग्रेस की विचारधारा को सूट करने वाले मुद्दों पर पार्टी का इकोसिस्टम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताता है कि अमुक मामले पर कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है। तो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस मुद्दे पर ध्यान देते हैं। हालांकि, इस तरह का विरोध केवल भाजपा शासित राज्यों में ही होता है। उदाहरण के तौर पर उप्र में महिलाओं पर अत्याचारों की बात करने वालीं प्रियंका गांधी की कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाती है।

चेहरे के दम पर नहीं मिल रहे वोट

बात बिहार की हो या पश्चिम बंगाल की, असम की हो या केरल, उत्तराखंड की हो या पंजाब की, गोवा की हो या मणिपुर की। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जी-तोड़ मेहनत की। लेकिन, पार्टी के अंदरूनी झगड़ों-खींचतान और कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी परिवार के गलत राजनीतिक फैसलों ने पार्टी को कमजोर कर दिया। उप्र में प्रियंका गांधी ने जमीन पर मेहनत की। लेकिन, वह कांग्रेस के पक्ष में न जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई। उत्तराखंड में राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया। लेकिन, कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बना सके। आसान शब्दों में कहा जाए, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ज्यादा प्रभाव तो वो कथित यूट्यूब पत्रकार रखते हैं, जो खुद को निष्पक्ष कहते हुए भी किसी एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का माद्दा रखते हैं। भले ही उससे जीत हासिल न करवा सकें। लेकिन, कम से कम उनकी कोशिशों का प्रभाव जमीन पर नजर तो आता है। लेकिन, गांधी परिवार इस मामले में भी पिछड़ता ही दिखता है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अपने चेहरे के दम पर ये केवल काडर वोट ही कांग्रेस को दिलवा सकते हैं। वहीं, पंजाब में तो गांधी परिवार ने सत्ता बाकायदा प्लेट में सजाकर आम आदमी पार्टी को सौंप दी।

राष्ट्रीय नेता के खिलाफ स्पष्ट रूप से तैयार है? क्या विपक्ष में कोई नेता जनता की नजरों में सर्वमान्य स्वीकार्यता बना पाया है, जैसा वर्तमान नेतृत्व ने 2014 में बनाया था? क्या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बन सकता है और अगर नहीं, तो क्या बंगाल, तेलंगाना, उप्र, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में हितों का टकराव इस एकता को स्वत: नहीं तोड़ेगा?

हर चुनाव में सभी पार्टियों के लिए कुछ न कुछ सीख होती है, चाहे वह पार्टी जीती हो या हारी हो। चुनाव के इस पाठ से जो पार्टी सीखती है, वही फायदे में रहती है। चुनाव में बार-बार हारने के बावजूद न सीखने वाली पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं। इन चुनावों से भी सीख मिली है, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। एक समय इन चारों राज्यों उप्र, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस इन राज्यों में कमजोर हुई तो उसकी जगह भाजपा ने ली। इसने तत्काल ऐसे कार्यक्रम लागू किए जिनसे समाज के बड़े वर्ग को फायदा हुआ। वह वर्ग मतदाता भी है। हिंदू पूजा स्थलों की दशा सुधारने के एजेंडे पर अमल करने के साथ भाजपा ने उप्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया और खासकर महिलाओं में सुरक्षा की भावना जगाई। योगी आदित्यनाथ को मिला जनमत उनके कार्यों को जनता की स्वीकारोक्ति समझा जाना चाहिए, न कि उसे सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाना चाहिए।

भाजपा पर हिंदुओं की पार्टी होने के आरोप लगते हैं। इसके बावजूद यह मणिपुर में बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, जहां 41 फीसदी आबादी ईसाइयों की है। गोवा और उत्तराखंड के चुनावी नतीजे भी इस बात के सबूत हैं कि भाजपा की लोकप्रियता समाज के हर वर्ग में है। सीमाई प्रदेश पंजाब ने कुछ अलग कहानी लिखी है। यहां कांग्रेस ने अपने ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बड़े बेआबरू करके हटाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद जो कुछ हुआ, वह इस बात का उदाहरण है कि किसी राज्य के शासन और पार्टी की इकाई में क्या नहीं किया जाना चाहिए। यहां कांग्रेस की हार की इबारत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की जीत से भाजपा को सीख लेने की जरूरत है, जो दिल्ली में उसकी मुख्य विरोधी पार्टी है। पंजाब में आप की बड़ी जीत का एक कारण कांग्रेस की कमजोर स्थिति तो है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण यह है कि भाजपा यहां अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश करने में नाकाम रही।

गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से यह तो स्पष्ट होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर नहीं देखता है। दिल्ली में उनके प्रदर्शन के बारे में कुछ न ही कहा जाए तो अच्छा। आप अन्य किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की तरह एक छोटे से इलाके तक सीमित है और उसका कोई राष्ट्रीय नजरिया भी नहीं है। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब में वे ईमानदारी से काम करेंगे और ऐसे हालात नहीं बनने देंगे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो। यह बात तो दिन की रोशनी की तरह साफ है कि भाजपा ने पूरे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस की जगह ले ली है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। वह आजादी के आंदोलन के नाम पर सत्ता सुख भोगती रही। लेकिन 1970 के दशक से हालात बदलने लगे। गुड गवर्नेंस के नाम पर उसने विभाजनकारी राजनीति, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक और अमीर बना गरीब की नीति अपनाई। आपातकाल लागू करके पार्टी ने यह भी साबित कर दिया कि उसे लोकतंत्र और संविधान की परवाह नहीं है। थोड़े समय के लिए आई जनता पार्टी की सरकार भी कोई विकल्प नहीं थी। तब लोकसभा में सिर्फ दो सांसदों वाली भाजपा ने अपने आपको बदला और कांग्रेस का विकल्प बनाया।

भाजपा के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की मुख्य वजह बेहतरीन रणनीति, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, दूसरों की परवाह करने वाला और कार्यकर्ताओं के करीब रहने वाला शीर्ष नेतृत्व और इन सबसे महत्वपूर्ण चुनावी वादों पर अमल करना है। कई बार तो घोषणापत्र में किए गए वादों से भी ज्यादा काम किए गए। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक ढांचा होने के कारण साधारण कार्यकर्ता भी सत्ता में ऊपर तक पहुंच सके और इसके बावजूद वे विनम्र तथा पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा के प्रति समर्पित रहे। आज के समय का मतदाता ऐसी पार्टियों को पसंद नहीं करता जहां शीर्ष पद जन्मजात अधिकार माना जाता हो, चाहे वह कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय। इन चुनावों की एक और खास विशेषता है कि अगले लोकसभा चुनावों के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि नतीजे भाजपा के पक्ष में होंगे। भाजपा का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ यही कारण उसकी जीत तय करने के लिए काफी है। हालांकि लोकतंत्र के हित में यही होगा कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई पार्टी विकल्प के रूप में मौजूद हो, लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना मुश्किल। सिर्फ भाजपा की आलोचना करने या उसका अनुसरण करके सफलता नहीं मिल सकती।

● **विपिन कंधारी**

5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने यह संकेत दे दिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की बहार रहेगी। शायद यही वजह है कि चुनाव परिणाम के साथ ही भाजपा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पार्टी के लगभग सभी पदाधिकारियों ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। जबकि विपक्ष अभी भी गठबंधन की कवायद में जुटा हुआ है।

भाजपा की 'बहार'

5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव नतीजे 2024 में किसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे देश के पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका हैं। भाजपा अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ताकत और भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी, जबकि खंडित विपक्ष के सामने यह चुनौती होगी कि वह अब करे क्या? हां, पंजाब में जीत दर्ज करके विपक्ष की ही एक पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जगह लेने का खम ठोंक दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब तीसरे मोर्चे के लिए ज्यादा मेहनत से काम करना होगा। यदि आने वाले महीनों में संगठन और नेतृत्व के मसले पर कांग्रेस ने वर्तमान स्थिति पर समझदारी और गहराई से अवलोकन नहीं किया, तो यह नतीजे कांग्रेस को और अंधेरे की तरफ ले जाने वाले साबित हो सकते हैं। हार के बाद विपक्ष ने इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 5 राज्यों में जीत की इस बढ़त के बूते ही भाजपा की नैया 2024 में पार लगेगी, या वह सिर्फ इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है?

उप्र में एग्जिट पोल से पहले कड़े मुकाबले के जो कयास थे, वो सभी गलत साबित हुए। भाजपा ने भले सन् 2017 के विधानसभा चुनाव से इस बार कम सीटें जीतीं; लेकिन फिर भी अपने बूते बहुमत हासिल कर उसने विपक्ष को पस्त कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सीटों में काफी बढ़ोतरी तो की; लेकिन इतनी नहीं कि सत्ता के द्वार पर पहुंच सके। अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव निश्चित ही बड़ा झटका है। भले सपा में उनके नेतृत्व के लिए कोई चुनौती पैदा न हो; लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी दोबारा परीक्षा होगी। हां, उन्हें पार्टी के भीतर यह साबित करना होगा कि उनकी नेतृत्व क्षमता पिता मुलायम सिंह यादव से कमतर नहीं है।

इस चुनाव के बाद भाजपा के भीतर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और भविष्य में निश्चित ही वह भाजपा में देश के प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार होंगे, जो कि वह चाहते भी हैं। उप्र चुनाव में जीत के बाद समर्थकों और सोशल मीडिया ने उन्हें इस तरह पेश भी किया है। 'सैफरॉन मोंक' और इस तरह के अन्य नाम देकर उनके समर्थकों ने उन्हें भाजपा और संघ के बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। निश्चित ही आने वाले महीनों में योगी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होगी। आखिर प्रदेश में पहली बार

मोदी बनाम योगी

भाजपा में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अब कोई कश्मकश होगी, इसकी फिलहाल तो कम ही संभावना है। लेकिन इसमें कोई दो-राय नहीं कि लगातार दूसरी जीत के बाद योगी भाजपा में नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं। उनके समर्थकों की भाजपा और भाजपा से बाहर बड़ी फौज है, जो उन्हें हिंदुत्व के नए और कट्टर चेहरे के रूप में देखती है। मोदी के विपरीत योगी खुले रूप से हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता हिंदुत्व के समर्थकों में मोदी से कहीं ज्यादा है। उप्र में भाजपा की लगातार दूसरी जीत के बाद सोशल मीडिया पर जो संदेश चलाए गए, उनमें से 80 फीसदी योगी के समर्थन में थे और मोदी के समर्थन में महज 20 फीसदी। आरएसएस के लोगों ने बड़ी संख्या में अपने ग्रुप्स में 'प्रो-योगी' संदेशों को फैलाया। हिंदुत्व समर्थक राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि 'निश्चित ही हिंदू धर्म की रक्षा पर फोकस करने की जरूरत है। योगी से बेहतर यह काम और कोई नहीं कर सकता। उप्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रशासन भी चलाया और हिंदुत्व की रक्षा का काम भी किया। हमें ऐसा ही नेता चाहिए।'

उनके नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इन चुनाव नतीजों को भाजपा के भीतर मोदी-शाह समर्थकों ने 'मोदी का करिश्मा बरकरार है' के रूप में पेश किया है। जाहिर है मोदी समर्थक किसी भी सूरत में अगले चुनाव मोदी के नेतृत्व में ही लड़ना चाहते हैं। इन चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत से उनके लिए ऐसा करना आसान हो गया है। नतीजों से यह साबित हो गया है कि भाजपा में मोदी एक चुनाव जिताने वाले नेता हैं और उनका कोई विकल्प फिलहाल नहीं। यहां तक कि चुनाव के दौरान जो भाजपा नेता संभावित हार-जीत को मोदी से जोड़ने से परहेज कर रहे थे, उन्होंने नतीजे आते ही इसे 'मोदी की लोकप्रियता की जीत' करार दिया।

उत्तराखंड में भले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए, भाजपा ने एकतरफा बहुमत हासिल करके कांग्रेस को करारा झटका दिया है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि उत्तराखंड की सत्ता में उसकी वापसी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिग्गज नेता हरीश रावत तक अपनी सीट से हार गए, भले उनकी बेटी चुनाव जीत गईं। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री धामी के लिए निश्चित ही जीत के बावजूद यह नतीजा अफसोस वाला रहा; क्योंकि पार्टी ने उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था। यह वैसा ही हो गया, जैसा 2017 में हिमाचल के चुनाव में हुआ था, जब पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे।

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस ही नहीं पंजाब की राजनीति में स्थापित पंथक पार्टी अकाली दल (शिअद) को भी साफ करके रिकॉर्ड जीत हासिल की। कांग्रेस फिर भी कुछ सम्मानजनक 18 सीटें जीतने में सफल रही, अकाली दल और भाजपा के साथ-साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और किसानों की नई-नवेली पार्टी का तो बंटाधार ही हो गया। कॉमेडी के सरताज रहे भगवंत सिंह मान अब पंजाब की राजनीति के नए सरताज हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने खुलकर काम करने दिया, तो मान को खुद को प्रमाणित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर कहीं आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली से चलाने की कोशिश की, तो अभी कहना कठिन है कि मान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आम आदमी पार्टी की जीत से पंजाब में नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई है। अगले लोकसभा चुनाव में भी निश्चित ही इसका असर दिखेगा।

कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी

देश में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए यह विकट संकट की घड़ी है। उसके पास उम्रदराज हो रहीं सोनिया गांधी का नेतृत्व है, और इसी साल के मध्य में उसे नया अध्यक्ष चुनना है। इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुछ राज्यों में जीत मिली होती, तो राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी ने निश्चित ही उप्र में बहुत मेहनत की, पर कांग्रेस को वहां पिछली बार से कम सीटें मिलीं। कांग्रेस के संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नतीजे आने के अगले ही दिन जी-23 के नेताओं ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के निवास पर बैठक करके चुनाव नतीजों को लेकर चिंता जताई। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में नेताओं ने सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई।

गोवा के नतीजे भी पूर्व अनुमानों के बिलकुल विपरीत रहे। वहां कांग्रेस को पक्की उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनेगी। लेकिन नतीजों ने उसके उत्साह पर बर्फ डाल दी। वहां भाजपा बहुमत के करीब पहुंच गई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी; लेकिन भाजपा ने जुगाड़ करके अपनी सरकार बना ली थी। गोवा में टीएमसी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई; लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सत्ता हासिल करने का सपना एक बार फिर टूट गया। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के भाजपा से बागी हुए बेटे भी चुनाव हार गए। उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट (अफ्सपा) की जोरदार मांग थी और ऐसा लग रहा था कि वहां भाजपा को इसका नुकसान होगा; लेकिन भाजपा ने सत्ता में वापसी की। वहां कांग्रेस पहले भाजपा को टक्कर देती दिख रही थी; लेकिन उसे चौथे नंबर से संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव में उसने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। मणिपुर में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो क्षेत्रीय दलों ने किया, जिनमें एनपीपी शामिल है।

उप्र में आसान जीत दर्ज करके भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। यदि भाजपा कुछ राज्यों में चुनाव हारती या उप्र जैसे राज्य में उसे बहुमत न मिला होता, तो विपक्ष के पास मुस्कुराने की वजह होती। भाजपा का लक्ष्य निश्चित ही अब 2024 है और इस मिशन के लिए वह पूरी ताकत से मैदान में जुट जाएगी। भाजपा की 4 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता ने उनकी सरकारों के काम पर मुहर लगाई है। भले विपक्ष ने इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हों; लेकिन मोदी बेफिक्र दिखते हैं और उनका कहना है कि हार के बाद जनता की समझदारी पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी आदत है। भले उप्र में भाजपा की सीटें पिछली बार से कम हुई हैं; लेकिन इसके बावजूद सरकार बना लेने का लाभ उसे लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने के बाद भी लोकसभा चुनाव तक उसे अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी।

● **इन्द्र कुमार**

एंटी इनकंबेंसी से कांग्रेस में छटपटाहट

छत्तीसगढ़ सरकार के पास विधानसभा चुनाव के लिए अब गिनती के महीने रह गए हैं। तीन साल तक सत्ता का सुख भोगने के बाद सरकार के अधिकांश मंत्रियों और विधायकों को एंटी इनकंबेंसी का डर सताने लगा है। ये कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं, बल्कि मंत्री और विधायक ही कह रहे हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष यानी कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इससे वाकिफ हैं। वे एंटी इनकंबेंसी की बात को खुले तौर स्वीकार कर मंत्रियों और विधायकों को चेता भी चुके हैं। वे यहां तक कह चुके हैं कि प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 सीट पर आसानी से चुनाव निकाल सकते हैं, लेकिन जिन 70 सीटों पर कांग्रेस के मंत्री और विधायक काबिज हैं, उसे कैसे जीत पाएंगे। उनका यह कहना कांग्रेस की राजनीति से जुड़े **बड़े ओहदेदार** नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संकेत है।

दरअसल, कोविड के कारण अधिकांश मंत्री और विधायक अपनी विधानसभा में सक्रिय नहीं हो पाए। कारण चाहे जो भी हो, सत्तापक्ष से जुड़े मंत्री, विधायक जनता से दूर हो गए। इससे जनता में नाराजगी बढ़ी है। इस नाराजगी को भुनाने के लिए विरोधी पार्टी ने कमर कस ली है। वैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीतिक पटल को देखें तो प्रदेश में अभी विपक्ष के रूप में भाजपा ही खड़ी है, जिसके पास सिपहसालारों की कमी नहीं है। भाजपा के रणनीतिकार खुद की पार्टी की जनाधार का **आंकलन** तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका फोकस सरकार के मंत्रियों और विधायकों की निष्क्रियता को लेकर ज्यादा है। भाजपा के रणनीतिकार सभी विधानसभा में विधायकों की परफार्मेंस रिपोर्ट बना रहे हैं। यह बात कांग्रेस के आलाकमान और पीसीसी चेयरमेन से छिपी नहीं है। यही वजह है कि पीसीसी चेयरमेन मोहन मरकाम ने भरी सभा में कह दिया था कि कोई यह न समझें कि गमछा रखने से कोई विधानसभा सीट रिजर्व हो जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि विधायकों और कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाना होगा। उनको सरकार के कामकाज की जानकारी देनी होगी। यह कहकर पीसीसी चीफ ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उन्होंने निष्क्रिय विधायकों और टिकट की चाह रखने वालों को चेतावनी दे दी है कि किसी के आगे-पीछे घूमने और एसी गाड़ी रखने और सफेद कुर्ता-पजामा पहनने से ही कोई नेता नहीं बन जाता। इसके लिए जनता के बीच लोकप्रियता जरूरी है। यह तब होगा, जब जनता से उनका सीधे जुड़ाव होगा। पीसीसी चीफ ने यह बयान देकर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों को समझाइश देने की भी कोशिश की है। बातों ही बातों में उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि अभी भी समय है। प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद मंत्री और विधायकों ने अब तक अपने ही मंसूबे पूरे किए हैं। अधिकांश ने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी है। जब सरकार से जुड़े कार्यकर्ता नाराज होंगे तो भला जनता कैसे संतुष्ट होगी।

दरअसल, कांग्रेस शासनकाल के तीन साल के दौरान कई मौके ऐसे आए हैं, जब कार्यकर्ता अपनी ही पार्टियों के नेताओं के खिलाफ मुखर हो गए थे। भरी मीटिंग में वे यह कहने से नहीं चूके थे कि उनका काम मंत्री और विधायक नहीं करते हैं। ऐसे में जनता के बीच सरकार की क्या उपलब्धियां गिनाएंगे। खुद का काम नहीं होने से कार्यकर्ताओं को टीस है। इसलिए वे सक्रिय नहीं हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी लाजिमी है, क्योंकि सरकार ने **तीन साल** में कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया है, जिसे लेकर वे जनता के बीच जाएं। छत्तीसगढ़ में धान बड़ा मुद्दा है, जिसे बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भुना चुकी है। समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन एक ही हथियार हर जंग जिता दे, यह भी मुमकिन नहीं है।

छत्तीसगढ़ में सरकार के प्रति एंटी इनकंबेंसी के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि पीसीसी चीफ यह सोचते हैं कि तीन साल के दौरान मंत्री और विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पाए हैं तो उसमें मेरा नाम भी शामिल होगा। मैं प्रतिदिन कुछ अच्छा करने के लिए सोचता हूं, लेकिन ये अलग बात है कि सोच के अनुसार काम नहीं होता। उन्होंने ने यह कहकर पार्टी में चल रही उनकी स्थिति और अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर दी है। पर राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले और मंझे हुए खिलाड़ी बिना सोचे-समझे कोई चाल नहीं चलता। इनमें बाबा भी शामिल हैं। उन्होंने इशारों-इशारों में ये संकेत दे दिए हैं कि किसी के सोचने और समझने से काई फर्क नहीं पड़ता, धरातल पर काम दिखाना ही पड़ेगा।

● **अक्स ब्यूरो**

एंटी इनकंबेंसी पर भ्रम

कांग्रेस संगठन और सरकार छत्तीसगढ़ में एंटी इनकंबेंसी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इन सबसे परे जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के अंदाज ही निराले हैं। उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि कोरोनाकाल में उन्होंने जितना काम किया है, उतना काम तो उनके संभाग में किसी ने नहीं किया है। अब एंटी इनकंबेंसी कहां काम कर रही है, ये तो प्रदेशाध्यक्ष ही बताएंगे। कांग्रेस की राजनीति से जुड़े और उच्च पदस्थ सूत्र राजस्व मंत्री के इस बयान को लेकर कई तरह के मायने निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के धाकड़ नेता और कद्दावर मंत्री को भ्रम हो गया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसी भ्रम ने तो बीते चुनाव में भाजपा की लुटिया डूबो दी थी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि सभी विधायक, मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना जैसे-जैसे कम होते जा रहा है मंत्री अपने विभागों में ध्यान दे रहे हैं। विधायक भी अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं। कृषि मंत्री अपने सहित प्रदेश के अधिकांश नेताओं के कार्यशैली को लेकर सफाई देते रहे लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस संगठन और सरकार छत्तीसगढ़ में एंटी इनकंबेंसी को लेकर चिंतित हैं और इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है।

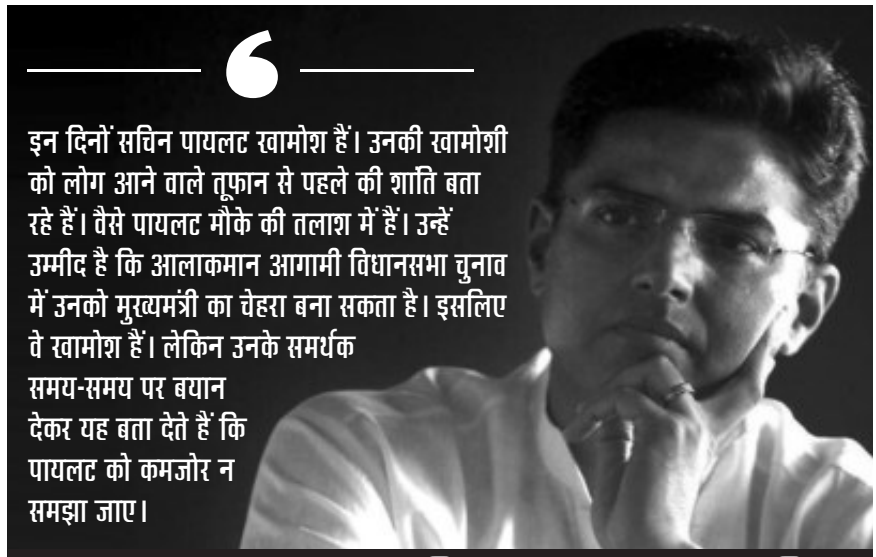

इन दिनों सचिन पायलट खामोश हैं। उनकी खामोशी को लोग आने वाले तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। वैसे पायलट मौके की तलाश में हैं। उन्हें उम्मीद है कि आलाकमान आगामी विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकता है। इसलिए वे खामोश हैं। लेकिन उनके समर्थक समय-समय पर बयान देकर यह बता देते हैं कि पायलट को कमजोर न समझा जाए।

पायलट की खामोशी

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खामोश हैं। 5 राज्यों में मिली चुनावी हार के बाद पायलट ने चुप्पी साध ली है। जानकार पायलट की खामोशी को सधी हुई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं।

पायलट कैंप के मंत्रियों की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ बयानबाजी से इस बात की हवा मिल रही है कि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर आया राम गया राम का दौर शुरू हो सकता है। इस बीच पायलट ने होली के बहाने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात सियासी अटकलों को हवा दे दी। पायलट की मुलाकात पर आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट ने नए कयासों को जन्म दे दिया। आचार्य प्रमोद ने पायलट की राज्यपाल से मुलाकात पर ट्वीट किया- लगता है जैसे शपथ ग्रहण समारोह को निमंत्रण दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद पायलट की सदन में उपस्थिति बेहद कम रही। सचिन पायलट विधानसभा में कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे है। माना जा रहा है कि पायलट की खामोशी से राज्य की सियासत में फिर उथल-पुथल का दौर शुरू हो सकता है। गहलोत सरकार पर सियासी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। पिछले साल उपमुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पायलट के हाथ खाली हैं। कांग्रेस **आलाकमान** ने पायलट को कोई पद नहीं दिया है। हालांकि, कैबिनेट के विस्तार में पालयट समर्थकों को प्रमुखता से जगह मिली है। राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप गहलोत कैंप पर हावी रहा। हालांकि, राजनीतिक नियुक्तियों में मलाईदार पद गहलोत कैंप से जुड़े नेताओं को मिले हैं।

विधानसभा में संख्या बल को देखा जाए तो बहुमत का गणित पूरी तरह मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ है। गहलोत सरकार पर फिलहाल खतरा नहीं है। लेकिन पायलट कैंप के मंत्रियों को रोजाना हो रही बयानबाजी से अटकलों को हवा मिल रही है। पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा है। हाल ही में करौली जिले में एक व्यापारी की हत्या के मामले में मंत्री रमेश मीणा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे में मंत्री रमेश मीणा ने पुलिस की आड़ में मुख्यमंत्री गहलोत को निशाने पर ले लिया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह विधानसभा में बयानबाजी कर गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।

पायलट कैंप के तीसरे मंत्री मुरारी लाल मीणा पायलट के धुर विरोधी किरोड़ी लाल मीणा से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। किरोड़ी लाल की सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के साथ पुरानी अदावत रही है। दौसा की राजनीति राजेश पायलट और किरोड़ीलाल के इर्द-गिर्द ही घूमी है। पायलट कैंप के मंत्री मुरारी लाल मीणा पुरानी अदावत को समाप्त कर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल का एक जाजम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट के इशारे पर ही मंत्री मुरारी लाल किरोड़ी लाल से दोस्ती बढ़ा रहे हैं।

उधर राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गहलोत और पायलट गुट की खींचतान कम करने के लिए आलाकमान ने दोनों गुटों के बीच तालमेल बैठाने की कवायद तेज कर दी है। इस खींचतान को कम करने के लिए आलाकमान का नया फॉर्मूला सामने आया है। राजनीतिक नियुक्तियों में कांग्रेस आलाकमान के तालमेल का फॉर्मूला साफ नजर आ रहा है। ये इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तालमेल बैठाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पायलट को मंत्रिमंडल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में **उम्मीद से ज्यादा** स्थान मिले हैं। लंबे समय से गहलोत और पायलट गुट में चल रही कलह पिछले साल इतनी बढ़ गई थी कि राजस्थान सरकार में विधायकों की बगावत देखने को मिली थी। अब राजनीतिक नियुक्तियों के दोनों दौर की सूची देखें तो मुख्यमंत्री गहलोत के नेताओं को मलाईदार पोस्ट मिली है, वहीं पायलट गुट को भी उम्मीद से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं। पायलट खेमे ने बगावत के बाद हुए समझौते में मंत्रिमंडल सहित राजनीतिक नियुक्तियों में अपने समर्थकों को सम्मानजनक स्थान देने की मांग की थी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

संतुलन साधने की कोशिश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों में संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। राजनीतिक नियुक्तियों की दोनों सूची देखकर साफ तौर पर जाहिर है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वफादारों को खास जिम्मेदारी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गहलोत समर्थक नेताओं चंद्रभान, महादेव सिंह खंडेला, पंकज मेहता, रफीक खान, खिलाड़ी लाल बैरवा, मेवाराम जैन, पुखराज पाराशर, धर्मेंद्र राठौर, राजीव अरोड़ा, लक्ष्मण मीणा, कृष्णा पूनिया और ब्रजकिशोर शर्मा को अहम पद मिले हैं। जबकि, पायलट गुट के सुरेश मोदी, गजराज खटाना, रामेश्वर डूडी, दर्शन सिंह, रेहाना, गोपाल सिंह शेखावत, महेश शर्मा, कीर्ति सिंह मीणा और पवन गोदारा को अहम पद मिले हैं। इस बीच राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर गहलोत और पायलट गुट के नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पायलट समर्थक सुशील आसोपा और राजेश चौधरी ने सदस्य पद सार्वजनिक तौर पर लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दोनों गुट के दर्जन भर नेता हैं जो नाराज हैं। लेकिन, फिलहाल उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं की है।

अपनी-अपनी जमावट

5 राज्यों के चुनाव परिणाम का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी नजर आ रहा है। महाविकास आघाडी गठबंधन के नेता आपसी बुनियाद मजबूत करने के साथ ही अपनी-अपनी जमावट में जुटे हुए हैं।

5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नेताओं की सक्रियता और मेल-मिलाप चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे यह संकेत भी मिल रहे हैं कि महाविकास आघाडी सरकार में सबकुछ ठीक नहीं है। जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा बंगले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में महाविकास आघाडी की एक अहम बैठक हुई, प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर मंथन हुआ। भाजपा ने तय किया हुआ है कि नवाब मलिक का इस्तीफा लिए बिना मानेगी नहीं। महाविकास आघाडी इस बात पर अड़ी हुई है कि जब नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई थी तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनका इस्तीफा क्यों लिया जाए। इस पर खुद नारायण राणे का कहना है कि नवाब मलिक पर दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों से **जमीन खरीदने** का आरोप है। उन पर ऐसे आरोप नहीं थे।

इस बीच देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राज भवन पहुंचे। पत्रकारों ने राजभवन के गेट के बाहर उनसे मिलने आने की वजह पूछी। जवाब में फडणवीस ने बस इतना कहा कि कोई राजनीतिक वजह नहीं है। वे एक इन्विटेशन देने आए हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के आने के बाद अलग-अलग जो बयान दिए हैं, वे गौर करने लायक हैं। गत दिनों जब उनसे पत्रकारों ने यह पूछा कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है क्या? फडणवीस ने कहा कि भाजपा इसके लिए कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन अपने अंतर्विरोध की वजह से अगर यह सरकार गिरती है तो भाजपा विकल्प देने के लिए तैयार बैठी है। इसके बाद भाजपा के गोवा प्रभारी होने की वजह से भाजपा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने उनका मुंबई में जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस जश्न के बाद अब लड़ाई मुंबई महानगरपालिका चुनाव की शुरू होगी। फिर वे वहां से विधानसभा के बजट सेशन में भाग लेने पहुंचे तो वहां पत्रकारों से कहा कि अत्याचारियों और दुराचारियों की सरकार के खिलाफ 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।

सत्ता के साथ भी, सत्ता के बाद भी

पवार के बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ कहे तो समझिए संबंधित व्यक्ति की राजनीति की समझ कच्ची है। लेकिन पवार के बारे में एक बात तो पक्की है। पवार हमेशा हवाओं के रुख को पकड़कर चलते हैं। 2014 के चुनाव के बाद उन्होंने शिवसेना से पहले ही भाजपा को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया था। शिवसेना की बारगेनिंग की संभावनाओं को खत्म कर दिया था। पवार बने रहते हैं हमेशा सत्ता के साथ भी, सत्ता के बाद भी। वे सत्ता से दूर नहीं रह सकते। फिलहाल 5 में से 4 राज्यों में चुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं। कुछ ही दिनों में यह दिखेगा कि एनसीपी और भाजपा के बीच दूरियां नजदीकियां बन गईं। वो नजदीकियां सत्ता में साझेदारी तक पहुंचेगी कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। केंद्रीय एजेंसियों की मार से बचने के लिए टेस्ट मैच की तरह विकेट बचाते हुए गेम को 5 साल तक पूरा कर ले जाना है या टी-20 की तरह हवाओं को भांपते हुए तुरंत मैच का रुख पलटना है। ना जाने पवार ने अब क्या ठाना है, यह उनको ही मालूम है। उनकी राजनीति को आज तक किसने जाना है?

इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के स्टेटमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कुछ दिनों पहले यह बयान दिया था कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी सरकार गिर जाएगी। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने अपनी यह बात याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि, अब तक वे जैसा-जैसा कहते आए हैं और जब-जब कहते आए हैं तब-तब, वैसे-वैसे बम फटते रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को अपना भविष्य ठीक रखना है तो संजय राउत को कंट्रोल करना पड़ेगा। संजय राउत तो कल को कभी भी शिवसेना का मुखपत्र सामना छोड़ कर कहीं और निकल लेंगे। उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरे कहां जाएंगे? दूसरी बात वे महाविकास आघाडी की सलामती के लिए चेतावनी देते हैं कि नवाब मलिक के इस्तीफे के बिना भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है।

फडणवीस के सारे बयानों का तारतम्य बिठाया जाए तो वे तीन बातें कह रहे हैं। एक, भाजपा सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन सरकार गिरी तो विकल्प देने में देरी नहीं करेगी। दो, फिलहाल फोकस मुंबई महानगरपालिका पर करना है। यानी अगले 6 महीने तक भाजपा का ध्यान बीएमसी के चुनाव पर रहेगा। तब तक सरकार को बदनाम करने की कोशिशें शुरू रह सकती हैं, गिराने की शायद नहीं। तीन, 2024 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इससे भी यह साफ होता है कि फिलहाल सरकार गिराने की कोशिशों पर ध्यान नहीं है। लेकिन चंद्रकांत पाटील की कही बातों में सरकार गिराने वाली चेतावनी संकेत छुपे हैं।

सवाल और भी कई हैं? एक सवाल तो यह कि क्या नवाब मलिक के इस्तीफे के बाद महाविकास आघाडी के लिए मामला सेटल हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। संजय राठोड़ के इस्तीफे के बाद, अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ, अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक का इस्तीफा होगा तो फिर अनिल परब, संजय राउत या और भी कई लोग हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। भाजपा नेता किरीट सोमैया भरी सभा में कह चुके हैं कि आधा दर्जन मंत्री जेल जाने वाले हैं। गौर करें तो देवेंद्र फडणवीस की कही मूल बात यही है कि महाराष्ट्र में सत्तांतरण अटल है। लेकिन कब? टाइमिंग बताना नहीं सरल है।

● **बिन्दु माथुर**

अब योगी मॉडल की बारी

महिलाओं की सुरक्षा के प्रति योगी की निजी प्रतिबद्धता बेमिसाल

वैसे तो दुनिया में कोई भी स्थान महिलाओं के लिए शत-प्रतिशत सुरक्षित नहीं है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के प्रति योगी आदित्यनाथ की निजी प्रतिबद्धता बेमिसाल है, जिसे जाति और संप्रदाय के पैमानों से परे भी सराहना मिल रही है। सुरक्षा के प्रति ऐसी अभूतपूर्व प्रतिबद्धता ने महिलाओं का एक विशेष वोट बैंक बनाया, क्योंकि गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाएं अपराध की सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। इस वोट बैंक में लाभार्थियों का पहलू जुड़कर सोने पर सुहागा सिद्ध हुआ। समाज के वंचित वर्ग के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के अमल पर केंद्रित योगी मॉडल बूस्टर डोज बनकर उभरा। कोविड जैसी अकल्पनीय त्रासदी के बीच योगी सरकार ने राशन वितरण तंत्र को इतना दुरुस्त बनाया कि कोई भूखा न रहे।

योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उप्र की कमान संभालने जा रहे हैं। 5 साल पहले जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। उनके विरोधी मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि उनके सत्तारूढ़ होने के गंभीर निहितार्थ होंगे और खासतौर से राज्य की मुस्लिम आबादी को इसकी तपिश झेलनी होगी।

दरअसल उप्र में सांप्रदायिक हिंसा का कलंकित अतीत रहा है और वहां हमेशा ऐसी चिंगारी भड़कने का जोखिम बना रहता है। योगी के पहले कार्यकाल की समाप्ति और शानदार जीत के साथ वापसी ने उन्हें लेकर जताई जा रही सभी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर आलोचकों को शांत कर दिया। उप्र के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी अवधि के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसने योगी को लेकर हुए आरंभिक दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। योगी अपनी पार्टी का वोट प्रतिशत आसमानी बुलंदी पर पहुंचा चुके हैं। यह जनता पर उनके शासन के प्रभाव का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचा, क्योंकि बीते चार दशकों में वह कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता में आने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए।

उप्र में भाजपा के लिए क्या कारगर रहा, इस पर तमाम विश्लेषण हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश का यही सार निकलता है कि जनता ने राशन एवं सुशासन से बने योगी मॉडल के प्रति अपनी गहरी आस्था जताई। योगी राज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के वादे को पूरा करने के प्रतीक रूप में उभरे। कई बार सांसद रहने के कारण उन्हें यह भलीभांति पता था कि सुशासन में क्या बाधाएं हैं और भ्रष्टाचार का दीमक किस प्रकार आम जनजीवन में घुन लगा रहा है। ऐसे में सांसारिक संबंधों को त्यागने वाले योगी ने आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत एक नई नेतृत्व शैली विकसित की। उनकी ईमानदारी पर उनके घनघोर आलोचक भी संदेह नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी राजनीति में ऐसा गुण बाजी पलटने वाली विशेषता सिद्ध होता है।

यदि एक संन्यासी के रूप में योगी के कद को देखा जाए तो उन्हें जाति और संप्रदाय के पैमानों से ऊपर उठना था। यह चुनौती उन्हें निशाना बनाकर किए जा रहे दुष्प्रचार से और विकराल होने जा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि क्या योगी लक्षित लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के पहुंचा सकेंगे। मानो, यह चुनौती ही पर्याप्त नहीं थी। इस बीच एक ऐसी वैश्विक महामारी ने दस्तक दी, जिसने अमेरिका जैसे विकसित देश को भी घुटने के बल ला दिया। यदि उप्र को एक अलग देश मान लिया जाए तो वह दुनिया का छठा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश के मुखिया पर अपनी जनता को कोविड रूपी प्रलय से बचाने का जिम्मा था। उसी दौरान प्रवासी श्रमिकों के पलायन की तस्वीरें भी आईं, जिनमें बीमारी और बेरोजगारी के मिश्रित भाव निहित थे।

राज्य पर आश्रितों का बोझ पहले से भी कई गुना बढ़ गया था। ऐसे गहन मंथन के दौर में योगी मॉडल जैसी मणि प्रकट हुई। कानून एवं व्यवस्था में सख्ती के साथ बदलाव की बयार पहले से ही महसूस की जाने लगी थी। योगी ने उप्र में ऐसा परिवेश बनाया, जिससे राज्य कारोबारियों के लिए निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरने लगा। योगी सरकार के पहले निवेश सम्मेलन के दौरान राज्य में 4.68 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। यहां तक कि महामारी के दौरान भी राज्य 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल रहा। बैंकों से सुगमतापूर्वक मिलने वाले ऋणों के दम पर गतिशील एमएसएमई क्षेत्र ने राज्य में 2.6 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान किया। मीडिया के एक वर्ग ने ऐसे परिवर्तनों को प्राथमिकता के साथ रेखांकित नहीं किया, क्योंकि इसमें जाति और समुदाय संबंधी कोई मसाला नहीं था। वहीं बदले माहौल का असर निवेशकों के भरोसे पर स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जो राज्य देश की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था था, वह अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया है और योगी उसे अव्वल नंबर पर लाने का संकल्प जता चुके हैं।

देश के सभी राज्यों में पूंजीगत व्यय के पैमाने पर उप्र सबसे ऊपर है। प्रदेश में उन्नत होते बुनियादी ढांचे और निर्बाध बिजली आपूर्ति से जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है। उनकी कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मेल खाती है। उन्होंने खुद को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाला मुख्यमंत्री साबित किया है। कई प्रकार से वह प्रधानमंत्री के 'कर्म पुत्र' की भांति हैं। कोविड के दुखदायी दौर में योगी ने कई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए, जबकि उस अनिश्चित दौर में विपक्षी नेतृत्व लोगों के बीच से नदारद था।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

भाजपा की ख्वाहिश अब तक अधूरी

बिहार ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। ब्रिटिश राज में बंगाल के विभाजन के बाद बिहार को अलग प्रांत के तौर पर अधिसूचित किया गया था। अलग प्रशासनिक इकाई के तौर पर बिहार की राजनीति का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। बिहार की राजनीति में पिछले करीब तीन दशक से बड़ा कद रखने वाली पार्टी एक बार भी इस राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है। जबकि, बिहारी राजनीति में लगातार हाशिए पर जा रही कांग्रेस ने इस राज्य को पूरे 14 मुख्यमंत्री दिए हैं। कई छोटे और क्षेत्रीय दल भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय फलक पर छाती जा रही भाजपा का यह सपना अब तक पूरा नहीं हो सका है।

बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के अलावा अन्य नौ दलों के प्रतिनिधि भी काबिज हो चुके हैं। इनमें समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, जनता पार्टी, जन क्रांति दल, सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस (ओ) और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस को सबसे अधिक दिनों तक शासन करने का मौका मिला है। कांग्रेस से जगन्नाथ मिश्रा बिहार के आखिरी मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बिहार में कांग्रेस को कभी फिर मौका नहीं मिला।

कांग्रेस को हराकर लालू जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वे जनता दल के नेता थे। चारा घोटाले में जब उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा तो जनता दल के नेतृत्व ने उन्हें कुर्सी छोड़ने का निर्देश दिया। इस निर्देश के खिलाफ लालू ने बगावत करते हुए बिहार में जनता दल को तोड़कर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना ली। राबड़ी देवी इसी पार्टी से मुख्यमंत्री बनीं।

नीतीश कुमार दो पार्टियों से बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वे पहली बार समता पार्टी के नेता के तौर पर जबकि इसके बाद लगातार जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बने। समता पार्टी और जनता दल के विलय के बाद जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को भी दो दलों से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। बिहार में केवल चार दलों को ऐसा मौका मिला कि उनके दो या इससे अधिक मुख्यमंत्री बन पाए। इनमें पहले नंबर पर तो कांग्रेस है। इसके बाद जदयू से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से सतीश प्रसाद सिंह और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जनता पार्टी से कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनने का मौका बिहार की जनता ने दिया। कर्पूरी ठाकुर एक बार सोशलिस्ट पार्टी से भी मुख्यमंत्री बने।

बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में इंडियन नेशनल कांग्रेस (ओ) से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने। यह दल कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले धड़े के विरोध में बना था। इनके अलावा जन क्रांति दल से महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। बाकी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के नाम हम पहले ही बता चुके हैं। बिहार को अब तक कुल 10 गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री मिले हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े दल के तौर पर स्थापित हो चुकी भाजपा लंबे समय तक बिहार में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर रही। इसके बाद करीब 15 साल से भाजपा बिहार की सरकार में है। फिलहाल भाजपा बिहार की सरकार में शामिल सबसे बड़ा दल भी है। इसके बावजूद बिहार में भाजपाई मुख्यमंत्री का सपना अभी अधूरा ही है।

बिहार ने अब तक सबसे अधिक मौका कांग्रेस को दिया। इस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर चेहरों को खूब बदला। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। यहां तक कि कई कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल एक महीने भी नहीं रहा। कांग्रेस से बिहार को श्रीकृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, कृष्ण बल्लभ सहाय, बिंदेश्वरी दूबे, बिनोदानंद झा, अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर सिंह, केदार पांडेय, भागवत झा आजाद, दारोगा प्रसाद राय, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री और दीप नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार की राजनीति में बवंडर

बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा सरेआम है कि बिहार विधानसभा सत्र के समापन के साथ ही बिहार की राजनीति में बवंडर आना तय है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और नीतीश कुमार की मुलाकात उसी बवंडर को थोड़े समय तक टालने की कवायत मानी जा रही है। हालांकि उप्र में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित है लेकिन भाजपा इस बात को लेकर चिंतित है कि बिहार सरकार के एक वर्ष पूरे होने के बावजूद भाजपा का कोई भी मंत्री उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाया है जिसके सहारे बिहार की राजनीति को साधा जा सके। ऐसे में सत्र के बाद बिहार मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे के मंत्री में बड़ा बदलाव हो सकता है जिसमें उपमुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों का हटना तय माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दो टूक कह दिया है कि साथ सरकार चलानी है तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को भी हटाए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अध्यक्ष को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार चल रहा है।

चीन का बढ़ता रक्षा बजट

चीन का रक्षा बजट पिछले वर्ष 209 अरब डॉलर था। 5 मार्च को प्रस्तुत इस वर्ष के रक्षा बजट को बढ़ाते हुए 230 अरब डॉलर कर दिया है। इस 21 अरब डॉलर को मामूली बढ़ोतरी नहीं कहा जा सकता है। चीन का रक्षा बजट अब भारत के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के साथ चीन का तनाव पिछले काफी दिनों से चल रहा है। भारत के साथ लगती सीमा पर तनातनी और अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपना रक्षा बजट प्रस्तुत किया जिसमें उसने भारी वृद्धि की है।

चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा वहां की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी में प्रस्तुत मसौदा बजट के हवाले से जानकारी दी कि चीन की सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 230 अरब डॉलर के रक्षा बजट का प्रस्ताव किया है। देखा जाए तो चीन द्वारा रक्षा बजट में वृद्धि का प्रस्ताव हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके द्वारा शक्ति प्रदर्शन की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है। ली केकियांग ने संसद में प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट में पीएलए की युद्ध संबंधी तैयारियों को वृहद तरीके से मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा विकास हितों की रक्षा के लिए चीन की सेना को मजबूत और ठोस तरीके से सैनिक तैयारियों को अंजाम देने की आवश्यकता है।

चीन का नया रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा हो गया है। यहां जानने वाली एक बात और है कि चीन का आंतरिक सुरक्षा बजट इससे अलग है जो हमेशा रक्षा बजट से अधिक ही होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वर्ष 2012 में सत्ता में आने के बाद चीन का रक्षा खर्च लगातार बढ़ा है। चीन द्वारा विगत वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई थी। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका का रक्षा बजट सबसे ज्यादा 770 अरब डॉलर है। इसके बाद चीन और भारत का नंबर है। इसके बाद रूस का 61.7 अरब डॉलर, ब्रिटेन का 59.2 अरब डॉलर, सऊदी अरब का 57.5 अरब डॉलर, जर्मनी का 52.8 अरब डॉलर, फ्रांस का 52.7 अरब डॉलर और जापान का 49.1 अरब डॉलर है।

चीन द्वारा उसके रक्षा खर्चों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है जब लद्दाख और अरुणाचल सीमा पर पिछले लगभग दो साल से चल रहा तनाव कम नहीं हुआ है। तनाव कम करने के लिए 15वें दौर की वार्ता में भी कुछ हल निकल सका है। वहीं दूसरी तरफ चीन का अमेरिका के साथ सैन्य एवं राजनीतिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन के खिलाफ बने क्वाड गठजोड़ ने भी चीन की चिंताओं को अधिक बढ़ाया है। इन सबके अलावा चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से पीछे हटने वाला नहीं है। शायद इसीलिए चीन अपने रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। विदित हो कि यह लगातार सातवां ऐसा वर्ष है जब चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी का प्रतिशत इकाई अंक तक ही सीमित रखा, लेकिन भारत की तुलना में उसका रक्षा बजट काफी अधिक है।

सेना को अत्याधुनिक बनाए जाने पर फोकस

चीन अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। चीन ने रक्षा बजट में वृद्धि को उचित ठहराते हुए यह भी कहा कि अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सैन्यीकरण कर रहा है। खासकर दक्षिण चीन सागर को लेकर खींचतान सबसे ज्यादा है। चीन के नीति नियंताओं के मुताबिक सेना को अत्याधुनिक बनाए जाने के फोकस को देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाया गया है। चीन का ध्यान स्टील्थ लड़ाकू विमान, विमानवाहक पोत, सैटेलाइट रोधी मिसाइल समेत नई सैन्य क्षमता विकसित करने पर है। चीन अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नौसेना की पहुंच को समुद्री क्षेत्रों में फैला रहा है। इस साल के रक्षा बजट का मुख्य जोर नौसेना के विकास पर रहेगा, क्योंकि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर उसके दावे तथा समुद्री आवागमन के लिहाज से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। इसके अलावा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए उसके जवाब के तौर पर तैयार होना है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन सैन्य क्षेत्र में दुनिया के शक्तिशाली देशों की तुलना में सबसे ऊपर रहना चाहता है। ऐसी स्थिति में भारत को चीन की रक्षा बजट में बढ़ोतरी से सजग रहने की आवश्यकता होगी।

यहां गौरतलब यह भी है कि रक्षा बजट के मामले में चीन अभी भी अमेरिका से काफी पीछे है। इस घोषणा के बाद चीन अमेरिका के बाद रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दूसरा देश बन गया है। अमेरिका का रक्षा बजट चीन के मुकाबले लगभग चार गुना ज्यादा होता था जो अब साढ़े तीन गुना ही ज्यादा है। हाल के वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े सैन्य सुधार किए हैं। इन सुधारों के तहत उसने दूसरे देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए नौसेना और वायुसेना को प्राथमिकता देते हुए उनका विस्तार किया। अब चीन नई रोबोट आर्मी तैयार कर रहा है और इसकी तैनाती भी भारतीय सीमा के नजदीक करनी शुरू कर दी है। उसने भारतीय सीमा के नजदीक सैन्य गांव भी बसा दिए हैं। जबकि उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की संख्या में तीन लाख तक की कटौती भी की है। इसके बावजूद 20 लाख की सैन्य संख्या बल के साथ पीएलए अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन अपनी इसी रक्षा नीति पर चलते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन रहा है। विगत दो वर्षों में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की गई हैं, उतने शायद अमेरिका की नौसेना में न हों। इतने हथियारों की बढ़ोतरी के बाद भी उसकी भूख कम नहीं हुई है। विदित हो कि कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी नौसेना को संसार की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बनाने का जो संकल्प लिया था उसे चीन पूरा करने में लगा हुआ है। वर्ष 2020 तक चीन ने 360 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती की है। चीन की यह विस्तारवादी नीति आने वाले समय में विश्व को नए युद्ध में धकेलने में देर नहीं लगाएगी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

प्रतिद्वंद्विता से उपजी तबाही

रूस और यूक्रेन के बीच 37 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी हमले से यूक्रेन में जान माल की जबरदस्त क्षति पहुंची है। फिलहाल युद्ध रूकने के आसर नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह है प्रतिद्वंद्विता। दरअसल साल 1988 में जब सोवियत संघ का विघटन होने लगा था, तब से लेकर रूस और इसके कुछ पड़ोसी गणतंत्रों के बीच रिश्ते असहज या तनावग्रस्त रहने लगे। जहां एक ओर रूस के संबंध अपने आसपास के सोवियत युग के पूर्वी इस्लामिक गणतंत्रों के साथ मधुर और सहयोगात्मक रहे वहीं भूतपूर्व सोवियत संघ का घटक रहे एस्टोनिया, लात्विया, लिथुएनिया और स्लोवानिया ने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली। यूरोपियन यूनियन के नव-निर्वाचित सदस्य बनने से उनकी आर्थिक तरक्की हुई। यूक्रेन, जो कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, उसने रूस के साथ अपनी पुरानी आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक सांझ वाली नजदीकियां बनाए रखीं। सामरिक रूप से भी यूक्रेन नक्शे में बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है, जिसके तटों से होकर रूस की पहुंच गर्म पानी वाले अजोव सागर, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर तक होती है। गर्म समुद्र तक अपने इस आवागमन मार्ग को बने आसन्न खतरे के मद्देनजर रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमिया का नियंत्रण यूक्रेन से छीन लिया था, साथ ही रूसी भाषी बहुलता वाले उसके डोनबास इलाके के अधिकांश हिस्सों को भी कब्जा लिया। ठीक इसी समय यूक्रेन में गतिशील, करिश्माई और कुछेक की नजरों में अधीर स्वभाव वाले वोलोदीमीर जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दोनों मुल्कों के बीच खटास बढ़ने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि जेलेंस्की अपने देश में बहुत लोकप्रिय हैं किंतु अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाने और बड़बोलेपन की वजह से उन्होंने जल्द ही रूस का शक और गुस्सा अर्जित करना शुरू कर दिया।

10 नवंबर, 2021 के दिन वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन और उनके यूक्रेनी समकक्ष दिमित्रि कुबेला द्वारा एक समझौते पर दस्तखत किया जाना रूस को बहुत नागवार गुजरा, जिसने कड़ी प्रतिक्रिया के किए भड़का दिया। इस संयुक्त घोषणापत्र में यूक्रेन पर सीधे या मिले-जुले आक्रमण से बचाव के लिए बड़े स्तर पर उपाय करने की बात थी और आक्रामकता दिखाने के लिए रूस को उत्तरदायी ठहराया गया। इसमें यह भी कहा गया कि क्रियान्वयन हेतु अमेरिका द्वारा यूक्रेन की रक्षा और रक्षा-उद्योग सुधार और काला सागर सुरक्षा जैसे मामलों में सहयोग किया जाएगा। जहां यूक्रेन के साथ अपने सैन्य सहयोग को विस्तार देना अमेरिका का हक बनता है वहीं काला सागर और भूमध्य सागर तक अपनी निर्बाध पहुंच समेत जिन विषयों को लेकर रूस अत्यधिक चिंतित रहता है उस पर आक्रामक भंगिमा अपनाना निश्चित रूप से कूटनीतिक दृष्टि से अक्लमंदी भरा कदम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रूस किसी भी सूरत में इन पहुंच मार्गों की सुनिश्चितता कायम रखने को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। बहुत पुराने समय से ही इन दक्षिणी तटों तक निर्बाध आवागमन बनाए रखना रूसी नौवहनीय नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है।

यूक्रेनी कदमों को रूस महासागर तक पहुंच मार्ग काटने वाला गंभीर खतरा मानता है और अब वह काला सागर और अजोव सागर तक निर्बाध रास्ता कायम रखने के लिए यूक्रेन के तटीय केंद्रों लुहांस्क और दोनेस्तक को अपने नियंत्रण में रखने पर बजिद है। हालांकि ओडेसा बंदरगाह को भी अपने नियंत्रण में लेना उसका अन्य ध्येय है पर यह कर पाना काफी मुश्किल होगा। इस सारे परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, 10 नवंबर को अमेरिका और यूक्रेन ने संयुक्त घोषणा पत्र में कहा 'रूसी सशस्त्र आक्रमण, आर्थिक और ऊर्जा बाधा और कुटिल साइबर हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका मदद करना चाहता है, इन उपायों में, अंतर्राष्ट्रीय मान्य सीमा के मुताबिक यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पुनः कायम होने तक रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए रखने या इससे संबंधित विषयों में, अन्य प्रासंगिक उपाय करना शामिल है।' निसंदेह, आमने-सामने की स्थिति में आए, विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु अस्त्र मालिक इन दो ताकतवर मुल्कों को इस किस्म की धमकीपूर्ण भाषा की जगह गंभीर वार्ता से काम लेना चाहिए। हालांकि यह विचार बलवती होता जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी से घरेलू और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई फजीहत को ढांपने के लिए रूस से बरतने में कड़े तेवर और दृढ़ता दिखा रहा है। उक्त समझौते में यूक्रेन के आस-पड़ोस को लेकर अमेरिकी नीतियों में, रूस को संभावित आक्रांता बताया गया। कहा गया कि इसका उद्देश्य यूक्रेन की पूरबी सीमाओं पर रूसी सेना की घुसपैठिया आक्रामकता शुरू होने के दो-तीन महीने पहले से विचाराधीन था। हालांकि रूसियों ने अपने नौवहनीय सामरिक हित सुरक्षित रखने के लिए सैन्य कार्रवाई को छोटे इलाके पर केंद्रित करने की बजाय समूचे यूक्रेन पर चढ़ाई करके युद्ध को विस्तार देने की गलती की है।

● **कुमार विनोद**

अमेरिकी-यूक्रेन संधि ने आग में घी का काम किया

10 नवंबर, 2021 की अमेरिकी-यूक्रेन संधि के विस्तृत एवं भड़काऊ प्रावधानों ने आग में घी का काम कर डाला। इसके अलावा, अमेरिका-यूक्रेन के बीच बढ़ती नजदीकियों से रूस को डर हो गया कि अन्य पूर्व सहयोगियों की तरह यूक्रेन का अमेरिका नीत नाटो संगठन का सदस्य बनने पर उसके बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। रूस पहले अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा सीमा से सटे यूक्रेन के दोनेस्तक और लुहान्सक क्षेत्र तक सीमित रखे हुए था, किंतु नवंबर में आई अमेरिकी-यूक्रेनी संयुक्त घोषणा और काला सागर में अमेरिका के पांचवें बेड़े की उपस्थिति को रूस ने अपने नौवहनीय प्रचालन और संचार संपर्कों के लिए खतरे के तौर पर लिया और रूसियों के पास यूक्रेन के दक्षिण-पूरबी इलाके का नियंत्रण अपने पास रखने के सिवा कोई विकल्प न बचा, ताकि काला सागर और भूमध्य सागर तक पहुंच मार्ग और संचार लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। ये वह मसले हैं जिन्हें केवल रूस और यूक्रेन के बीच रचनात्मक वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता था।

महिलाएं बन रहीं मेगा-इकोनॉमिक फोर्स

देश में महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में अपना हुनर दिखा रही हैं। यहां महिलाएं स्वसहायता समूह बनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं कई तरह के उद्यम भी कर रही हैं। महिलाओं की सक्रियता से देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। आर्थिक विश्लेषक महिलाओं को मेगा-इकोनॉमिक फोर्स की तरह देख रहे हैं।

बिजनेस के मैदान में पहली बार उतरने वाली महिलाएं भी अब अपने धैर्य और कड़ी मेहनत के दम पर पुरुषों की तरह ही सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपनी उद्यमशीलता को नए आयाम दे रही हैं, और एकदम नए और गैर-परंपरागत व्यावसायिक क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। वे अपना सारा डर ताक पर रख बेझिझक कारोबारी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उतर रही हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही हैं। कारोबारी परिदृश्य में इस हालिया बदलाव के पीछे भारत सरकार के कार्यक्रमों की भी अहम भूमिका रही है, जिनका उद्देश्य महिलाओं के दीर्घकालिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

विश्व बैंक के मुताबिक, कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी दोगुनी होने पर भारत की विकास दर 7.5 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगी और 2025 तक देश की जीडीपी भी बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच जाएगी। भारत में आज महिलाएं जिस तरह मेगा-इकोनॉमिक फोर्स बन रही हैं, उसे दुनिया में व्यापक स्तर पर पहचान भी मिल रही है। भारत में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों ने केवल पांच सालों में अनुमानित तौर पर 90 फीसदी की वृद्धि हासिल की है, जो अमेरिका (50 प्रतिशत) और ब्रिटेन (24 प्रतिशत) की महिला उद्यमियों की तुलना में कई ज्यादा है।

शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि 2021 में भारत एक ही साल में 33 यूनिकार्न के आगाज के साथ इस मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा, और यहां तक कि ब्रिटेन को भी पछाड़ देगा। हालांकि, भारत में अभी 1 बिलियन डॉलर वाले ऐसे स्टार्ट-अप की संख्या काफी सीमित हैं, जिनकी संस्थापक महिलाएं हों। इसके बावजूद बदलता ट्रेंड उत्साहजनक है, क्योंकि भारत के अधिकांश स्टार्ट-अप जो आज यूनिकार्न बन चुके हैं, उनमें एक दशक पहले कोई महिला संस्थापक नहीं थी। ये बेहद रोमांचक है कि बतौर नियोक्ता महिलाओं की भूमिका और सकल घरेलू उत्पाद में उनके अहम योगदानकर्ता होने को लेकर आज गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है।

कारोबारियों के तौर पर भारतीय महिलाओं की क्षमता पूरी तरह आंकने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर बाजारों और वित्त पोषण तक उन्हें अधिक पहुंच मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, इसकी पुष्टि आरबीआई का एक सर्वेक्षण करता है, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा समय में 43 फीसदी छोटे कारोबारों का वित्त पोषण मित्रों और परिवार के योगदान से होता है। इससे भी अहम बात यह है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ, नीति निर्माताओं और बड़े निगमों को मिलकर काम करना होगा। खासतौर पर, यदि हम सही मायने में 2030 तक लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-5 यानी एसडीजी-5 को पूरा करने के प्रति गंभीर हैं। हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है, और हमें इसकी शुरुआत अभी करनी होगी।

वीकनेक्ट इंटरनेशनल अपने सदस्य खरीदारों को महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों से अधिक से अधिक खरीद के लिए सार्वजनिक लक्ष्यों पर प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी यह पहल एसडीजी-5 लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का एक उदाहरण है, और अन्य संगठनों और व्यावसायिक संघों को भी ऐसा ही करना चाहिए। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों से खरीदना स्थानीय ही नहीं विश्व स्तर पर भी एक स्मार्ट फैसला है। निवेशकों, संगठनात्मक खरीदारों से लेकर व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तक, महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों का समर्थन करना सभी हितधारकों के लिए अच्छी व्यावसायिक समझ का परिचायक है। बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले और विकासोन्मुख महिला आपूर्तिकर्ताओं का विकास हो। इसी तरह क्षमता निर्माण, बाजार तक पहुंच, वित्त पोषण और बिजनेस नेटवर्किंग को सुविधाजनक बनाने में एनजीओ को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

दुनियाभर में 30 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय

यद्यपि दुनिया के सभी निजी व्यवसायों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं, लेकिन वर्ष 2022 में भी महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के उत्पादों और सेवाओं पर बड़े कॉर्पोरेट और सरकार का खर्च एक प्रतिशत से भी कम है। एक्सेंचर, सिस्को, इंटेल, आईबीएम, जॉनसन एंड जॉनसन, मैरियट और पीएंडजी जैसे कुछ प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी अपनी वैल्यू चेन के कुछ हिस्से की आपूर्ति पहले से ही दक्षिण एशिया से कर रहे हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय खरीदार भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों से आपूर्ति के अपने प्रयास बढ़ाकर अपनी कंपनी के सार्वजनिक लक्ष्यों को पूरा करने की सामर्थ्य बढ़ाने और क्षमता-निर्माण संबंधी अन्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रगति दोनों में योगदान कर सकते हैं। इससे आपूर्तिकर्ताओं को भी कोविड-19 के व्यापक विनाशकारी आर्थिक प्रभावों से उबरने में मदद मिलेगी।

चैत्र नवरात्रि में होगी मां शक्ति की आराधना

साल की बड़ी उजागर चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि ब्रह्माजी ने इस दिन से सृष्टि निर्माण की शुरुआत की थी। इसी दिन से नया साल संवत् 2079 की शुरुआत होगी। भक्त नए साल की शुरुआत देवी की आराधना से करेंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि यह नवरात्रि खास ग्रह योग-संयोग के कारण मनोकामना पूर्ति करेगी तथा साधकों को सिद्धि देगी।

चैत्र नवरात्रि पूरे नौ दिन रहेगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल शनिवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगी। ज्योतिषविद् अर्चना सरमंडल के अनुसार बुद्धादित्य योग स्वयं की राशि मकर में शनि देव मंगल के साथ रहेंगे, जो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। रवि पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग नवरात्रि को स्वयं सिद्ध बनाएंगे। शनिवार से नवरात्रि का प्रारंभ शनिदेव का स्वयं की राशि मकर में मंगल के साथ रहना निश्चित ही सिद्धि कारक है। इससे कार्य में सफलता, मनोकामना की पूर्ति, साधना में सिद्धि मिलेगी। 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। एकम-शैलपुत्री, द्वितीया-ब्रह्मचारिणी, तृतीया-चंद्रघंटा, चतुर्थी-कुष्मांडा, पंचमी-स्कंद माता, षष्ठी-कात्यायनी, सप्तमी-कालरात्रि, अष्टमी-महागौरी, नवमी-सिद्धिदात्री का विध-विधान से भक्तों द्वारा पूजन किया जाता है।

शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि साल में 4 बार आता है- चैत्र, आषाढ़ व अश्विन माघ। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उजागर नवरात्रि है, शेष दो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कही जाती हैं। चैत्र नवरात्र में देवी के नौ रूपों का पूजन किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार नवरात्र का धार्मिक महत्व इसलिए भी है कि नवरात्रि के पहले दिन आद्यशक्ति प्रकट हुई थी। देवी के कहने पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ही ब्रह्माजी ने सृष्टि के निर्माण की शुरुआत की थी। इसीलिए चैत्र नवरात्रि को सृष्टि के निर्माण का उत्सव भी कहा जाता है। इसी तिथि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसके बाद भगवान विष्णु का सातवां अवतार भगवान राम का है, वह भी चैत्र नवरात्रि में हुआ था। इसीलिए चैत्र नवरात्र का ज्यादा बड़ा महत्व है।

मकर राशि में शनि, मंगल के साथ विराजित। कुंभ में गुरु, शुक्र के साथ विराजित। मीन में सूर्य, बुध के साथ विराजित। मेष में चंद्रमा, वृषभ में राहु, वृश्चिक में केतु विराजमान रहेंगे। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत व वराह पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर सृष्टि का आरंभ हुआ था। यही कारण है कि देवी पुराण में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार के दिन रेवती नक्षत्र, ऐंद्र योग, बव करण तथा मेष राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व है। किस दिन किस नक्षत्र का संयोग बनने से क्या विशेष योग बन रहा है इस संबंध में ऋषि महर्षि ने अपने मत प्रस्तावित किए हैं। मुहूर्त ग्रंथों में पंचक के नक्षत्र में शुरू होने वाले विशिष्ट व्रत, त्यौहार का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार चैत्र नवरात्र रेवती नक्षत्र में शुरू हो रही है। यह पंचक का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में देवी आराधना की शुरुआत करने से भक्त को पांच गुना अधिक शुभफल प्राप्त होता है।

नवरात्रि संस्कृत के 2 शब्दों नव और रत्रि से बना है, जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सालभर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का अधिक महत्व बताया गया है। चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल में आती हैं और शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर के बीच आती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा-अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई नवरात्रि में इन कामों को करता है तो उसे दरिद्रता के साथ-साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब उन कामों के बारे में भी जान लीजिए, जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से बचना चाहिए।

नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। आपने देखा भी होगा कि कई लोग नवरात्रि शुरू होने के पहले ही नाखून काट लेते हैं, ताकि 9 दिनों में नाखून काटने की जरूरत न पड़े। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती हैं और फिर उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। नवरात्रि के दौरान कटिंग और शेविंग कराने से बचें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की संभावना कम हो जाती हैं। इसलिए 9 दिनों तक बाल और बियर्ड कटवाने से बचें। 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। इन 9 दिनों तक देवी भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान सभी प्रकार के नॉनवेज फूड खाने से बचना चाहिए। प्याज और लहसुन, तामसिक भोजन के रूप में आते हैं। तामसिक का मतलब है कि प्याज-लहसुन मन और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना जाता है कि वे मानसिक थकान का कारण भी बनते हैं। नवरात्रि के दौरान तामसी खाद्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी पवित्र समारोह या त्योहार के दौरान शराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि देवी मां की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि पूजा के 9 दिनों के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।

चमड़े के बेल्ट, जूते, जैकेट, ब्रेसलेट आदि पहनने से बचना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में लेदर से बनी चीजों को पहनने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी से भी अशुभ या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। इसका कारण है कि नवरात्रि देवी की भक्ति और आराधना करने का समय होता है। अगर इस दौरान गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो देवी मां क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए ऐसा करने से बचें।

● ओम

माँ और मॉम

आज कक्षा में उसे मैथिली शरण गुप्त की कविता 'मां कह एक कहानी' का पाठ पढ़ाया गया। आया के संरक्षण में पली उस मासूम को यह कोई परीकथा जैसी लगी। मां की ममता से अनजान वह किसी काल्पनिक पात्र में खो गई।

उसके घर में मां तो नहीं एक मॉम कभी-कभी दिखाई देती हैं। क्योंकि सुबह आया उसे तैयार कर देती है। उसके ड्राइवर अंकल स्कूल छोड़ने जाते हैं और छुट्टी के बाद वापस ले आते हैं। रात में आया ही उसे खाना खिलाकर सुला देती है।

उसे नींद नहीं आती है, तब वह देखती है कि रात ढले क्लबों और किटी पार्टियों में मस्ती कर वही मॉम लड़खड़ाते हुए कदमों से घर लौटती है। वह चाहकर भी पूछ न सकी कि 'राजा था या रानी।' क्योंकि तीन इक्कों के सामने राजा-रानी की जोड़ी नहीं चलती।

डैड के गले में बाहें डालकर अपने कमरे की ओर जाती हुई मॉम को देखकर लगता है कि उनका वात्सल्य कहीं मर गया है। उसका मन वितृष्णा से भर जाता है। अपने नन्हें मन में वह संकल्प लेती है कि वह इन संदर्भों की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी, जिनमें उसका शैशव बीता।

वह कहानियां-लोरियां सुनाने वाली मां बनना चाहती है, मॉम नहीं!

- विनोद प्रसाद

उपाय

मां मना करती रही कि घर में कैक्टस नहीं लगाया जाता। किंतु सुशील बात कब सुनता मां की। न जाने कितने जतन से दुर्लभ प्रजाति के कैक्टस के पौधे लगाए थे। आज अचानक उसे बरामदे में लगे कैक्टस को काटते देख रामलाल बोले, 'अब क्यों काटकर फेंक रहा है? तू तो कहता था कि इन कैक्टस में सुंदर फूल उगते हैं? वो खूबसूरत फूल मैं भी देखना चाहता था।'

'हां बाबूजी, कहता था, पर फूल आने में समय लगता है, परन्तु कांटे साथ-साथ ही रहते। आज नष्ट कर दूंगा इनको!'

'मगर क्यों बेटा?'

'क्योंकि बाबूजी, आपके पोते को इन कैक्टस के कांटों से चोट पहुंची है।'

'ओह, तब तो समाप्त ही कर दो! पर बेटा, इसने अंदर तक जड़ पकड़ ली है! ऊपर से काटने से कोई फायदा नहीं!'

'तो फिर क्या करूं?'

'इसके लिए पूरी की पूरी मिट्टी बदलनी पड़ेगी। और तो और, इन्हें जहां कहीं भी फेंकोगे ये वहीं जड़ें जमा लेंगे।

'मतलब इनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं?'

'है क्यों नहीं..' कहकर कहीं खो से गए।

'बताइए बाबूजी, चुप क्यों हो गए?'

'तू अपनी दस बारह साल पीछे की जिंदगी याद कर!'

मां के मन में उसने न जाने कितनी बार कांटे चुभोए थे। अपनी जवानी के दिनों की बेहूदी हरकतों को यादकर शर्मिंदा हुआ। मां भी तो शायद चाहती थी कि ये कांटे उसके बच्चों को न चुभें।

'मैंने तुझे संस्कार की धूप में तपाया, तू इन्हें सूरज की तेज धूप में तपा दे।' उसकी ओर गर्व से देख पिता मुस्कुराकर बोले।

फिर वह तेजी से कैक्टस की जड़ें खोदने लगा।

- सविता मिश्रा 'अक्षजा'

पितामह तुम सत्य कहते थे

पितामह
तुम सत्य ही कहते थे
धरती किसी के साथ
जाती नहीं है

कहां गए नकुल
कहां गए सहदेव
भीम और अर्जुन कहां हैं
धर्मराज भी रह न सके
एक से बढ़ कर एक
धरती को धारण करने वाले वीर
अवतरित हुए
किंतु कोई धरती को
ले न जा सका

सभी धर्मों
के ईश्वरों ने
या तो अवतार लिया
अपने पुत्र भेजे
या कि पैगंबर
किंतु वे भी दुनिया से
खाली हाथ ही रुखसत हुए
कोई भी धरती को
अपने साथ ले न जा सका

महान अशोक, चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य, पोरस
सिकंदर, अकबर
और राणा प्रताप
भी हुए धरती को बल भर जीता
किंतु वे भी अंगुल भर धरती
साथ ले जा न सके

धरती अपने सभी
पुत्र-पुत्रियों
को आश्रय देती है
झेलती है
उनका पुरुषार्थ और घमंड
किंतु धरती किसी
के साथ जाती नहीं है

वह सबको समाहित कर लेती है
अंततः सोख लेती है
धरती हवा में तैरने देती है
किस्से और कहानियां
किंतु धरती रंच मात्र भी
किसी के साथ जाती नहीं है।

- अभिषेक सिंह, आईएएस

रेल्वे ने जीता औबेदुल्ला खां हेरीटैज कप

4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 21 से 27 मार्च तक औबेदुल्ला खां हेरीटैज कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। प्रतियोगिता की शुरूआत 21 मार्च, 2022 को खेल प्रेमी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। गत दिनों संपन्न हुए औबेदुल्ला खां हेरीटैज कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में इंडियन रेल्वे ने आर्मी इलेवन को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अपरान्ह 2:30 बजे खेले गए हार्ड लाईन मुकाबला आर्मी ग्रीन और इंडियन ऑयल के मध्य खेला गया। बहुत ही रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर रही। खेल पेनॉल्टी शूट आउट तक पहुंचा। शूट आउट में आर्मी ग्रीन ने इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान अर्जित किया। पहली बार वर्ष 1931 में इस टूर्नामेंट की शुरूआत हुई। तब इसका नाम अब्दुल्ला खां गोल्ड कप रखा गया था। यह टूर्नामेंट 2016 में औबेदुल्ला खां हेरीटैज हॉकी कप के नाम से आयोजित किया जाने लगा था।

प्रतियोगिता के अंतर्गत फाइनल मुकाबला आर्मी इलेवन और इंडियन रेल्वे के मध्य खेला गया। इस मुकाबले में इंडियन रेल्वे ने आर्मी इलेवन को 2-1 से परास्त कर फाइनल मुकाबला जीता। इस मैच के पहले क्वार्टर के 12वें मिनट में आर्मी इलेवन के खिलाड़ी हरमान सिंह ने फील्ड गोल कर अपनी टीम का स्कोर 1-0 कर दिया। मैच के दूसरे क्वार्टर के 22वें मिनट में इंडियन रेल्वे के खिलाड़ी जोगिंदर सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर से गोल कर अपनी टीम को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। मैच के तीसरे क्वार्टर में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। मैच के चौथे और अंतिम क्वार्टर के 50वें मिनट में एक बार फिर इंडियन रेलवे के खिलाड़ी जोगिंदर सिंह ने पेनॉल्टी कॉर्नर से गोल कर अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिलाई। शेष समय में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी और इंडियन रेल्वे की टीम ने यह फाइनल मुकाबला 2-1 से जीत लिया।

टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए हार्ड लाईन मुकाबला आर्मी ग्रीन और इंडियन ऑयल के मध्य खेला गया। इस मैच के पहले क्वार्टर के 9वें मिनट में इंडियन ऑयल के खिलाड़ी रघुनाथ वीआर ने पेनॉल्टी कॉर्नर से गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मैच के दूसरे क्वार्टर के 29वें मिनट में इंडियन ऑयल के खिलाड़ी तलविंदर सिंह फील्ड गोल कर अपनी टीम का स्कोर 2-0 कर दिया। मैच के तीसरे क्वार्टर के 33वें मिनट में आर्मी ग्रीन के खिलाड़ी मीनल टोप्पो ने फील्ड गोल कर अपनी टीम का स्कोर 2-1 कर दिया। इसी क्वार्टर के 36वें मिनट में आर्मी ग्रीन के खिलाड़ी जॉनी जसरोतिया ने पेनॉल्टी कॉर्नर से गोल कर अपनी टीम का स्कोर 2-2 से बराबरी पर ला दिया। मैच के चौथे और अंतिम क्वार्टर के 55वें मिनट में इंडियन ऑयल के खिलाड़ी सुनील यादव ने पेनॉल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर अपनी टीम का स्कोर 3-2 कर दिया। इसी क्वार्टर के 58वें मिनट में आर्मी ग्रीन के खिलाड़ी प्रदीप बिष्ट ने फील्ड गोल कर अपनी टीम का स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। अंतिम समय तक दोनों ही टीमें 3-3 से बराबरी पर रही। जीत का निर्णय शूट आउट से हुआ। जिसमें आर्मी ग्रीन ने 3-1 से इंडियन ऑयल को परास्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। जबकि इंडियन ऑयल को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा।

लोकायुक्त मप्र नरेश कुमार गुप्ता और औबेदुल्ला खां के पारिवारिक सदस्य नादिर रशीद ने पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर खेल संचालक रवि कुमार गुप्ता तथा लोकायुक्त एनके गुप्ता की धर्मपत्नि मनीषा गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि खेल मंत्री की पहल पर 4 साल के लंबे अंतराल के बाद औबेदुल्ला खां हेरीटैज कप हॉकी टूर्नामेंट प्रारंभ किया गया था। पचमढ़ी कैबिनेट बैठक के कारण मंत्री उपस्थित नहीं हो सकी थीं। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। टूर्नामेंट में इंडियन ऑयल, भारतीय रेलवे, पंजाब एंड सिंध बैंक, आर्मी एकादश मप्र हॉकी अकादमी, सीएनजी जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज चेन्नई, पंजाब पुलिस, इंडियन नेवी, आर्मी ग्रीन, सेंट्रल सेक्रेटेरियट और मप्र हॉकी एसोसिएशन की टीमों की भागीदारी रही।

● आशीष नेमा

भोपाल फिर बनेगा हॉकी की नर्सरीः मुख्यमंत्री शिवराज

21 मार्च को औबेदुल्ला खां हैरीटेज कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल कभी हॉकी की नर्सरी था, हम पुनः भोपाल को हॉकी की नर्सरी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हॉकी हमारे देश का मान है, भोपाल की शान है और भारत की जनता का सम्मान है। एक समय था जब भारत यदि ओलिंपिक से मेडल लाता था, तो वह हॉकी में ही होता था। हमारे खिलाड़ी उत्साह से परिपूर्ण हैं, यदि उन्हें उचित रूप से संसाधन और श्रेष्ठ कोच उपलब्ध हों, तो भारत एक बार फिर हॉकी का सिरमौर बन सकता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने देगी। संसाधनों, कोचेस और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी। औबेदुल्ला खान कप, 1931 में स्थापित हुआ था। बीच में यह बंद हो गया, कोरोना के कारण भी इसमें व्यवधान हुआ।

जूनियर एनटीआर को देखने पहुंचे 10 लाख फैंस के लिए सरकार ने चलवाई थीं 9 स्पेशल ट्रेन

8 साल की उम्र में किया डेब्यू

तेलुगू सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म आरआरआर में नजर आ रहे हैं। तारक और जूनियर एनटीआर जैसे नामों से पसंद किए जाने वाले वर्सेटाइल एक्टर नंदमुरी तारक रामा राव ने स्टूडेंट नं 1, राखी, सिम्हाद्री, टेंपर, प्रेमाथो, जनता गैराज और बादशाह जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं जिनसे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जूनियर एनटीआर की साउथ में तगड़ी फैन फॉलोविंग है, जिसका फायदा जाहिर तौर पर इस पैन इंडिया फिल्म को मिलेगा।

राजनेता के परिवार से हैं एक्टर

जूनियर एनटीआर उर्फ तारक का जन्म 20 मई 1983 को तेलुगू के पॉपुलर एक्टर नंदामुरी हरिकृष्णा के घर हुआ था। जूनियर एनटीआर के दादा जी एनटी रामा राव आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फॉर्मर तेलुगू एक्टर थे। दादा जी के सुझाव के बाद तारक का नाम बदलकर एनटीआर किया गया था, लेकिन नाम के कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्हें जूनियर एनटीआर बुलाया जाने लगा। ये एक प्रोफेशनल कुचीपुड़ी डांसर भी हैं। साल 2004 में जूनियर एनटीआर आंद्रावाला फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में एक-दो नहीं बल्कि पूरे 10 लाख लोग पहुंचे थे। हैरानी की बात ये थी कि 10 लाख की भीड़ एक जगह इकट्ठा होने के बावजूद न भगदड़ हुई और न ही कोई नुकसान हुआ। जूनियर एनटीआर ने महज 8 साल की उम्र में अपने दादाजी की फिल्म ब्रह्मर्षि विश्वमित्रा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था।

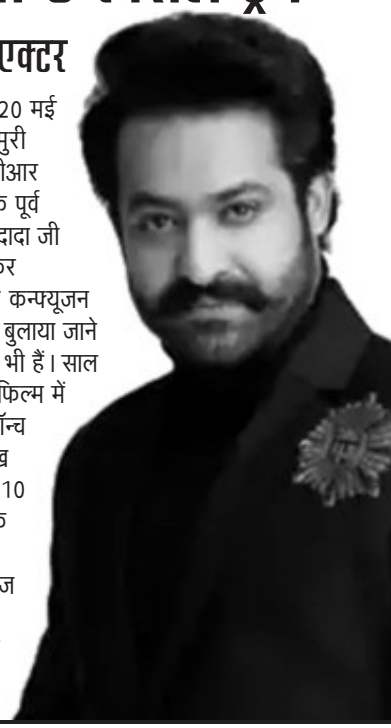

कैसे मिला पहला रोल?

रामायणम फिल्म की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर डायरेक्टर के राघवेंद्र ने एसएस राजामौली को अगली फिल्म स्टूडेंट नं 1 के लिए जूनियर एनटीआर के नाम का सुझाव दिया। इस फिल्म को बनने में सालों लगे और इसी बीच जूनियर एनटीआर ने रामोजी राव की फिल्म निन्नू चूड़ालानी से डेब्यू कर लिया। इस समय एनटीआर सिर्फ 17 साल के थे। डेब्यू के बाद जूनियर एनटीआर स्टूडेंट नं 1 (2001), आदी (2002) सिम्हाद्री (2003), टेंपर (2015) जैसी कई हिट फिल्में कीं। आरआरआर से पहले जूनियर एनटीआर एसएस राजामौली के साथ तीन फिल्में स्टूडेंट नं 1, सिम्हाद्री और यामाडोंगा में काम कर चुके हैं। गौरतलब है कि ब्रह्मर्षि विश्वमित्रा के बाद वो माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम में राम के रोल में दिखे, जिसे बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।

...जब जॉन अब्राहम को शूटिंग के दौरान तालिबान से मिली थी धमकी

एक्टर जॉन अब्राहम ने काबुल एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा शेयर किया है। इसमें उन्होंने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग के दौरान तालिबान से धमकी मिली थी। काबुल एक्सप्रेस 2006 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दो इंडियन और एक अमेरिकन जर्नालिस्ट और एक गाइड की कहानी पर बेस्ड है। इसमें जॉन अब्राहम ने इंडियन जर्नलिस्ट सोहेल खान का किरदार निभाया था। जॉन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। जब मैं अफगानिस्तान से निकल रहा था तो अफगानी लोगों ने मुझसे कहा कि जॉन जान (भाई) आप कुछ भी करो, लेकिन हमारे अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। आज मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि अफगानी लोग दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे प्यारे लोग हैं। वाकई में बहुत प्यारे लोग हैं। जॉन ने काबुल एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान के हादसे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा शूटिंग के समय हम अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह के घर पर रह रहे थे। वो एक यूएन अप्रूव्ड होटल था। मैं चाय पीने के लिए छत पर गया था और सामने से एक रॉकेट आया और अमेरिकी एंबेसी से टकराया।

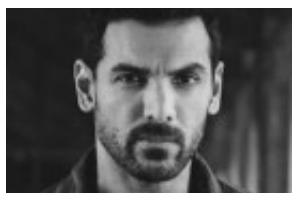

फिल्म राज में असिस्टेंट डायरेक्टर थे इमरान हाशमी, फुटपाथ से बने हीरो

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में हुआ था। इमरान ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म राज से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। इमरान हाशमी 105 करोड़ की सम्पत्ति के मालिक हैं। वह एक फिल्म के लिए लगभग 5-6 करोड़ रुपए लेते हैं। एक्टर एक स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड बैकग्राउंड से हैं। उनके पिता सैयद अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने 1968 में आई फिल्म बहारों की मंजिल में एक्टिंग भी की थी। उनकी मां माहेरा हाशमी एक हाउस वाइफ थीं। इमरान 1940 के दौर की जानी-मानी एक्ट्रेस मेहर बानो मोहम्मद अली के पोते हैं। मेहर को उनके स्क्रीन नेम पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पहली शादी पत्रकार सय्यद शौकत हाशमी से की थी जिसके बाद बेटे अनवर हाशमी का जन्म हुआ। भारत पार्टीशन के बाद शौकत पाकिस्तान चले गए और 1954 में मेहर ने दूसरी शादी प्रोड्यूसर-डायरेक्टर भगवान दास वर्मा से की। भगवान दास ने अनवर को बेटे की तरह अपना लिया। इसके बाद अनवर ने माहेरा हाशमी से शादी की और इमरान हाशमी का जन्म हुआ। उनकी दादी मेहर बानो प्रोड्यूसर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की मां और शिरीन मोहम्मद अली बहनें थी।

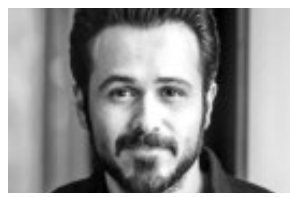

आज की शादियों में मुख्य नायक- नायिका दूल्हा-दुल्हन नहीं; फोटोग्राफर ही हैं। दरवाजे, भांवरों आदि के मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। कौन पूछता है पंडित जी या वर कन्या के घर वालों को! उनके जाने सब भाड़ में जाएं। सबसे मुख्य काम ड्रोन कैमरों, मोबाइल फोनों, अन्य कैमरों से फोटो खींचना और वीडियो बनाना ही शेष रह गया है। ये शादी न होकर एक मजाक की शूटिंग से अधिक कुछ भी दिखाई नहीं देती है। नकली अदाएं और दिखावटी हाव-भाव के बिम्ब-अंकन का यह जीवंत ड्रामा है।

शादी बनाम फोटोग्राफी

अरे! छोड़िए भी 'शादी' कभी 'सादी' हो ही नहीं सकती। 'शादी' के नाम पर कुछ भी प्रदर्शन करने की मनमानी का एक नाम 'शादी' है। यों तो ये 'शादी' शब्द अरबी से फारसी और फारसी से उर्दू की गलियों में घूमते हुए हिंदुस्तानी तथा हिंदी में आया है। 'शाद' शब्द प्रसन्नता, हर्ष, खुशी आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु 'शादी' का रूढ़ प्रयोग 'विवाह' के लिए ही प्रचलन में है।

आज 'शादी' शब्द की चर्चा एक अन्य रंग-रूप में करने की सोच रहा हूं। जिस 'शादी' को जितना सादी कहा जाता है, उसमें सादगी और सादा पन की खुशबू दाल में हींग के छोंक के बराबर भी प्रतीत नहीं होती। कुछ युवतियों के लिए इसके मानी केवल मंहगे लंहगे, चुनरी, ब्लाउज, कीमती गहने और हनीमून से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सादापन की धज्जियां बिखेरना ही इसका मुख्य मन्तव्य उन्हें लगता है। वही बात दूल्हे के लिए भी उतनी ही सत्य है, जितनी किसी दुल्हन के लिए। शादी भी कोई बार-बार थोड़े ही होती है? कठपुतलों की कितनी भी हो जाएं, पर कैमरों की नहीं होतीं। बल्ले-बल्ले तो उन्हीं की है। उनके आगे पंडित जी भी लल्लू ही हैं। अब सारा ज्ञान और विधि-विधान का सरंजाम उन्हीं के लेंस-कमलों में है।

अब शादियां दूल्हा-दुल्हन की नहीं; फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, ड्रोन कैमरों की होती हैं। दूल्हा-दुल्हन तो सूत्रधारों की कठपुतली बने हुए नाचते दिखाई देते हैं। उनकी अंगुलियों के संकेतों के आदेश स्वीकार करते हुए। कभी हाथों में हाथ डाले हुए, कभी दूल्हे की बांहों में दुल्हन को 'यू' या 'एल' के आकार में झुलाते हुए, कभी तिरछी नजरों से दुल्हन द्वारा दूल्हे को प्यार भरी दृष्टि से निहरवाते हुए, कभी दूल्हे की द्वारा गोद में उठाए हुए, प्रेमालिंगन में लिपटे-चिपटे हुए... ऐसी ही विविध रोमांचक मुद्राओं में सार्वजनिक मंचीय प्रदर्शन करते हुए दिखाए जाते हैं। लगता है कि ये शादी नहीं किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। हया और शर्म तो उड़ चुकी है। उड़नछू हो चुकी है। पिता, चाचा, ताऊ, ससुर, सास, सब देख रहे हैं और अपने लाडलों की शूटिंग दृश्य से खिलखिलाकर कर मुंह बाए देख रहे हैं। बेशर्माई की इन्तहां ही हो रही है। बरात तो बारहों रंग की भरी हुई परात है। जिसमें हर रंग के लोग मजे लेने को उतारू हैं। जो काम कभी बंद कक्षों में भी करते हुए भी दुल्हन शरमाती होगी, आज खुलेआम मुम्बइया शूटिंग का आनंद ले ही नहीं रही, आम जनता को लुटा भी रही हैं। बिना पैसे, बिना टिकिट और बिना किसी प्रतिबंध या नियंत्रण की जिंदा फिल्म देखनी हो, तो अत्याधुनिक पीढ़ी की इन 'शादियों' की शूटिंग में देखिए।

आज की शादियों में मुख्य नायक-नायिका दूल्हा-दुल्हन नहीं; फोटोग्राफर ही हैं। दरवाजे, भांवरों आदि के मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। कौन पूछता है पंडित जी या वर कन्या के घर वालों को! उनके जाने सब भाड़ में जाएं। सबसे मुख्य काम ड्रोन कैमरों, मोबाइल फोनों, अन्य कैमरों से फोटो खींचना और वीडियो बनाना ही शेष रह गया है। ये शादी न होकर एक मजाक की शूटिंग से अधिक कुछ भी दिखाई नहीं देती है। नकली अदाएं और दिखावटी हाव-भाव के बिम्ब-अंकन का यह जीवंत ड्रामा है। सारी रात आशीर्वादों का इतना जमघट हो जाता है कि बेचारे कठपुतले संभाल भी नहीं पाते। दादी-बाबा (यदि शेष हों), पिता-माता, चाचा-चाची, भाई-भाभी, ताऊ-ताई, फूफा-बुआ, जीजा-जीजी, इष्ट-मित्रों के ढेरों आशीर्वादों के गट्ठर संभाले नहीं जाते। सौ-सौ के नोटों को नचाते, उड़ाते, घुमाते हुए दृश्य कैमरों की रीलों में रियल लाइफ का मजा देते हैं। इसी कैमरेबाजी का नाम अब शादी रह गया है।

जमाना बहुत आगे चला गया। हर आदमी अपना इतिहास बनाने में लगा है। तो दूल्हा दुल्हन के बहाने यदि कैमरे अपना इतिहास न बनाएं तो आश्चर्य ही क्या है? कुल मिलाकर दूल्हा-दुल्हन तो मात्र कठपुतलियां ही हैं। सारा दारोमदार तो कैमरेबाजी पर टिका हुआ है। वही तथाकथित 'सादी' (शादी) के सर्वेसर्वा हैं। बरात का हर आदमी-औरत अपनी गर्दन ऊंची करके, घूंघट अथवा मास्क हटाकर फोटो खिंचवा रहा है। क्रीम इस प्रकार लगाई गई है कि जैसे उसकी खुशबू फोटो में भी रच-बस जाएगी।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687